हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

शोकोद्गार

11-03-2025/1100/ns-as/1

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं कार्यवाही शुरू करूं, आज माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी का जन्मदिन है और मैं उनको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा के तृतीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदन के नेता श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी, माननीय उप-मुख्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, मंत्रिमण्डल के समस्त सदस्यगण व मेरे सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष एवं समस्त माननीय सदस्यों का सत्र में एकत्रित होने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि 16 दिन चलने वाले बजट सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले।

सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरी यह उम्मीद भी रहेगी कि इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मुझे आप सभी का भरपूर सहयोग मिलता रहे।

अब माननीय मुख्य मंत्री स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री व श्री किशन कपूर, पूर्व सदस्य एवं मंत्री व सांसद, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार प्रस्तुत करेंगे।

11-03-2025/1100/ns-as/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि पूर्व प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी का दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी का जन्म दिनांक 26 सितम्बर, 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाहर नामक गांव वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आ कर बस गया। डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर (एम0ए0) की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 1957 में केंद्रीय विश्वविद्यालय

चले गए तथा अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ Economics Tripos पूरा किया। उन्होंने वर्ष 1962 में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में D.Phil की उपाधि हासिल की। डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने पंजाब विश्वविद्यालय Delhi School of Economics में अर्थशास्त्र के प्रोफैसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने कुछ वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय के लिए भी कार्य किया। इसी के आधार पर उन्हें वर्ष 1987 व वर्ष 1990 में जेनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

आर0के0एस0 द्वारा----- जारी

11.03.2025/1105/RKS/As-1

शोकोद्गार... जारी

मुख्य मंत्री... जारी

स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवा शुरू की और फिर वर्ष 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, और भारतीय प्रोद्योगिकी विकास बैंक के निदेशक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी को वर्ष 1991 में भारतीय संसद के उच्च सदन, राज्य सभा के लिए चुना गया। वह वर्ष 1991 से 1996 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार में देश के वित्त मंत्री रहे जहां उन्होंने आर्थिक संकट से उबारने और आर्थिक सुधारों को मजबूती देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वह वर्ष 1998 से 2004 तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता रहे। वर्ष 2004 में आम चुनावों के बाद स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह जी ने 22 मई, 2004 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 22 मई 2009 को दूसरी बार देश के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। वह वर्ष 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान कई क्रांतिकारी फैसले लिए। उनके नेतृत्व में सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम,

मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरुआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और 72 लाख किसानों के ऐतिहासिक ऋण माफी योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। डॉ0 मनमोहन सिंह की दूरदृष्टि और सहयोग की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुईं जिनमें अटल टनल, तीन चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक में ई.एस.आई. अस्पताल, आई.आई.टी. मंडी, आई.आई.टी. ऊना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं। स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनके देश और विदेश के लिए दी गई सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें वर्ष 1987 में पद्मविभूषण, वर्ष 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, वर्ष 1993 और वर्ष 1994 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशियामनी अवार्ड और यूरोमनी अवार्ड, 1956 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा ऐडम स्मिथ पुरस्कार, और 1955 में सेंट जॉन्स कॉलेज द्वारा राइट पुरस्कार प्राप्त हुआ।

11.03.2025/1105/RKS/As-2

इसके अलावा, कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों से भी उन्हें मानद उपाधियां प्रदान की गईं। स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी की लेखन और समाज सेवा में गहरी रुचि थी। यह माननीय सदन उनकी देश, प्रदेश और समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है और उनके निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना और उनके परिवार को इस कठिन समय में सहनशक्ति देने की कामना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 1993 में देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो उस समय कांग्रेस सरकार का शासन नहीं था। उस समय पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री चन्द्रशेखर जी का शासन था। उस समय देश का सोना गिरवी रखा गया था और देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि देश आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा था। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के देहांत के बाद जब स्वर्गीय श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव जी को प्रधान मंत्री के पद पर नवाजा गया तो उस समय डॉ0 मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी गई। डॉ0 मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीतियों में बदलाव कर गिरवी रखे गए सोने को वापस लाकर देश की स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभाई। यह सच्ची देशभक्ति का उदाहरण

था। लोगों की सेवा करना, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना, और राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना उनकी विशिष्ट पहचान थी।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

11.03.2025/1110/बी.एस./डी.सी./-1

सोकोद्गार जारी...

मुख्य मंत्री जारी...

स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए एक सोच विकसित की और आज मनरेगा के तहत जो बजट उन्होंने एलोकेट किया, उस बजट के माध्यम से आज गांव में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जब दो साल तक कोरोना रहा उस समय मनरेगा को याद किया गया। उस वक्त घर के दरवाजे पर रोजगार देने के लिए जो अवसर थे वे भी मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए। डॉ0 मनमोहन सिंह जी शिक्षाविद् थे और उन्होंने एक नई सोच के साथ संस्थानों को खोलना आरंभ किया। शुरू में उन्होंने एक्म, आई0आई0टी0 और नाइपर खोले और जो उनके टैक्नॉलोजी बेस्ड संस्थान थे जिसका अभाव इस प्रदेश में था, उन्होंने उसकी शुरूआत की। उन्होंने पहले सात और बाद में पांच अन्य एम्स खोले। इस प्रकार से 12 एक्स उनके समय में खोले गए। आदरणीय चन्द्र कुमार चौधरी जी उस वक्त सांसद थे, इसलिए इन्हें अच्छे से ये सारी बातें याद हैं। उसके बाद पूरे प्रदेश में जो हायर एजुकेशन और सर्च का काम था उस सोच को भी उन्होंने विकसित किया। जो शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले अध्यापक, लेक्चर्र और यूनिवर्सिटीज में प्रोफैसर्ज थे उनके लिए उन्होंने पाया कि जो शिक्षक आगे बच्चों को ज्ञान देता हैं उसकी सैलरी बहुत कम है। उन्होंने यू0जी0सी0 के नियमों में भी परिवर्तन किया और उन्हें हाइली पेड सैलरी का तोहफा उन शिक्षकों और कर्मचारियों को दिया। उनके द्वारा लाई गई सैलरी का पैकेज आज पूरे देश में बहुत अच्छा है। पहले शिक्षकों की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। एक सोच और एक परिवर्तन की

लहर अगर कोई नेतृत्व ले करके आया वह आदरणीय मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व ले करके आया। हमारी सरकार ने भी उनके देहांत के बाद जहां से हमारे प्रशासनिक अधिकारी ट्रेनिंग ले करके निकलते हैं और आने वाले कई वर्षों तक इस प्रदेश की सेवा करते हैं, जो भी वहां पर परीक्षा पास करके आते हैं और समाज के वर्गों की सेवा करते हैं।

हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान का नाम स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख दिया है। अब इस संस्थान को डॉ0 मनमोहन सिंह हिमाचल लोग प्रशासनिक संस्थान के नाम से

जाना जाएगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और इसके बोर्ड इत्यादि भी वहां पर लगवा दिए हैं। आदरणीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने जो इस देश को दिया और खास करके जो हिमाचल प्रदेश को दिया, मुझे याद है वर्ष 2008-09 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रोफैसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे, उस समय रिज पर एक बड़ी रैली का अयोजन किया गया और आदरणीय पी0 चिदम्बरम जी उस रैली में आए और उन्होंने दो संस्थानों, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और आई0आई0टी0 मण्डी के लिए घोषणा की थी और उनके लिए बजट का भी प्रावधान किया। इन दोनों सस्थानों की घोषणा आरणीय पी0 चिदम्बरम जी ने रिज मैदान पर की थी। एक बार जब में प्रदेश अध्यक्ष था, उस वक्त पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे। हम सब उनके पास गए और उसमें हमारा मंत्रीमण्डल भी था। हमने उस समय उनसे अनुरोध किया। मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते साथ गया था और हमने आग्रह किया कि आप हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा कि आप जो भी योजनाएं लाएंगे हम उनमें आपकी आर्थिक सहायता करेंगे और हमारे को उन्होंने उस वक्त हमें(JNNURM) जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत पैसा उपलब्ध करवाया था। वे हमेशा प्रदेश की मदद करते रहते थे। अटल टनल जिसका नाम रखा गया, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके समय यह स्टोन रखा गया और बी0आर0ओ0 की मदद से उनके समय यह आधारशीला रखी गई। बी0आर0ओ0 की मदद से उसके लिए 1800 करोड़ रुपया उस समय के हिसाब से रखा गया था और काम भी शुरू हो गया। यह

ठीक है कि वर्ष 2014 में हम हार गए और सत्ता में आई सरकार ने उस टनल का नाम बदल कर रख दिया।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

11.03.2025/1115/DT/DC-1

शोकोद्गार जारी...

मुख्य मंत्री जारी....

और बी.आर.ओ. की मदद से उसमें 1800 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से बजट का प्रावधान किया गया और काम शुरू हो गया; ठीक है वर्ष 2014 में केंद्र में कांग्रेस हार गई। केंद्र में सक्सेसिव गवर्मन्ट आई उस सरकार ने उसका नाम बदल दिया। लेकिन उसकी स्वीकृति भी स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी के द्वारा हुई और उसका शिलान्यास भी श्रीमती सानिया गांधी जी के द्वारा किया गया। वह फाउंडेशन हमने दूसरी जगह रखा है। यह भी स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी की हिमाचल प्रदेश को देन है।

नाहन का IIM भी स्वर्गीय डॉ. मनमहोन सिंह जी की देन है। IIIT वह भी भी स्वर्गीय डॉ. मनमहोन सिंह जी की देन है। क्योंकि वह शिक्षाविद् थे और 75 लाख जनसंख्या वाले इस छोटे से राज्य में इस प्रकार के संस्थान अगर कोई देकर गया है तो वे हैं स्वर्गीय डॉ. मनमहोन सिंह जी और निश्चिततौर पर उसका लाभ हिमाचल की जनता को होगा और उससे भी अधिक लाभ हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी होगा। इसलिए हमारी स्वर्गीय डॉ. मनमहोन सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उन्होंने जो संस्थान दिए है, उन सस्थानों से जो प्रदेश के या अन्य राज्यों के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनकी सोच भी पारदर्शी, ईमानदार और नैतिक मूल्यों वाली होनी चाहिए जैसी सोच स्वर्गीय डॉ. मनमहोन सिंह जी की थी और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है की पूर्व मंत्री श्री किशन कपूर जी का 1 फरवरी, 2025 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी का जन्म

11 जून, 1951 को जिला कांगड़ा के गांव खनियारा में हुआ। उन्होंने डिग्री कॉलेज धर्मशाला से शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी वर्ष 1990 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह वर्ष 1993, वर्ष 1998, वर्ष 2007 और वर्ष 2017 में पुनः विधायक चुने गए। वह राज्य सरकार में मार्च 1998 से 1 मार्च, 2001 व 3 अप्रैल, 2001 से दिसम्बर 2003 तक

11.03.2025/1115/DT/DC-2

परिवहन एव जनजातीय विकास मंत्री रहे। वह 9 जनवरी, 2008 से दिसम्बर 2012 तक परिवहन व उद्योग मंत्री रहे। इसके अलावा वह प्रदेश सरकार में 27 दिसम्बर, 2017 से 5 जुलाई, 2019 तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री भी रहे। स्वर्गीय किशन कपूर जी वर्ष 2019 में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के लिए सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। उनकी समाज सेवा में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय किशन कपूर जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किशन कपूर जी से हमारी कई बार मुलाकात भी होती थी। वह बड़े स्पष्टवादी थे। जब उन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़ा तो देश भर में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से वह चुनाव जीते। जब वह चुनाव जीते तो मैंने फोन पर उन्हें मुबारकबाद दी। मैंने उन्हें कहा कि अब आप केंद्र में मंत्री बनेंगे क्योंकि आप सबसे अधिक वोटों से जीते हैं, आप मंत्री बनकर हिमाचल प्रदेश की सेवा करेंगे। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा कि जो धर्मशाला का एयरपोर्ट है इसका एक्सपेंशन करना है, मैं इसके लिए पैसा भारत सरकार से स्वीकृत करवाऊंगा; उस समय मैं मुख्य मंत्री नहीं था-लेकिन मुझे उनकी बात याद है। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात संसद में भी उठाई और इसके लिए

उन्होंने प्रयास भी किए। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्होंने प्रयास नहीं किए-उन्होंने प्रयास किए और केंद्र सरकार से भी इस विषय को उठाया । स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी हर बात को बड़ी सटीकता और स्पष्टता से कहते थे। उनकी बात में कोई छल-कपट नहीं होता था। हमनें उनकी कार्यप्रणाली को भी देखा - अगर हम उन्हें कोई भी जनहित के संबंध में पत्र देते थे तो वह अपने कार्यालय को उस पर तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश देते थे। जब उनका देहांत हुआ तो

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

11.03.2025/1120/एच.के.-एन.जी./1

शोकोद्गार .....जारी

मुख्य मंत्री.....जारी

हमारी सरकार ने राजनीति की बेड़ियों को न अपनाते हुए एक व्यक्तित्व को राजकीय सम्मान दिया है क्योंकि उनके व्यक्तित्व ने इस प्रदेश की सेवा की है। ऐसा व्यक्ति जो स्पष्टता से प्रदेश की सेवा करता हो उसके लिए हमें राजनीति से ऊपर उठ कर कार्य करना होगा। हमने उन्हें उनकी अंतिम यात्रा में अपनी सरकार की ओर से राजकीय सम्मान दिया और यह इसलिए दिया क्योंकि उनका समाज तथा धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो योगदान था, उसके लिए हमारा फर्ज़ बनता है कि हम भी अपनी सरकार की ओर से कुछ योगदान कर सकें। इसलिए हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री चन्द्र कुमार जी और माननीय उप-मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया जी ने उन्हें सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

मैं आप सभी के समक्ष यही कहना चाहता हूं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2025/1120/एच.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष : इसमें और भी माननीय सदस्य बोल सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने शोकोद्गार प्रस्तुत करें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोकोद्गार प्रस्तुत किए हैं मैं भी उसमें अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी को मालूम है कि डॉ0 मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितम्बर, 1932 को हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तब भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। उन्होंने बहुत लम्बे राजनीतिक जीवन के पश्चात अपने प्राण त्यागे हैं। उन्होंने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही काम नहीं किया है बल्कि समाज के बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य किया है। उनके कार्यक्षेत्रों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनके योगदान को स्मरण करते हुए मैं उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन में करिअर की शुरुआत एक प्रध्यापक के रूप में की थी। मैं डीटेल में न जाकर सिर्फ यही कहुंगा कि उन्होंने भारत सरकार के कईं अहम पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। उन्होंने आर0बी0आई0 के अध्यक्ष (गवर्नर) के रूप में और वर्ष 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। आज तक जितने भी प्रधान मंत्री रहे हैं और जिनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार की रही हो, वह बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर प्रधान मंत्री किसी दल के नेतृत्व का एक चेहरा होता है। लेकिन स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने जिस सहजता व सरलता के साथ बतौर प्रधान मंत्री काम किया है, यह अलग परिस्थिति है कि उन्होंने एक राजनीतिक दल के चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयत्न भी नहीं किया। उन्होंने एक प्रशासक के रूप में, एक एक्मेडिशन के रूप में और एक विज़न के साथ काम करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी छवि को स्थापित किया था और निश्चित रूप से वे इसमें सफल भी हुए। जब केन्द्र में सरकार बनाने का विषय आया तो लोग कुछ और चाहते थे लेकिन उसके बावजूद उनके नाम का प्रस्ताव आगे आया तथा वे देश के प्रधान मंत्री बन गए। उससे पहले भी मैं इस बात को देख रहा हूं कि

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

11.03.2025/1125/पी0बी0/एच0के0/-1

शोकोद्गार जारी...

श्री जय राम ठाकुर जारी...

उससे पहले वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे तथा राज्यसभा में वर्ष 1998 से वर्ष 2004 तक विपक्ष के नेता रहे। इस बीच उनको दिल्ली से चुनाव भी लड़ाया गया था लेकिन वह चुनाव नहीं जीत पाए थे। उनका कार्य करने का तरीका चाहे वह संगठन में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, बहुत ही सहज एवं सरल था। वर्ष 2004 में आम चुनाव में उन्होंने देश के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद दिनांक 22 मई, 2009 को भी दूसरी बार देश के प्रधान मंत्री बने। वह 10 वर्ष तक देश के प्रधान मंत्री रहे। उन्हें वर्ष 1987 में उन्हें पद्म विभूषण मिला व 1957 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला। उन्हें 1953-1954 में वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला, वर्ष 1993 में देश के वित्त मंत्री के रूप मे यूरो मनी अवार्ड मिला। उन्हें 1956 में केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और डाक्टर मनमोहन सिंह जी को केम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा मानक उपाधि भी प्रदान की गई। पूरे देश भर के लिए उनका एक योगदान रहा है। यहां हिमाचल के संदर्भ में जहां हिमाचल के लिए भी इन्स्टीच्यूशन्ज का जिक्र कर रहे थे ठीक है और बतौर प्रधान मंत्री उनकी मंशा इस बात को लेकर थी कि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें योगदान करना चाहिए उस दृष्टि से उन्होंने अपना सहयोग किया और जितने इन्स्टीच्यूशन्ज का यहां पर जिक्र किया गया उनमें से कुछ इन्स्टीच्यूशन्ज की शुरुआत चाहे घोषणा के रूप में हुई या बाद में उनको ज़मीनी हकीकत में लाया गया तो उसके लिए हम उनके योगदान को स्मरण करते हैं। मैं समझता हूं कि डॉ0 मनमोहन सिंह जी के निधन की क्षति को एक राजनैतिक दल, परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैंने इस बात को भी देखा है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी उनके प्रति बहुत

सम्मान और आदर का भाव रखते थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधान मंत्री रहे और उनपर बहुत कम टिप्पणियां होती थी। ऐसे प्रधान मंत्री के रूप में

11.03.2025/1125/पी0बी0/एच0के0/-2

उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया जहां विपक्ष के प्रहार का उनको बहुत ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि सहजता-सरलता उनके जीवन का हिस्सा थी और वही उनकी बहुत बड़ी ढाल थी। सबसे बड़ी बात जिसे मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उस कार्यकाल में नीचे क्या हुआ वह बात अलग है लेकिन उसके बावजूद प्रधान मंत्री रहते हुए डॉ0 मनमोहन सिंह जी की छवि बहुत साफ-सुथरी रही इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं उनके इस दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उनके योगदान को हम सब लोग स्मरण करते हैं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस माननीय सदन में यह शोकोद्गार के माध्यम से यह प्रस्ताव उनके परिवार तक अवश्य पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी, जिनका दिनांक जन्म 25 जून, 1951 को हुआ था और वे एक जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते थे, गद्दी समुदाय से थे। वे इस माननीय सदन के पांच बार सदस्य रहे, तीन बार मंत्री रहे, दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रहे।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

11.03.2025/1130/A.P./Y.K./01

श्री जयराम ठाकुर द्वारा जारी.....

मैं उनके दुःखद निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दें। मैं उनके योगदान को स्मरण करता हूं। मैं यह भी जरूर चाहूंगा कि इस माननीय सदन में शोकोद्गार के माध्यम से हम सभी की भावनाएं उनके परिवार तक अवश्य पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, श्री किशन कपूर जी का जन्म 25 जून, 1951 को हुआ था। वह एक ट्राइबल व गद्दी समुदाय से संबंध रखते थे। वे पांच बार इस सदन के सदस्य रहे जिसमें से तीन बार मंत्री रहे। मुझ से पूर्व में दो बार जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तब वे दोनों बार हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और जब मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्य मंत्री बना तब वे मेरी सरकार में भी मंत्रिमण्डल में मेरे साथ थे। मैं इस बात को कह सकता हूं कि उनकी छवि एक ईमानदार व स्पष्टवादी नेता के रूप में रही। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वे मेरे साथ मंत्रिमण्डल में थे और वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव आया तब वे मेरे साथ महत्वपूर्ण मंत्रालय में काम कर रहे थे। हमारी पार्टी को एक फैसला लेना था कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव कौन लड़ेगा?

आदरणीय श्री शांता कुमार जी उस समय के सांसद थे लेकिन पार्टी ने एक फैसला किया कि 75 वर्ष की आयु के ऊपर जो नेता पूरे देश भर में है लोकसभा के चुनाव में अबकी बार वे चुनाव न लड़े। हमारी बैठक चल रही थी और आदरणीय प्रधानमंत्री व गृह मंत्री जी ने मुझे इस बात के लिए आदेश दिया कि आप श्री शांता कुमार जी के पास जाएं और पार्टी का आग्रह पहुंचाएं और उन्हें इस बात के लिए तैयार करें क्योंकि बहुत अधिक दबाव था कि शांता कुमार जी चुनाव लड़े। यहां तक कि शांता कुमार जी चुनाव लड़ना भी चाहते थें। लेकिन पार्टी ने यह व्यवस्था दी किवे चुनाव नहीं लड़ेगे और उसके साथ-साथ उनसे पूछा जाए कि उनके स्थान पर किसे चुनाव लड़ाया जाए। तो यह बहुत कठिन विषय था हमारे सामने इसके बावजूद मैं शांता कुमार जी के पास गया। मैंने पार्टी का पक्ष उनके समक्ष रखा और मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि शांता कुमार जी ने तुरन्त सहज रूप से इस बात को स्वीकार किया और कहा जीवन भर मैं पार्टी का काम करता रहा। मैं पंचायत के चुनाव से लेकर के लोकसभा, राज्य सभा तक के सभी चुनाव मैंने लड़ लिए

11.03.2025/1130/A.P./Y.K./01

और ऐसे में पार्टी का यह नीतिगत फैसला है इसे मैं स्वीकार करता हूं। इसके बाद अगला प्रश्न यही था कि चुनाव कौन लड़ेगा और चुनाव लड़ने के लिए शांता कुमार जी की उपलब्धता हमारे लिए आवश्यक थी, उनका सुझाव महत्वपूर्ण था। उन्होंने दो नामों का जिक्र किया और उन नामों के जिक्र करने के साथ फिर हमें लगा कि किशन कपूर जी को चुनाव लड़ाना चाहिए और रात को करीब डेढ़ बजे के समय पर मैंने किशन कपूर जी को फोन किया। पहले तो फोन उठा नहीं पाए, जब दूसरी बार फोन किया तो हमने उनसे इस बात के बारे पूछा और अचानक इस बात को लेकर उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा नहीं मैं यहां पर ठीक हूं मैं अच्छी तरह से पार्टी के साथ काम कर रहा हूं। हमने कहा इस पर पार्टी विचार कर रही है यह मेरा विषय नहीं है और उन्होंने कहा मैं सोच-विचार कर के बताता हूं। थोड़ी देर बाद उनका जब फोन आया और कहा कि अगर पार्टी का यही फैसला है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। इच्छा न होने के बावजूद पार्टी का फैसला सर्वोपरि है मैं इसे स्वीकार करता हूं और फिर अध्यक्ष महोदय उनको चुनाव लड़ाया गया और पूरे देश में वोट शेयर के हिसाब से वह सबसे ज्यादा वोटों से जीते लगभग 4,80,000 वोटों से चुनाव जीते, 72 प्रतिशत उनका वोट शेयर रहा और सबसे बड़े अंतर से वह देश भर में जीते।

ए0टी0 द्वारा जारी.....

11.03.2025/1135/AT/YK/1

श्री जय राम ठाकुर द्वारा जारी ....

उसके बाद एक सांसद के नाते हमने काम किया, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की । इस बात को लेकर उन्होंने हमसे भी बात की और वर्तमान मुख्यमंत्री जी से बात की थी कि जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है इसका एक्सपेंशन होना चाहिए । लेकिन एक प्रक्रिया के माध्यम से

हमने कहा कि चीजों को आगे बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं। हमने किया भी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वह एक ट्राइबल के नेता होने के बावजूद भी बात को स्पष्ट कहने की स्थिति में रहते थे और इस बात के लिए वे जाने जाते थे। चाहे वह कैबिनेट की बैठक होती थी या फिर किसी विषय पर एजेंडा होता था, उनका मत बहुत सारे विषयों को ले कर के स्पष्ट होता था। उनकी यह एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। अपने लंबे जीवन के करियर में उन्होंने जो योगदान दिया उसको पूरा प्रदेश याद करता है। पिछले दिनों अध्यक्ष महोदय, वे अस्वस्थ चल रहे थे और उनका मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तब मुझे मालूम हुआ कि वे बीमार हैं और तब वह सांसद थे और चुनाव नहीं था तो मैं उनको मिलने के लिए गया था। तब मैंने देखा कि उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। उनका थोड़ा किडनी, लंगज़ का कोई इशू था। सर्जरी की प्रक्रिया से वे गुजरे थे लेकिन उसके बाद रिकवर कर गये थे लेकिन बीच में स्वास्थ्य में फिर से गिरावट आई और मैं चंडीगढ़ में पी0जी0आई0 किसी सिलसिले में गया था वहां मुझे मालूम पड़ा कि किशन कपूर जी अस्पताल में पी0जी0आई0 में एडमिट हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए पहुंचा। उस समय वे ठीक बात कर रहे थे और कहा कि मुझे दो दिन बाद छुट्टी होने वाली है लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ऐसा लगता है कि अब वह सारी सिचुएशन रिवर्स होगी ऐसी बहुत ज्यादा संभावना नहीं लग रही है स्वाभाविक रूप से हमको भी इस बात को लेकर चिंता हुई लेकिन एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर भी गये लेकिन घर में फिर से उनकी तबीयत खराब होने के बाद दोबारा एडमिट किया गया और ब्रेन हैमरेज इस कद्र हुआ कि उसके बाद वे कोमा में ही चले गए और उसके बाद कोमा से बाहर नहीं निकल पाए। एक साथी के नाते हमारे लिए यह सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय है कि छोटी आयु में एक साथी हमने खोया जिन के साथ हमने वर्षों से काम किया और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। एक ट्राइबल नेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में मैं उनके दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

11.03.2025/1135/AT/YK/2

ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अपने बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

Speaker : I will request the rest of the Hon'ble Members to be very brief please.

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय ,आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक प्रस्ताव पर अपने उदगार प्रकट किये। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह यू0पी0ए0 फर्स्ट की जो सरकार बनी उसमें प्रधानमंत्री रहे हैं और चौदहवीं लोकसभा में मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला और उस वक्त यू0पी0ए0 फर्स्ट की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और उस वक्त सभी कहते थे कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी होनी चाहिए।

श्रीमती एम0 डी0 द्वारा जारी .....

11-3-2025/1140/MD/AG/1

कृषि मंत्री---- जारी

लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने हमारी उस वक्त पार्लिमेंट की मीटिंग हुई दोनों हाउसिस की और उसने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज यह कहती है कि मैं हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती मैं डा.मनमोहन जी को हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री देखना चाहती हूं और उस वक्त डा. मनमोहन जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। डा. मनमोहन सिंह एक बहुत ही विजनरी, ऐडुकेशनिस्ट और अच्छे ऐडमिनस्ट्रेटर रहे और उन्होंने 1952 में पंजाब युनिवर्सिटी से इक्नोमिकस की और फर्स्ट क्लास ओनर्स की डिग्री प्राप्त की और उसी यूनिवर्सिटी में 1960 में लिडर्स के पोस्ट के हउपर इकोनोमिक्स के प्रोफेसर रहे और मुझे भी उस यूनिवर्सिटि में पढ़ने कर मौका मिला क्योंकि में जियोग्राफी का स्टुडेंट था और वहां पर डा. गुरदीप सिंह कौशल हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और दोनों काफी पढ़े लिखे थे उसने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से पी.एच डी. की थी और इन्होंने

ऑक्सफोर्ड यूनिवसर्सिटी से पी.एच.डी की थी और उनका बडा लंबा अकादमिक एक्सपीरियंस रहा है विभिन्न पदों के उपर उन्होंने काम किए। वह एडवाइजर भी रहे और जिस विकट स्थिति में उनको नरसिम्हा राव की सरकार में वित मंत्री के रुप में काम करने का मौका मिला तो उस वक्त उन्होंने देश की इक्नोमी को संभाला और उन्होंने कहा कि जितने भी प्रवासी भारती जो विदेशों में रहते हैं ।उनको सभी को निमंत्रण दिया कि आप अपना पूंजी जो हैं वो हिन्दुस्तान के बैंकों में जमा करवाएं क्योंकि उस वक्त हिन्दुस्तान का जो हमारा आर्थिक संकट था और हमारे पास सिर्फ दो-तीन महीने का विदेशी मुद्रा का भंडार था और हमें बहुत सी चीजें जो थी विदेशियों से लेनी पड़ती थी और उस वक्त उन्होंने कहा कि जो भी प्रवासी भारती अपना पैसा हिन्दुस्तान के बैंकों में जमा करवाएगा तो में उसके उपर कोई टेक्स नहीं लगाउंगा और उस वक्त हमारे बैंक जो थे वो विदेशी मुद्रा के भंडार से भरे और उन्होंने जो हमारी आर्थिक स्थिति जो थी उसको उन्होंने उभारा और उस वक्त हमारी लिब्रलिजेशन उसको किया। आज जो बडी-बडी सडकें और एयरपोर्ट मिलते हैं वो सारी उनकी देन है और वह

11-3-2025/1140/MD/AG/

बडे प्रेक्टिकल राजनितिक थे उस वक्त 2004 में उन्होंने चार पांच का लोन बनाया खाने का अधिकार, स्वास्थय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और रोजगार का अधिकार जिसमें मनरेगा का काम शुरु किया पांच बडे-बडे पार्लिमेंट में वो कानून पास करके लोगों को बडी राहत पहुंचाने की कोशिश की और जहां जब अमेरिका के साथ नयूक्लर डील थी तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग जो थे उनकी कुछ रिजरवेशन थी कि यह डील नहीं होनी चाहिए जो ओपोजिशन पार्टीस थी वो भी इस डील को करने के तैयार नहीं थी और उस वक्त हमारे स्पीकर सोमनाथ जी थे और उस न्यूकिलर डील को उन्होंने कहा कि नहीं में उस डील को जरुर करुंगा और उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो थी वह उसके विरुद थी तो उस वक्त सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि में अपना वोट नयूक्लर डील के पक्ष में करुंगा और उस वक्त प्रकाश खरार जो थे वो राज्यसभा के मेंम्बर थे और उन्होंने अपने ब्यूरो से उस वक्त स्पीकर को निकाल दिया और उन हालात में जो है वो उन्होंने

न्यूक्लीयर डील जो थी वो सभी पक्ष-विपक्ष के लोंगों को सहमति के साथ जो है वो नयूकलर डील पास करने में डा.मनमोहन जी कामयाब रहे।

श्रीमती के0एस0 जारी -----

11.03.2025/1145/केएस/एजी/1

कृषि मंत्री जारी---

जहां राजीव गांधी फाउंडेशन की मीटिंग थी, वहां पर सभी लोग आए हुए थे और डॉ0 मनमोहन सिंह जी भी आए हुए थे। राजा वीरभद्र सिंह जी ने उनके यहां से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा था। वीरभद्र सिंह जी ने उनको कहा कि हमने आपके लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा है, आप बाई एयर चलिए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि my country is not so rich that I should fly every day in the air. मेरे पास गाड़ी का टिकट है, मैं शाम को गाड़ी में जाऊंगा। वे इतने हम्बल थे। कई बार उन्होंने कहा कि ये बड़े-बड़े इश्तहार जो प्रैस मीडिया में जाते हैं, इनके ऊपर मेरा फोटो नहीं लगना चाहिए। उनका फोटो एक छोटे से लोगो के रूप में लगाया जाता था। वे कहते थे कि यह देश का धन है और इसमें हमारे गरीब लोगों का पैसा है। बड़े-बड़े इश्तहार/पोस्टर लगाकर उससे वाहवाही लूटने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं। वे बड़े प्रैक्टिकल थे। मुझे एक वाकया याद है कि जब मंत्रिमण्डल बना तो दो-तीन दिन के बाद मैं और आदरणीय कर्नल धनीराम शांडिल जी, हम दोनों उनको मिलने के लिए गए। वे अपनी कुर्सी से उठे और सामने एक सोफा रखा था उसके बीच में बैठ गए। एक तरफ मैं बैठा और दूसरी तरफ शांडिल साहब बैठे। वे मुझे कहने लगे कि Professor Chander Kumarji, I recommended your case for the Council of Ministers, but your Party people has so ideal pace. मैंने कहा कि I am very proud of you that when you were Professor (Economics), Punjab University, I was the student of Geography Department. Oh yes, Gurdev Singh was the Head of the Department. Yes, Sir. Such was a humble soul. He was breaking all these things to me. हम दोनों को कहने लगे कि कोई काम हो तो आप हमें जरूर मिलिए। उस वक्त क्योंकि मैं सांसद था तो मैं टांडा मैडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 125 करोड़ रुपया ले कर आया। आज जो वह हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, उसमें 25 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमैंट के थे और 125 करोड़ रुपये उस वक्त डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने दिए थे। आज वह कितना बढ़िया हॉस्पिटल बना है। उस वक्त 12 ऑल इंडिया

मैडिकल इंस्टिट्यूट्स खोले गए थे जिनमें से एक हमें भी मिला। उन्होंने हमें सैंट्रल यूनिवर्सिटी दी। आई0आई0टी0 मण्डी दिया, आई0आई0एम0, पांवटा साहिब दिया। उनकी सोच थी कि हिन्दुस्तान के ढांचे को भी हम मॉडर्नाइज़ करें और आपको पता होगा कि उन्होंने उस वक्त नॉलेज कमिशन बनाया। वे चाहते थे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के बराबर हों और उस वक्त सैम पित्रोदा को नॉलेज कमिशन का चेयर पर्सन

11.03.2025/1145/केएस/एजी/2

बनाया। जब भी हम उनसे मिलते थे वे बड़े प्यार और विनम्रता से मिलते थे। छोटे से छोटे आदमी से मिलने से भी वे परहेज नहीं करते थे। एक बार अमेरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका इंटरनेशनल फेम था और वे सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट रहे। उन्होंने इस देश को एक अच्छी दिशा और दशा दी। यू0पी0ए0 फर्स्ट और यू0पी0ए0 सैकण्ड में वे प्रधान मंत्री रहे। उनकी सोच हमेशा इस देश को आगे ले जाने की थी। उस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं होता था। उन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज़ किया। आज हमें खुशी है कि आज हर घर में कार खड़ी है। आज हमारा गांव का सिस्टम बदला है। जब इकोनॉमी खुलती है तो उसमें हमारे कॉर्पोरेट सैक्टर के बड़े-बड़े लोग आते हैं। उस वक्त टाटा, बिरला आदि सभी उनको मिलने गए कि आपने इकोनॉमी को खोल दिया है तो इससे बाहर के बहुत सारे लोग यहां आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने इकोनॉमी खोली है तो वह आपके लिए भी और उनके लिए भी खोली है। आप प्रतिस्पर्धा में आएं। उस वक्त इस देश को अच्छी दिशा और दशा दी गई। मुख्यमंत्री जी शोक संतप्त परिवार को जो पत्र लिखेंगे, मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ किशन कपूर जी के साथ भी मैं काफी देर तक विधायक भी रहा और मंत्री भी रहा। जब वे विपक्ष में थे तो मैं उस वक्त मंत्री था। वे भी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए उन्होंने अच्छा काम किया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

11.03.2025/1150/av/as/1

शोकोद्गार--------- **क्रमागत**

कृषि मंत्री --------- **जारी**

वे भी एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने अच्छे काम किए। वे धर्मशाला विधान सभा क्षेत्र से 5 बार जीते थे और वे मंत्रिमण्डल में भी रहे। वे ट्राइबल बैकराउंड के थे और उन्होंने वहां के लोगों के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। श्री किशन कपूर जी सांसद भी रहे और यह ठीक कहा है कि उनको सांसद के रूप में नम्बर दो पर हाईएस्ट वोट्स पड़े थे। मैं उनके लिए भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : अभी बहुत सारे सदस्यों ने शोकोद्गार पर बोलना है। परंतु आप सभी जानते हैं कि लगभग 50 मिनट्स बीत चुके हैं। इसके बाद प्रश्नकाल भी है। डॉ0 मनमोहन सिंह जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। अगर हम बोलने लगें तो उनके बारे में घण्टों बोला जा सकता है। इसलिए शोकोद्गार को इसी स्तर पर ...(व्यवधान) 50 मिनट हो चुके हैं और 12.00 बजने के लिए अब केवल 10 मिनट का समय शेष रहता है। मेरी यही चिंता है कि प्रश्नकाल नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इस माननीय सदन में दो मिनट का मौन भी रखना है। ...(व्यवधान) मैंने पहले कह दिया है कि Dr. Manmohan Singh was such a personality कि हम उनके बारे में घण्टों बोल सकते हैं। हम दोनों शोक संतप्त परिवारों को आप सबकी ओर से संवेदनाएं पहुंचा देंगे। ...(व्यवधान)

ठीक है, माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी, आप बोलिए।

11.03.2025/1150/av/as/2

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 मनमोहन सिंह जी हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं और इस माननीय सदन में उनके देहवसान के बाद आज शोकोद्गार के रूप में उनके जीवन के बारे में संवेदनाएं प्रकट करने के लिए मैं भी उपस्थित हुआ हूं।

इस सदन के नेता व तदुपरांत हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने उनके जीवन के बारे में बहुत विस्तार से उल्लेखनीय जानकारियां व टिप्पणियां की हैं। उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। उन्होंने इस देश को एक योग्य एजुकेशनिस्ट, अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इस माननीय सदन के माध्यम से मैं भी उनके शोक संतप्त परिवार को अपने श्रद्धासुमन प्रेषित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री किशन कपूर जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वे हमारे कांगड़ा-चम्बा संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद रहे। यहां पर जैसे श्री जय राम ठाकुर जी ने उनके जीवन के बारे में उल्लेख किया है कि वर्ष 1970 में जब जनसंघ थी तो वे उसके प्राथमिक सदस्य बनें। वे वर्ष 1982 में धर्मशाला मण्डल के मण्डलाध्यक्ष बनें। उन्होंने पहला चुनाव वर्ष 1985 में लड़ा था। उन्होंने वर्ष 1990 व वर्ष 1993 में धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र का विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1998 तथा वर्ष 2007 में फिर से चुनाव जीतने के बाद वे प्रो0 प्रेम कुमार जी की सरकार के समय दो बार मंत्री रहे।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2025/1155/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

शोकोद्गार ….. जारी

श्री विपिन सिंह परमार ... जारी

और जब श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे तो उन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री की जिम्मेवारी मिली थी। मैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि वे मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी विशेषता थी कि जो उनके दिल में होता था, वही जुबान पर होता था। कांगड़ा पहले एक संगठन के रूप में बड़ा जिला था लेकिन अब तो उसके छोटे-छोटे जिले बन गए हैं। एक बार मुझे भी उस संगठनात्मक जिला कांगड़ा का प्रशासनिक अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैंने श्री किशन कपूर जी से कहा कि आप बड़े सीनियर नेता है, वर्ष 1970 से जनसंघ से जुड़े हुए हैं और आप इसकी जिम्मेवारी सम्भालिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ही इसकी जिम्मेवारी सम्भालिए। मैंने उनसे कहा कि यह मेरे लिए मुश्किल होगा परंतु उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। इसलिए मुझे वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2007 तक यह आभास हुआ कि उनका व्यवहार बहुत मित्रवत् व्यवहार था। उनका व्यवहार एक भाई के रूप में था और वाकपटुता के रूप में उनकी पहचान थी। इसके कारण उनको राजनीतिक जीवन में कुछ बुरा भी झेलना पड़ा। वे अक्सर कहते थे कि यह जो सफेद चादर मैंने ओढ़ी है, इस पर कभी छींटे न पड़े। वे कोई भी बात साफ-साफ कह देते थे और चुनाव के दिनों में उन्हें इसका नुकसान भी हुआ। जब लोक सभा के लिए उनका नाम तय हुआ और यहां से मंत्री की जिम्मेवारियों से वे मुक्त हुए तो उन्होंने और श्री जय राम ठाकुर जी ने मुझे कहा कि आप वहां से मंत्री है, इसलिए हम आपको उस संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाते हैं। हमने लगभग 28 दिनों तक पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और हमने देखा कि पूरे क्षेत्र में उनकी अपनी अलग ही छवि थी। वे 'आइकन' थे। विशेषतौर पर जनजातीय क्षेत्र के लोग उनके नाम व उनके व्यवहार को लेकर हमेशा उनका सम्मान करते थे। समाज में उनकी बेहद साफ और स्पष्ट छवि थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था।

11.03.2025/1155/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

मुझे याद है जब श्री शांता कुमार जी केंद्रीय मंत्री थे तो वे भरमौर व चम्बा के पिछड़े क्षेत्रों में जाते थे जिनको ट्राइबल का स्टेट्स मिला था। कांगड़ा में भी गद्दी समुदाय के लोगों को ट्राइबल का स्टेट्स मिले लेकिन उसके लिए कौन प्रयास कर सकता था? केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे और शांता कुमार जी केंद्रीय मंत्री थे तथा यहां पर जनजातीय क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता के रूप में श्री किशन कपूर जी थे जिनको किशो के नाम से भी जाना जाता था। धर्मशाला में श्री अभिमन्यु कुमार चोपड़ा जी एक प्रसिद्ध वकील हैं और अध्यक्ष महोदय उनको आप भी जानते हैं। श्री शांता कुमार जी ने उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए जो इस कार्य को पूर्ण कर सके तो श्री शांता कुमार जी ने कहा कि एक व्यक्ति हैं जो स्लेट माइन का काम करते हैं और समृद्ध व्यक्ति हैं, तेज तरार व सम्पन्न व्यक्ति हैं तथा जनजातीय क्षेत्र में मेजर बृज लाल के बाद भाजपा के दो बार विधायक रहे हैं, आप उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने उस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया यानी कांगड़ा के क्षेत्र में गद्दी समुदाय या जाट समुदाय को जो ट्राइबल का स्टेट्स मिला है उसमें श्री शांता कुमार जी, श्रद्धेय अटल जी और श्री किशन कपूर जी जैसे दूरदृष्टि वाले नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री अभिमन्यु कुमार चोपड़ा और श्री किशन कपूर जी (किशो) की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसी भूमिका के रूप में मुझे दो ही बातें याद हैं कि जब उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष बनिए और संसदीय क्षेत्र में प्रभारी के रूप में काम किया। उनका मित्रवत व्यवहार जो जुबान पर था वही चेहरे पर था और ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके परिवार में उनके पिता श्री हरि राम जी थे। जब हम धर्मशाला जाते थे तो वे डी0सी0 आफिस, एस0डी0एम0 या वैल्फेयर ऑफिस के बाहर मिलते थे। हम उनसे पूछते थे कि आपका बेटा तो नेता व विधायक हैं। तब वे कहते थे कि

एन0एस0 द्वारा जारी ...

11-03-2025/1200/ns-dc/1

श्री विपिन सिंह परमार .....जारी

मुझे चैन नहीं आती जब तक मैं हर दिन 5-10 लोगों का अपने हाथों से काम नहीं करवाऊं। वे घूमते रहते थे। खनियारा में जहां पर श्री किशन कपूर जी का मूल घर था वे वहां से पैदल चल करके जिला मुख्यालय धर्मशाला पहुंचते थे और हर दिन काम करते थे। ऐसी छवि उनके परिवार की थी और उनका परिवार एक सम्पन्न परिवार है। मैं यह भी कह सकता हूं कि वे समाज की केयर और लोगों की केयर करते थे। श्री किशन कपूर जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा कपूर जी ज्वाइंट डायरैक्टर हैं और उनका एक बेटा व एक बेटी है। मैं श्री किशन कपूर जी से धर्मशाला व चंडीगढ़ में मिला था और उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने उस समय मुझे इतना ही कहा कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और ठीक हो करके आ जाऊंगा। उनको जो ब्रेन हेमरेज हुआ उसके बाद मृत्यु ने उनको अपने गले लगा लिया और आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भेजना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी शोकोद्गार में भाग लेंगे। Please be very brief.

11-03-2025/1200/ns-dc/2

Health & Family Welfare Minister: Thank you, Mr. Speaker, Sir, you gave me time to speak. As per the directions I will be very brief. A lot has been said about Dr. Manmohan Singh ji. I quite agree with the Hon'ble Speaker, Sir, that even if we keep on speaking for the hours together, still it will not be enough to speak on this great gentleman Prime Minister of our times. As Hon'ble Member Prof. Chander Kumar ji has said it was an honour to work with him. He use to speak in concise but very politely. Once Members of Shri Guru Singh Sabha, Shimla requested me that I work with the Hon'ble Prime Minister so they want me to invite him for the Gurupurab to Shimla. I agreed to this. When I visited him at his residence, he himself got me a glass of water from the fridge, I was

really humble to see a Prime Minister of our Country serving a glass of water to his colleague. That was Dr. Manmohan Singhji. I was student in DAV College Ambala from the year 1957-59. As I was also a student of economics. We had visited Punjab University along with Prof. C.L. Khanna where Dr. Manmohan Singh was Lecturer of Economics. I never knew that one day I will see him as Prime Minister of the Country in my life. He was Doctorate from Cambridge University with so many epithets in him but he never exhibited that. He was so talented and knowledgeable that whether it was Shri P.V Narasimha Rao or Shri Atal Bihari Vajpayee, for everyone his behavior was like down to earth person working for the Country. As Prof. Chander Kumar ji said, Dr. Manmohan Singh ji was considered to be very quiet. He hardly spoke and because of that many people use to say that 'we have Prime Minister who doesn't speak'. Once Former President of USA Mr. Barack Obama remarked 'when Dr. Manmohan Singh speaks the whole World listens. He will speak only when it is required and when he will speak he will really mean it'.

Continued in eng...by DC

11.03.2025/1205/RKS/डी.सी.-1

Health& Family Welfare Minister continues….

After Pt. Jawaharlal Nehru, he was re-appointed as the Prime Minister again completing the term of five years. Although when we see the length of Prime Ministers there is a big list after Pt. Jawaharlal Nehru; Smt. Indira Gandhi was there, Shri Narendra Modi is there. In 2004, Congress led NDA had to decide the Prime Minister and the whole House including Prof. Chander Kumar ji and me were sitting in the Central Hall waiting for Smt. Sonia Gandhi ji who was to come from the President House and declare the Prime Minister. After some time when she came to the House and gave great surprise to everyone and

announced the name of Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister. He himself never expected that he will be announced as the Prime Minister. Once the British Journalist Mark Tully said that on the day Shri P.V. Narsihma Rao was formulating his Cabinet, he sent his Principal Secretary to Dr. Manmohan Singh saying the Prime Minister would like him to become his Minister of Finance. Dr. Manmohan Singh said that he doesn't take it seriously. But Shri P.V. Narsihma Rao eventually came personally to him. Next morning in very angry mood he told Dr. Manmohan Singh to get dressed up and come to Rashtrapati Bhawan for the Swearing Ceremony. So that is how he said that my journey in politics started. You have seen in the year 1990-91 India's Fiscal Deficit was closed to 8.5 per cent of the Gross Domestic Product(GDP). The balance of payment deficit was huge and current account deficit was closed at 3.5 per cent of India's DGP. India's foreign reserve barely amounted to US dollar one billion, enough to pay two weeks of import in comparison to US six hundred billions. Dr. Manmohan Singh explained to the Prime Minister and to the Party that India is facing unprecedented crisis and as you know the rest is the history; but he faced all the challenges and became the liberator out of this financial crises. That will be remembered by all times to come. He could be

11.03.2025/1205/RKS/डी.सी.-2

compared with so many great Leaders of the World who worked silently and relentlessly. As told by Hon'ble Member Shri Chander Kumar he really was the father of our whole economy specially MGNRAGA, Right to Information, Right to Food and like TANDA Medical College. So many things will go down in favor of Dr. Manmohan Singh. Considering the constrain of time as given by the Hon'ble Speaker, I bow down to him and pay my respect. We all, Hon'ble Chief Minister, Hon'ble Deputy Chief Minister and I had gone to pay homage. I

today in this august House pay my offering for the peace of the departed soul who led this Country to such good heights.

I also pay homage to gentleman and politician Shri Kishan Kapoor. A lot was told about him by the Hon'ble Leader of Opposition and Hon'ble Member Shri Vipin Singh Parmar. He was really a gentleman and very clear person in his dealings. I remember he told me कर्नल साहब मुझे आपका मकान नं0-7 अलॉट हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि आपको 24 घंटे के भीतर यह मकान खाली मिलेगा। He felt so happy. I never knew that one day we shall loose him suddenly. I pay all my respect to him and really expect the House also to join in this Motion. We have lost a gentleman out of us. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री सुधीर शर्मा जी अपने शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे। Please be short and brief. I am giving you time to speak since you are the Hon'ble MLA from an area from where Late. Shri Kishan Kapoor ji was.

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष ने जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री, डॉ0 मनमोहन सिंह और पूर्व मंत्री एवं सांसद, स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

11.03.2025/1210/बी.एस./एच.के./-1

श्री सुधीर शर्मा जारी...

मैं अपने आप को इसमें शामिल करता हूं और स्वर्गीय किशन कपूर जी ने लम्बा समय धर्मशाला चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे पांच बार विधायक रहे और कांगड़ा-चम्बा के सांसद भी रहे। मेरा पहली बार कॉलेज के दिनों में उनसे परिचय हुआ। बैजनाथ में मुकुट

नाथ जी नामक एक स्थान है, वहां पर स्वामी रामान्द जी रहते थे और वहां पर वे अक्सर आया करते थे। जब कॉलेज के समय में मैं वहां पर आता था तो उसी आश्रम में रहता था, मैं उनसे पहली बार वहीं मिला था। वे एक ईमानदार, स्पष्टवादी व्यक्ति थे और जो उनके दिल में होता था उसे ही वे मुंह से बोलते थे। उसके बाद वर्ष 2007 में जब मैं दूसरी बार विधायक बना तो वे मंत्री थे और उस वक्त पुनर्सिमांकन हो रहा था। उस समय बैजनाथ आरक्षित हुआ और मैं उस दौरान भी उनसे मिला वे मेरे सारे काम कर दिया करते थे। परंतु मेरी चिंता भी करते थे कि अब तुम्हारा क्या होगा? वे कहते थे कि आपकी आयु अभी बहुत छोटी है। वे हमेशा मेरी चिंता किया करते थे। मेरी माता जी का संबंध खनियारा से रहा है इसलिए भी वे मेरी विशेष चिंता करते थे। वर्ष 2012 में मुझे धर्मशाला से कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और मैंने उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा। परंतु कभी कोई ऐसी टिप्पणी या बयान नहीं दिया। अभी जब मैंने उपचुनाव लड़ा, जो उनका स्वभाव था उसे देखते हुए कोई भी यह प्रयास नहीं कर पा रहा था। परंतु मैं सबसे पहले उनसे मिलने गया। मैं वहां पर दो घंटे बैठा रहा और पूरे चुनाव में उनका मार्गदर्शन लेता रहा और उन्हीं के कार्यालय के लोग जो उनका चुनाव का काम संभालते थे, मेरे चुनाव में भी उन्होंने ही सारा कार्य संभाला। क्योंकि वे अस्वस्थ थे इसलिए उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा था कि मैंने पूरा जीवन नियमों में रह करके बिताया है, हमेशा खाने-पीने व अन्य सब प्रकार का परहेज किया। परंतु यह मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? जब वे दोबारा फोलोअज के लिए चण्डीबढ़ गए, मेरी बात उनसे हुई। उन्होंने कहा कि मैं थोड़े ही दिनों में वापिस आऊंगा, परंतु दोबार जब फिर से उनकी स्थिति गंभीर हो गई तो मैं चण्डीगढ़, पी0जी0आई0 गया। डॉक्टर्ज ने उनसे मिलने के लिए इंकार कर दिया था। मैं उनके परिजनों से बात करके आया। धर्मशाला के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और जिस तरह से एक व्यक्तिगत क्षति बड़े भाई के नाते उनके जाने से मुझे हुई है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद।

11.03.2025/1210/बी.एस./एच.के./-2

अध्यक्ष : अब डॉ0 जनक राज जी शोकोद्गार में भाग लेंगे।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, जो शोकोद्गार का प्रस्ताव आज सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष ने सदन में रखा है, उसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। डॉ0 मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधान मंत्री ने 26 सितम्बर, 1932 को अखण्ड भारत में जन्म लिया। देश की उन्नति और देश के विकास के योगदान को शब्दों में समा पाना मुश्किल है। जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी, आप ने भी कहा कि कहने लगे तो पूरा समय क्या पूरा दिन इसमें लग जाएगा। उनकी एक बहुत बड़ी यात्रा है और मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि वे इकलौते देश के प्रधान मंत्री हैं जिनके नोटों पर भी हस्ताक्षर हैं, क्योंकि वे आर0बी0आई0 के गवर्नर भी रहे हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और देश के प्रति उनके योगदान को देश सदैव याद रखेगा। इतना ही मुझे कहना है।

मैं स्वर्गीय किशन कपूर, पूर्व सांसद जी के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गद्दी समुदाय से संबंध रखता हूं और वे हमारे समुदाय के बहुत बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया। जैसा पूर्व में माननीय सदस्य विपिन सिंह परमार जी ने कहा कि किस तरह से उनका राजनीति में पदार्पण हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यह दुर्भाग्य है कि हमारे साथ आज श्री किशन कपूर जी नहीं हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

11.03.2025/1215/डीटी/एचके-1

शोकोद्गार... जारी

डॉ. जनक राज जारी...

स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी तीन बार कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने एक बार लोकसभा सांसद और पांच बार धर्मशाला विधान सभा क्षेत्र से धर्मशाला का प्रतिनिधित्व किया। उनकी निष्कलंक सेवा और जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए पूरा प्रदेश और विशेषकर गद्दी समुदाय हमेशा उन्हें याद रखेगा। जैसा बताया गया की वर्ष 1970 में वह जनसंघ से जुड़े और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजनीति में अपनी प्रतिभा के दम पर अनेकों आयाम स्थापित किए। मैं विशेषतौर से उनकी संवेदनशीलता, ईमानदारी और मानवीय दृष्टिकोण की छवि का उल्लेख करना चाहूंगा।

जब मैं धर्मशाला में नौकरी करता था तो वर्ष 2009 में मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय हुआ। श्री किशन कपूर जी गद्दी समुदाय से संबंध रखते थे इसलिए उन्होंने गद्दी समुदाय के उत्थान के लिए विशेषतौर पर कार्य किया। हालांकि गद्दी समुदाय का मूल स्थान भरमौर है परंतु भरमौर से अधिक संख्या में गद्दी समुदाय के लोग कांगड़ा जिला में रहते हैं। उन्होंने इन सब लोगों के जनजातीय हकों को दिलाया। गद्दी समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय भेड़-पालन है। जब सर्दियों के समय में हमारे घुमंतू भेड़-पालक कांगड़ा जिला में आते हैं तो उनकी समस्याएं, जैसे पशु चोरी होना या यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान जैसी घटनाओं के लिए उन्होंने हमेशा सदन के भीतर और सदन के बाहर अपनी आवाज बुलंद की। घुमंतू भेड़ पालकों को सफर के दौरान जो दिक्कतें होती थी, जैसे रहने की समस्या या बारिश के समय में होने वाली समस्याएं इत्यादि, उसके लिए तिरपाल बांटने से लेकर घुमंतू भेड़ पालकों एवं उनके पशुधन की सुरक्षा के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई और अपने समुदाय के उत्थान के लिए तत्परता से लगे रहे। आज माननीय किशन कपूर जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन हिमाचल प्रदेश का जिला कांगड़ा और विशेष कर हमारे समुदाय के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। उनके देहांत से हिमाचल प्रदेश और विशेषकर गद्दी समुदाय को भारी क्षति हुई है। मैं समस्त गद्दी समुदाय की ओर से भगवान से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2025/1215/डीटी/एचके-2

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जी अपने शोकाद्गार प्रस्तुत करेंगे।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह और स्वर्गीय सांसद एवं मंत्री श्री किशन कपूर जी के प्रति शोकोद्गार रखे हैं, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। इसमें नेता प्रतिपक्ष और बाकी माननीय सदस्यों ने भी अपने आप को शामिल किया है। मुझ से पूर्व वक्ताओं ने जो

बातें कही हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। डॉ0 मनमोहन सिंह जी देश के सर्वोच्च फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर.बी.आई. के भी गवर्नर रहे। जब वे देश के वित्त मंत्री बने तो देश की अर्थव्यवस्था एक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लोन देने के लिए सोना गिरवी रखवा रही थी। बाद में वे देश के प्रधानमंत्री बने। उनका किसी पोजीशन के प्रति कभी कोई मोह नहीं था। उन्होंने डिटैच्ड होकर एक बैरागी भाव से हमेशा उस पोजीशन पर रहकर काम किया। डॉ0 मनमोहन सिंह जी जब इस देश के वित्त मंत्री बने उस समय हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वह बहुत कम था और वह लगभग एक हफ्ते से ज्यादा नहीं था। उस समय हमारा बजट का साइज 72000 करोड़ रुपये था। उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर सर्विस सेक्टर की पहचान की और सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस किया और उसका आज नतीजा है कि हम 72000 करोड़ से 48 लाख करोड़ रुपये के बजट साईज में पहुंचे है इसकी नीव उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाकर शुरु की थी। जहां विभिन्न देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के लिए गैट एग्रीमेंट साईन किया, हालांकि उस समय उसका बहुत विरोध होता था- उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे और विपक्ष के हमारे बहुत सारे साथी उसका विरोध करते थे। एक नारा लगया जाता था कि डंकल-अंकल नहीं चलेंगे। क्योंकि उनका विजन क्लीयर था और उन्होंने गैट एग्रीमेंट साईन किया

श्री एन. जी.द्वारा... जारी

11.03.2025/1220/वाई.के.-एन.जी./1

शोकोद्गार.....जारी

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री.....जारी

तथा जिससे बाद में World Trade Organization (WTO) निकली। आज उससे देश लाभान्वित भी हो रहा है। उन्होंने न केवल टैरिफ पर ध्यान दिया बल्कि टेक्नोलॉजी

ट्रांसफर पर भी फोकस किया। जब वे देश के वित्त मंत्री थे तब उन्होंने वैट लागू किया था। जब वे देश के प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने जी0एस0टी0 को भी लागू करने की पूरी कोशिश की थी। वे बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। जब भारत सरकार ने विमुद्रीकरण का फैसला लिया था तब उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इससे हमारी जी0डी0पी0 का डाउनफॉल होगा। इसी प्रकार से उन्होंने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया। इसके तहत उन्होंने किसानों को महज चार प्रतिशत के सिम्पल इंट्रस्ट पर लोन देने का फैसला लिया क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहे थे। इससे पहले जिन किसानों पर लोन था और वे लोन वापिस नहीं कर पा रहे थे तो उन किसानों के लिए 72 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ माफ करने का भी फैसला किया। यह उनकी सादगी का ही प्रतीक है कि जब वे देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने फैसला लिया कि मेरी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। वे अपने प्रचार-प्रसार पर विश्वास नहीं करते थे। वे देखने में बहुत सरल लगते थे लेकिन जब प्रिंसीपल्ज़ व देशहित की बात आई तब हम सबने देखा कि न्यूक्लियर एग्रीमैंट के दौरान हमारी सरकार खतरे में पड़ जाने के बाद भी उन्होंने इस एग्रीमैंट को साइन किया। उस समय हमारी सरकार के सहयोगी दलों ने अपना समर्थन वापिस ले लिया था लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बिना भी यह एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने उस समय कहा था कि मेरी सरकार गिरनी है तो गिर जाए लेकिन हमें देशहित में न्यूक्लियर एग्रीमैंट करना है। आज हम जो न्यूक्लियर एनर्जी डवलप कर पा रहे हैं तो इसका श्रेय स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी को जाता है।

11.03.2025/1220/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा उन्होंने टेलीकॉल सैक्टर में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। टेलीकॉम सैक्टर में पहली बार 3जी स्पैक्ट्रम की ओपन ऑक्शन की गई। उस समय 3जी स्पैक्ट्रम की ऑक्शन से भारत सरकार को लगभग 67000 करोड़ रुपये मिले थे।

वे अन्य राजनेताओं की तरह राजनीतिज्ञ नहीं थे इसलिए हमारे मित्रों ने उसे घूमा कर 2जी स्पैक्ट्रम के साथ जोड़ दिया। हालांकि 2जी स्पैक्ट्रम के समय परिस्थितियां और थीं लेकिन एक 'presumptive loss' दिखा कर उसे 2जी स्कैम के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की गई। उससे उन्हें बहुत दुःख हुआ था। उन्होंने बहुत सिम्पल शब्दों में कहा था कि 'History will do justice with me', 'इतिहास जब लिखा जाएगा तब मेरे साथ न्याय होगा'। बाद में उस पर फैसला भी हुआ और उसमें किसी भी प्रकार का स्कैम नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ 'presumptive loss' दिखा कर और उसे आधार बना कर राजनीतिक रूप से नुकसान करने का प्रयास किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि उन्होंने टीचर्स के लिए यू0जी0सी0 पे-स्केल लाया था। उनका मानना था कि 'best mind should be in the teaching professional, it should not be the last option but it should be the priority option'. उन्होंने इस तरह की सोच को लेकर काम किया था। आने वाले पीढ़ियों को यदि हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे तो स्वभाविक है कि उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। जो राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान हैं, उसमें चाहे IIT, Central University, IIM and AIIMS हों, ये हर प्रदेश में होने चाहिएं और उनके समय में इस पर फैसला लिया गया था। उसी के परिणाम स्वरूप हमें मेडिकल कॉलेजिज़ मिले हैं। वे इस प्रकार की सोच रखने वाले महान व्यक्ति थे। उनके बारे में कई घण्टों तक बोला जा सकता है और जितना बोला जाए उतना ही कम होगा। माननीय सदन की अपने समय सीमा होती है इसलिए ज्यादा न बोलता हुआ मैं अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

11.03.2025/1225/पी0बी0/वाई0के0/-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी...

और भगवान उनके परिवार को सब्र प्रदान करे। दूसरा, स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी जो इस माननीय सदन के भी सदस्य रहे हैं। जब मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बना तो उस समय वे सरकार में मंत्री थे। मुझे याद है कि ट्रांस्पोर्ट से सम्बंधित एक घुमारवीं बस अड्डे का छोटा सा इश्यू था उसमें जो भाजपा के लोकल नेता थे वह हमारे उस इश्यू का विरोध कर रहे थे लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं वही करूंगा जो विधायक के तौर पर आप बोलेंगे। यह उनकी बड़ी सोच को दिखाता है क्योंकि वह उन्होंने उस इन्सच्यूशन को रिस्पैक्ट देने के लिए किया। वे उस समय वह युवा थे। वह हमें भी प्रोत्साहित करते थे कि आप अच्छा काम करो और हम आपकी पूरी स्पोंट करेंगे। एक बार मैंने प्रश्न किया कि जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से सीमेंट की प्रोक्योरमैंट होती है उसमें पी0डब्ल्यू0डी0, आई0पी0एच0 के अलावा भी जो डिपार्टमैंटस रूरल डेवल्पमैंट या फॉरेस्ट डिपार्टमैंट है उसमें भी सिविल सप्लाई कोरपोरेशन से सीमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। इस पर वह सदन में बोले कि इसमें ज्यादा बचत नहीं होगी। लेकिन बाद में उन्होंने फैसला लिया और उसको स्वीकृति दे दी। जब साल के आखिर में उसका परिणाम निकला और उनके ध्यान में विभाग द्वारा लाया गया तो उन्होंने मुझे एप्रीशियेट किया कि इसकी वजह से एक वर्ष में 27 करोड़ रुपये की बचत हुई है। वह बड़े लिबरल सोच के व्यक्ति थे। एक बार हम एन0आई0टी0 में गए वहां उनकी बेटी वहां पढ़ती थी, तभी उन्होंने हमें साथ बिठाया। वह हमें काफी ज्यादा प्रोत्साहित करते थे और बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। एक बार कोई इन्चैस्टर थे उनकी फाइल उनके पास थी और वह मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पहली बार ऐसा मंत्री देखा कि बिना कुछ एक्सपैक्ट किए, बिना कोई लागलपेट के उन्होंनें तुरंत ही हमारी फाइल पास की। वह भोले-भाले आदमी थे और वह गद्दी समुदाय से सम्बंध रखते थे, उनके अंदर भोलापन था तो मैं समझता हूं कि वह उस बात का प्रतीक था जिस समुदाय से वे सम्बंध रखते थे। जब हमें उनके देहांत का समाचार मिला तो बहुत दुःख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सब्र प्रदान करें यही हम कामना करते हैं।

11.03.2025/1225/पी0बी0/वाई0के0/-2

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

Speaker : I am sorry, I will not be in a positon to give time to the rest of the Hon'ble Members. I am sorry, now its 12:30 pm and already enough time has been given. स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधान मंत्री व श्री किशन कपूर, पूर्व सदस्य के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और इस मान्य सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा।
अब मैं, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(सभा में उपस्थित सभी ने खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ क्षण के लिए मौन रखा।)

साप्ताहिक कार्यसूची श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

11.03.2025/1230/AP/A.G./ 01

सप्ताहिक शासकीय कार्यसूची के बारें में वक्तव्य

अध्यक्ष : अब मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जोकि इस प्रकार है:

मंगलवार 11 मार्च, 2025:

1.शोकोद्गार

2. शासकीय एवं विधायी कार्य।

3.अनुपूरक बजट प्रथम एवं अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष 2024-25 प्रस्तुतीकरण एवं पारण।

i. सामान्य चर्चा।

ii. मागों पर चर्चा एवं मतदान; और

iii. विनियोग विधेयक पुरःस्थापना, विचार विमर्श एवं पारण।

4. राज्यपाल महोदय पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

बुधवार 12 मार्च, 2025ः

1.शासकीय एवं विधायी कार्य।

2.राज्यपाल महोदय में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

वीरवार 13 मार्च, 2025 ः

1. शासकीय व विधायी कार्य।

2.राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

11.03.2025/1230/AP/A.G./ 02

शुक्रवार 14 मार्च,2025 ः "होली" अवकाश

शनिवार 15 मार्च,2025 ः

1. शासकीय व विधायी कार्य।

2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण।

Speaker: What do you want to speak? Whether it is Point of Order or something else?

Shri Jai Ram Thakur: Yes, Sir.

Speaker: What is that?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण इस माननीय सदन में हम सब लोगों ने सुना। यह हम अच्छी तरह से जानते है कि महामहीम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण जो होता है वह सरकार की तरफ से डोकोमंट होता है जिसमें सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है। इस व्यवस्था के अनुरूप राज्यपाल महोदय जी इसे पढ़ते हैं और जब वह पढ़ते है तो उस वक्त वह उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो लिखे हुए होते है। इसमें राज्यपाल महोदय जी मेरी सरकार का जिक्र करते हैं। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि आज तक के इतिहास में जो समाचार पत्रों में जिस तरह से उस सारी चीज़ को हैडीग करके लगाया गया है मैं सोचता हूं कि वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यपाल महोदय, जी की गरीमा के खिलाफ है। राज्यपाल के इंस्टीटयूशन के खिलाफ है, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। हिमाचल के दो-तीन समाचार पत्रों में मैने देखा यहां खबर लगी है, जिक्र भी करूगां दैनिक जागरण में लिखा गया है कि हिमाचल की खराब वित्तीय हालात के लिए केंद्र जिम्मेदार राज्यपाल इस प्रकार से खबर लगाई गई है। राज्यपाल जी का अपना अभिभाषण तो होता नहीं है एक शब्द भी उनका अपना नही होता, जो होता है वह सरकार का होता है।

दूसरा, पंजाब केसरी में हिमाचल की खराब वित्तीय हालत के लिए केंद्रीय सरकार जिम्मेबार राज्यपाल। …(Interruption)

11.03.2025/1230/AP/A.G./ 03

Speaker: Please, please. No Interruption please. …(Interruption) Please, please. …(Interruption) I am listening to you.

श्री जय राम ठाकुर : तीसरा, अमर उजाला में भी सरकार ने दो साल में पूरी की 6 गारंटियां, जी0एस0टी0 से सरकार को घाटा,राज्यपाल। यह सभी खबरें राज्यपाल जी के अभिभाषण, राज्यपाल जी के नाम पर छापी गई। क्या यह जिम्मेदाराना व्यवहार जो मीडिया के लोगों की तरफ से हुआ है विधान सभा के सतर से या सरकार के स्तर से हुआ है। यह चिंता का विषय है आज तक राज्यपाल जी भाषण देते रहें और हर बार मेरी सरकार ही कहा जाता है। लेकिन उसके बाद मंशा लगती है कि मुख्यमंत्री जी बैठ कर यह टिप्पणी

कर रहें है कि जो कहा गया है वह ठीक कहा गया है जो लिखा है वह ठीक लिखा हुआ है तो मैं समझता हूं यह हैडिग देने के लिए क्योंकि सरकार का दबाव लगातार दो वर्षों तक मीडिया के उपर रहा मीडिया के उपर एफ0आई0आर0 मीडिया के उपर अत्याचार, दवाब कहीं इसके चलते तो नहीं सरकार ने इस तरह से किया।

Speaker: I have taken a note of that.

श्री जय राम ठाकुर : इस बात को मैं विषेश तौर से में चाह रहा हूं यह विधान सभा के इतिहास में ऐसा नहीं होआ है। अध्यक्ष महोदय, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए और मीडिया के प्रति मेरा भी सम्मान है लेकिन आज से पहले कभी भी मीडिया ने राज्यपाल जी की टिप्पणी को इस प्रकार से हैडिंग के रूप में नहीं किया है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। राज्यपाल का अपना कोई शब्द नहीं होता है जो भी होता है सरकार की तरफ से होता है।

ए0टी0 द्वारा जारी.....

11.03.2025/12:35/AT/AG/.1

श्री जयराम ठाकुर द्वारा जारी .....

एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो कि होता ही होता है इसलिए मैं समझता हूं कि सारे विषय में कॉग्निजेंस लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी स्पष्ट करना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए और जिन मीडिया के पेपर में यह खबर लगी है उनके साथ इस मामले को टेक अप करना चाहिए ।

Speaker: I have taken a note of the references, which have been made by the Hon'ble Leader of the Opposition and I will go through the record also. In any case if somebody moves the Motion against the erring Press people, then certainly this House will take a cognizance of that also. Now before that.

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पांच साल सत्ता में रहे हैं और जब भी राज्यपाल भाषण देते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, हिमाचल सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हैं। हेडिंग लिखना या ना लिखना अखबार वालों का दायित्व

होता है। अब आप अखबार वालों को यह धमकी दे रहे हो? कोई भी चीज अगर राज्यपाल द्वारा बोली जाएगी, चाहे हमारे ही बारे में क्यों न बोली जाए, क्योंकि हमारे भाषण को पहले कैबिनेट अप्रूव करती है उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास जाता है। राज्यपाल महोदय के बाद अप्रूव होकर फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, वह यहां इसके माध्यम से पढ़ा जाता है। कोई भी चीज बोली जाएगी तो अखबार क्या लिखेगी सरकार , बोलिए राज्यपाल सरकार का भाषण है .....(व्यवधान) आप कंन्फ्यूज क्यों हो रहे हैं इसमें लिखना पड़ेगा मुख्यमंत्री बोले उनका शब्द हटा देना आपने और यह लिख देना.....(व्यवधन) देखिये हेडिंग पर क्या लगाना है यह अखवारों का अधिकार है मैं किसी की हेडिंग को नहीं रोक सकता और मंच से पत्रकारों को धमकाना और यह कहना कि यह देख ले, भाई ये सरकार का वक्तव्य है आप उस पर ऐसे क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए कि आप राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री लिख देना क्योंकि पढ़ा उनके द्वारा गया है ऐसा चाहते हैं आप मेरा कहने का मतलब है राज्यपाल ही लिखा जाएगा क्योंकि जब उनके द्वारा बोला गया होगा तो उनका नाम ही लिख जाएगा। लॉ यही बोलता है

Speaker: I have already given a ruling to this. I will go through the record also and the things which have been pointed out by the Hon'ble Leader of the Opposition, if anything is to be done in this behalf, certainly we will take action accordingly. Thank you.

11.03.2025/12:35/AT/AG/.2

अब सचिव, विधानसभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विधेयकों की प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है :-

1. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 1);
2. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 2);
3. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 3) ;
4. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 4) ;
5. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 5) ;
6. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 6) ;
7. हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 7) ;
8. चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 8) ;
9. ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय

11.03.2025/12:35/AT/AG/.3

10. स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 9);
10. इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 10) ;

11. श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 11);

12. **दि इनस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 12**);

13. **महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 13**);

14. **हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 14**);

15. **हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक) विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 15**);

16. महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 16);

17. **शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम संख्यांक 17) ;

18. **कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 18**) ;

19. बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 19) ;

11.03.2025/12:35/AT/AG/.4

20. ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 20) ;

21. अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 21) ;

22. **आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 22**);

23. **हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 23**);

24. **हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2023** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 24**);

25. बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 25) ;

26. **मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 26**);

27. अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 27) ;

28. **हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 28**);

29. **हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 29**); **और**

30. **हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024** (2025 का अधिनियम **संख्यांक 30**) ।

11.03.2025/12:35/AT/AG/.5

अध्यक्ष : अब श्री जगत सिंह नेगी, माननीय राजस्व मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 13.02.2025 को प्रख्यापित, **भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन), अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्यांक 1)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे। । will request the Secretary, Vidhan Sabha to read this also. Please give it with the English version also

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमती से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 13.02.2025 को प्रख्यापित, **भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन), अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्यांक 1)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

11.03.2025/12:35/AT/AG/.6

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन समितियां के प्रतिवेदन आप **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2024-25),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे

श्री मोहनलाल ब्रक्टा : अध्यक्ष मोदी में आपकी अनुमति से **कल्याण** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

1. समिति का **30वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 19** (वर्ष 2023-24) की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के प्राप्त विभागीय उत्तरों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

2. समिति का **31वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

3. समिति का **32वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

श्रीमती एम0डी0द्वारा जारी.....

11.03.2025/1240/MD/AS/1

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अंतिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रस्तुतीकरण एवं पारण

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अंतिम किस्त) को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम तथा अन्तिम किस्त प्रस्तुत कर रहा हूं।

ये अनुपूरक मांगें 17053.78 करोड़ रुपये की हैं जिनमें से 15776.19 करोड़ रुपये राज्य स्कीमों और 1277.59 करोड़ रुपये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु प्रावधित किए गए हैं।

राज्य स्कीमों के अंतर्गत मुख्यतः 10137.07 करोड़ रुपये Ways and Means और ओवरड्राफ्ट के लिए, 1033.63 करोड़ रुपये विद्युत उपदान, मॉनसून के दौरान क्षतिग्रस्त 33 KVA/11 KVA ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और HPPTCL, HPPCL, HPSEBL व HPSLDC को ऋण, 814.94 करोड़ रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों को किराये में दी जा रही छूट की एवज में उपदान, ई- बसों की खरीद 763.26 करोड़ रुपये पैंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 455. 91 करोड़ रुपये मैडिकल कॉलेजों के निर्माण एवं मशीनरी की खरीद तथा हिम केयर योजना, 329.44 लाख रुपये

जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं, 303.67 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा राहत, 173.25 करोड़ रुपये पर्यटन विकास, 150.19 करोड़ रुपये मॉनसून के दौरान क्षतिग्रस्त पाठशाला भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण, नई पाठशालाओं एवं महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण इंडोर ऑडिटोरियम के निर्माण तथा फार्मेसी कॉलेज सिराज के लम्बित दायित्व के भुगतान, 142.83 करोड़ रुपये 15वें वित्तायोग के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, 135.88 करोड़ रुपये सड़कों/ पुलों के निर्माण व मुआवजे, 130.16 करोड़ रुपये कामकाजी महिला हॉस्टलों के निर्माण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं के मानदेय, मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के अंतर्गत विभिन्न व्ययों, 127.77 करोड़ रुपये द्वारका, नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के निर्माण, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के

11.03.2025/1240/MD/AS/2

छात्रावास के निर्माण और कार्यालय भवनों के निर्माण व रख-रखाव, 124.50 करोड़ रुपये रेल परियोजनाओं, 120.72 करोड़ रुपये मनरेगा (Top up) के अंतर्गत मज़दूरी के भुगतान, 88.97 करोड़ रुपये बल्क ड्रग पार्क, मैडिकल डिवाइस पार्क और हिम स्वान कनैक्टिविटी, 81.52 करोड़ रुपये शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, मॉनसून के दौरान क्षतिग्रस्त विभिन्न मल निकासी योजनाओं, रास्तों, एम्बुलेंस सड़कों व पार्किंग मरम्मत व पुनर्निर्माण और एस0जे0पी0एन0एल0 में निवेश, 79.62 करोड़ रुपये जायका प्रोजैक्ट एम0आई0एस0 के लम्बित दायित्व और 73.54 करोड़ रुपये आवासीय भवनों के निर्माण व रख-रखाव, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु प्रतिबन्धित किए गए हैं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है। 296.56 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, 207.71 करोड़ रुपये एन0डी0आर0एफ0 से प्राप्त आपदा प्रबन्धन हेतु, 207.23 करोड़ रुपये रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजे, 90.28 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री ग्राम आवास योजना (ग्रामीण) , 53.39 करोड़ रुपये मनरेगा, 51.74 करोड़ रुपये AMRUT, 43.25 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री स्कूल्ज़ फॉर

राइज़िंग इंडिया, 42.71 करोड़ रुपये बी0पी0एल0 परिवारों को गेहूं और चावल पर उपदान, 38.62 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्राम स्वरोज़गार अभियान, 35.23 करोड़ रुपये विशेष पोषाहार कार्यक्रम, 22.29 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन और 18.88 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु प्रस्तावित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान मांगों की रूपरेखा प्रस्तुत की है । मांगों का पूरा विवरण माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेज में दर्शाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से इन अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

11.03.2025/1240/MD/AS/3

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अंतिम किस्त) पर चर्चा होगी जो आज ही समाप्त होगी तथा मांगों पर मतदान भी आज ही होगा। उसके उपरांत हिमाचल विनियोग विधेयक भी पारित होगा।

सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकते हैं तथा माननीय मुख्य मंत्री जी जिनके पास वित्त विभाग भी है, चर्चा का उत्तर देंगे।

अब वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा।

सभा का समय बचाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से सभी मांगों को प्रस्तुत हुआ समझा जाए और इन्हें मैं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं जोकि निम्न प्रकार से हैं :-

मांग संख्या	मांग का नाम		मांग की राशि जो विधान सभा की स्वीकृति वोट के लिए प्रस्तुत है। ₹ में
1	2		3
01	विधान सभा	(राजस्व) (पूंजीगत)	6,37,65,811 28,37,05,000
02	राज्यपाल और मंत्री परिषद्	(राजस्व)	1,52,95,581
03	न्याय प्रशासन	(राजस्व) (पूंजीगत)	55,26,73,332 31,11,22,000
04	सामान्य प्रशासन	(राजस्व) (पूंजीगत)	24,45,90,631 50,25,20,000
05	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व) (पूंजीगत)	5,38,03,50,785 21,00,00,000
06	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	13,13,70,258
07	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व) (पूंजीगत)	13,000 31,75,45,000
08	शिक्षा	(राजस्व) (पूंजीगत)	12,000 88,57,91,954
09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व) (पूंजीगत)	81,54,00,785 3,92,65,89,444
10	लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	(पूंजीगत)	4,56,11,20,000
11	कृषि	(राजस्व) (पूंजीगत)	33,88,02,000 1,40,00,000
12	उद्यान	(राजस्व) (पूंजीगत)	23,06,12,000 4,99,98,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व) (पूंजीगत)	1,000 1,94,59,31,888
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व) (पूंजीगत)	27,67,85,778 13,39,98,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	26,13,00,100

1	2		3
17	निर्वाचन	(राजस्व) (पूंजीगत)	34,34,01,619 2,00,00,000
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व) (पूंजीगत)	8,93,97,045 80,39,02,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व) (पूंजीगत)	92,45,37,496 92,48,39,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	4,21,72,03,977
21	सहकारिता	(राजस्व)	5,000
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	58,31,07,073
23	विद्युत विकास	(राजस्व) (पूंजीगत)	6,77,20,42,815 2,07,22,73,000
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व) (पूंजीगत)	2,33,72,15,000 5,95,07,17,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व) (पूंजीगत)	94,10,24,452 77,71,03,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व) (पूंजीगत)	61,66,07,284 2,41,00,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	(राजस्व) (पूंजीगत)	1,16,75,17,756 1,31,36,56,000
29	वित्त	(राजस्व) (पूंजीगत)	7,65,27,30,053 1,000
30	विविध सामान्य सेवाएँ	(राजस्व) (पूंजीगत)	22,10,42,915 44,98,59,000
31	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	(राजस्व) (पूंजीगत)	1,61,05,61,162 9,58,64,000
32	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	(राजस्व) (पूंजीगत)	4,07,97,06,325 86,07,84,960
	जोड़	**(राजस्व)** **(पूंजीगत)**	**39,86,70,73,033** **26,43,54,20,246**
	कुल जोड़		**66,30,24,93,279**

11.03.2025/1240/MD/AS/6

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर तीन में दर्शाई गई क्रमशः मु0 39,86,70,73,033/- रुपये एवं 26,43,54,20,246/- रुपये (कुल 66,30,24,93,279/-रुपये) की अतिरिक्त धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर तीन में दर्शाई गई क्रमशः मु0 39,86,70,73,033/- रुपये एवं 26,43,54,20,246/- रुपये (कुल 66,30,24,93,279/-रुपये) की अतिरिक्त धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं।

11.03.2025/1240/MD/AS/7

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित हुआ।

11.03.2025/1240/MD/AS/8

विचार एवं पारण

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

के0एस0 द्वारा जारी

11.03.2025/1245/केएस/एएस/1

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण :

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.03.2025/1250/av/dc/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 2) पारित हुआ।

11.03.2025/1250/av/dc/2

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा होगी। इस प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कुल चार दिन का समय निर्धारित है। माननीय मुख्य मंत्री इस चर्चा का उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2025 को देंगे। समय की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावक को 15 मिनट्स, अनुसमर्थन करने वाले को 10 मिनट्स और माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए 20 मिनट्स का समय निश्चित किया गया है, जबकि अन्य सदस्यों हेतु बोलने के लिए 5 से 10 मिनट का समय रहेगा। इसलिए जिन बिन्दुओं पर चर्चा हो चुकी हों उनको न दोहराएं।

अब माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एकत्रित सदस्य राज्यपाल महोदय का दिनांक 10 मार्च, 2025 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए :-

'इस सदन में एकत्रित सदस्य राज्यपाल महोदय का दिनांक 10 मार्च, 2025 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।'

अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी भाग लेंगे। उसके बाद माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे।

11.03.2025/1250/av/dc/3

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वह सरकार के लेखा-जोखा के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस सदन में हम जो भी 68 व्यक्ति हैं, हम सारे-के-सारे चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं और हमें जनप्रतिनिधि का दायित्व भली-भांति पता है। आप सभी सरकार का दायित्व भी जानते हैं क्योंकि सरकार किसी एक व्यक्ति, किसी एक क्षेत्र और किसी एक मज़हब की नहीं होती। सरकार का प्रथम दायित्व यह होता है कि वह सबसे पहले जन-कल्याण की योजनाओं की बात करे और जन-कल्याण की योजनाओं को समाज के हरेक तबके तक पहुचाएं। दूसरा, सरकार का यह दायित्व भी होता है कि प्रत्येक क्षेत्र का बिना किसी भेदभाव के विकास करे। इसके अतिरिक्त सरकार का कानून-व्यवस्था बनाए रखने का भी एक प्रमुख दायित्व होता है। उसके बाद सरकार का यह दायित्व भी बनता है कि वह समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए सोचे कि वह उसके लिए क्या-क्या कर सकती है। राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में जो-जो मुख्य बिन्दु उठाए गए वे सारे-के-सारे हमारी सरकार के कोर फोकस के रूप में बोले गए हैं। उसमें प्रमुख रूप से गवर्नेंस, लॉ एण्ड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन तथा ईकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए पॉलिसी बनाती है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि वह जनता है कौन, उसमें हम उनको जिस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारी ये 70 लाख के लगभग जनसंख्या जिसमें हमारे किसान-बागवान, छोटा व्यापारी, मनरेगा व दिहाड़ीदार मज़दूर, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सैक्टर में कार्य करने वाले व्यक्ति, पेंशनर्ज, गृहणियां इत्यादि आती हैं।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2025/1255/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री भवानी सिंह पठानिया ... जारी

हम इन सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए आज इस सदन में बैठे हुए हैं। सरकार का कुछ दिनों में जो बजट पेश होगा, सरकारी की जो पॉलिसी है और जिस तरह से सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसमें हिमाचल प्रदेश के वे सब लोग जिनको मैं आम हिमाचली बोलता हूं, उन सबका उत्थान केन्द्रित हैं। वर्ष 1970-80 के दशक में हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थितियां थीं, उस समय जो हमारी अपेक्षाएं थीं, वे अलग प्रकार की थीं। उस समय हमारे मुख्य मुद्दे ये होते थे कि गांव तक सड़क व पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा। सरकार शहर के लिए क्या बिजली उपलब्ध करवा पा रही है या नहीं करवा पा रही है लेकिन पिछले 30-40 सालों में लोग बदल गए, उनकी परिस्थितियां भी बदल गई। हमारे डवलपमैंट के पैरामीटर्ज बदल गए और आज का हिमाचली किसान, नौजवान और गृहिणियों की अपेक्षाएं वे नहीं हैं जो वर्ष 1980 के दशक में थीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हम वही कार्य करते आ रहे थे जो हमने वर्ष 1950, 1960, 1970 व 1980 के दशकों में किया। उस व्यवस्था की स्थिति उस गाड़ी की तरह ही थी, हम सब ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं और किसी-न-किसी के साथ यह एक बार अवश्य हुआ होगा। श्री चौधरी साहब जी के साथ तो कुछ समय पहले ही यह घटना हुई। जब गाड़ी किचड़ में फंस जाती है तो ड्राइवर एक्सीलेरेटर देता है। उससे गाड़ी के चक्के तो घूमते हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा पाती है। इसी तरह से पिछले कुछ सालों से सरकारें भी एक्सीलेरेटर दबाई जा रही है, गाड़ी किचड़ में फंसी हुई है, पहिए घूमते जा रहे हैं लेकिन हम वहीं-के-वहीं हैं जहां थे और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे होता यह है कि जब हम और ज्यादा एक्सीलेरेटर देते हैं तो उससे आसपास के लोग कीचड़ से लतपत हो जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक व्यवस्था जो एक समय के लिए बनी थी, उस व्यवस्था को अगर

हम आज भी उसी तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नही लगता कि हम हिमाचल प्रदेश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। जब हमारी सरकार बनी तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पार्टी ने चुना कि आप इस

11.03.2025/1255/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

सरकार का नेतृत्व करिए और उस मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठिए जिसको कभी बड़े-बड़े नेताओं ने सुशोभित किया था। मुख्य मंत्री जी ने आते ही सर्वप्रथम अपनी मंशा जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अब आप पूछेंगे कि यह व्यवस्था परिवर्तन क्या है? यह व्यवस्था परिवर्तन वही है अगर कोई और मुख्य मंत्री होता तो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता, सीट पर बैठता और उसी तरीके से एक्सीलेरेटर दबाता जिससे चक्के घूमते जाते लेकिन सरकार व प्रदेश आगे नहीं बढ़ता और न ही व गाड़ी आगे बढ़ती। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि अगर इस गाड़ी को गड्ढे से निकालना है तो हमें उन पैरामीटर्ज को बदलना है जिनकी वजह से हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जिन पैरामीटर्ज की वजह से आज कुछ लोग सुख भोग रहे हैं, जिनके लिए वह सिस्टम बना था, वे लोग इस सिस्टम को चेंज नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए जब भी कोई किसी व्यवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वह इंसान उसका विरोध करता है जो उसका उपभोग कर रहा होता है यानी जो उसका आन्नद ले रहा है और प्रदेश व सरकार का नुकसान करवा रहा है। आज हर उन सैक्टर्ज में सुधार हो रहा है जिसके बारे में पिछले 20-25 सालों से सोचा भी नही गया था। व्यवस्था परिवर्तन से उन लोगों को डर लगता है जिनकी कमाई इसके कारण से बाधित हो रही होती है। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इसकी परवाह न करके कुछेक पैरामीटर्ज में बदलाव किया है। हमारी सरकार ने समाज के सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए कार्य करना शुरू किया यानी अनाथ बच्चे और एकल नारी से इसकी शुरुआत की। मुख्य मंत्री जी शपथ लेने के बाद अपने ऑफिस गए और वहां से बालिका आश्रम गए। उसके पश्चात् मुख्य मंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई। उससे अनाथ बच्चों जिनके माता-पिता या भरण-पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था यानी जिन बच्चों को यह लगता था कि उनका कोई भविष्य नहीं है उनका भविष्य और उनके माता-पिता बनकर आज सरकार खड़ी हो गई है।

एन0एस0 द्वारा.... जारी ।

11-03-2025/1300/ns-hk/1

श्री भवानी सिंह पठानिया.....जारी

यह बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का तहेदिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा कि आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, देखते भी हैं लेकिन उसके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करते। एकल नारी यानी जिसका परिवार में आगे-पीछे कोई नहीं है उसको घर बनाने के लिए आपने जो व्यवस्था की है, वह बड़ी काबिले तारीफ व्यवस्था है। समाज के ऐसे तबके जिनके बारे में कोई नहीं सोचता था उनके लिए आपने सबसे पहले सोचा। पहला तबका एकल नारी, दूसरा, अनाथ व बेसहारा लोग और तीसरा तबका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए है और उसमें मैंने पहले भी कहा है कि हमारे किसान व बागवान शामिल हैं। सरकार ने किसान व बागवान को केंद्र बिन्दु बना करके जो कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। सबसे पहले अगर दूध की बात की जाए तो दूध के मूल्य में 15 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। यह ऐतिहासिक वृद्धि है और आज तक किसी भी सरकार ने यह वृद्धि नहीं की है। अगर आपने इसका इम्पैक्ट देखना है तो आनी व बन्जार में जाकर देखें। वहां कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं हैं लेकिन आपको वहां पता चलेगा कि वहां पर जो भी पशुपालक, गाय पालक और दुग्ध जीव पालक थे उन लोगों की जिंदगी 180 डिग्री के ऊपर टर्न कर गई है क्योंकि उनकी कमाई में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है जो आज से पहले नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए दो कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैविक व प्राकृतिक खेती में जो भी व्यक्ति गेहूं उगाता है तो सरकार उसको 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से समर्थन मूल्य देगी और अगर मक्की उगाता है तो उसको 30 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य देगी। यह बात केवल हम बोलते ही नहीं हैं बल्कि इस वर्ष जो मक्की की फसल हुई है उसको हम प्रोक्योर भी कर चुके हैं। सरकार ने प्रोक्योरमैंट के बाद उसका आटा बना कर एज प्राकृतिक खेती का आटा बेचना भी शुरू कर दिया है। हम

हमेशा यह कहावत बोलते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह मोर नाचा भी है और हमने देखा भी है। प्रोक्योरमैंट शुरू हो गई और उसका आटा बना करके उपभोक्ताओं के घर पहुंच गया है।

हमारे बागवानों के लिए पिछले वर्ष एक यूनिवर्सल कार्टन की स्कीम शुरू हुई थी। प्रदेश के चार जिले ऐसे हैं और उन जिलों की मुख्य अर्थव्यवस्था सेब पर निर्धारित है। उनमें शिमला,

11-03-2025/1300/ns-hk/2

कुल्लू, मण्डी और कुछ भाग सिरमौर का है। अगर आप वहां के लोगों को पूछें कि इस बार की प्रोक्योरमैंट में क्या आढ़ती शोषण कर पाए जैसा वे पहले करते थे? उनका जवाब यही होगा कि इस दफ़ा पहली बार ऐसा हुआ कि उस प्रकार से शोषण नहीं हो पाया। क्योंकि पेटी का मतलब 24 किलो सेब है और इस बार उसी हिसाब से सेब बिका है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी व बागवानी मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जो यूनिवर्सल कार्टन का कार्य किया है, यह काबिले तारीफ एक पहल है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मनरेगा की दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं और जब हम सुबह अपने घर या दफ्तर में बैठे होते हैं तो लोग हमसे मिलने आते हैं। आप यह देखिए कि जो व्यक्ति हमारे पास शिकायत लेकर आ रहा है उसकी जरूरतें क्या हैं? उसकी पहली जरूरत यह होती है कि मेरी सड़क बननी है, मेरा डंगा लगना है या मेरी तबादला होना है। अगर आपसे 100 व्यक्ति मिलते हैं तो आज से दो साल पहले की स्थिति यह थी कि मेरे पास लगभग 30 प्रतिशत लोग राजस्व मामलों को लेकर आते थे कि हमारा इंतकाल, तकसीम, निशानदेही नहीं हो रही है या हमें पटवारी तंग कर रहा है, हमें कानूनगो टाइम नहीं दे रहा है। आज अगर देखें तो हमारे पास कोई भी इंतकाल का केस नहीं आता है क्योंकि मेरे हिसाब से यह सरकार अपनी राजस्व अदालतों के माध्यम 1 लाख से ज्यादा इंतकाल एक वर्ष के अंदर खत्म कर चुकी है। ...(व्यवधान) राजस्व के मामलों में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य हुआ है क्योंकि सरकार ने इंतकार व म्यूटेशन के केसिज में बैकलॉग क्लीयर किया है और यह काबिले तारीफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ केयर की बात करना चाहूंगा। हैल्थ केयर में व्यवस्था कैसी थी? हम यही कहते थे कि पैडल दबाने वाली बात है।

आर0के0एस0 द्वारा----- जारी

11.03.2025/1305/RKS/एचके-1

श्री भवानी सिंह पठानिया... जारी

हम यही कहते थे कि जनता रो रही है तो क्या करें? पैडल दबाओ, टायर को घुमाओ, कीचड़ उछालो। आप स्कूल तो खोल सकते हैं लेकिन वहां पर टीचर्स की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब आप डिस्पेंसरी या कॉलेज खोलते हैं तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ डॉक्टर्ज और प्रोफेसर्ज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप अनेकों संस्थान खोल रहे हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या वास्तव में उन संस्थानों से जनता को कोई वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं। आपने जो 900 संस्थान खोले थे, 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, महिलाओं का सफर फ्री किया था, अगर इन योजनाओं के साथ जनता का हित जुड़ा होता तो आप शायद इस तरफ बैठते। लेकिन जनता को यह अहसास था कि उनका हित इन योजनाओं के साथ नहीं जुड़ा है इसलिए आप वहां बैठे हैं और हम यहां बैठकर जनता को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के पीछे हमारी सोच क्या है? हमारी सोच यह है कि छोटी-छोटी डिस्पेंसरी के बजाय एक बड़ा और समर्पित हॉस्पिटल बनाना ज्यादा प्रभावी हो सकता है जिसमें सभी जरूरी विशेषज्ञ, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गाइनेकोलॉजिस्ट और अन्य डॉक्टर मौजूद हों ताकि मरीज को कहीं और रेफर करने की जरूरत न पड़े। इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब हर निर्वाचन क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान तैयार हो रहा है। चाहे वहां कांग्रेस का विधायक हो या बीजेपी का, ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनकर रहेंगे। क्योंकि जनता न तो कांग्रेस पार्टी की है, न बीजेपी की, जनता हिमाचल प्रदेश की है और यह सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता का सर्वांगीण विकास करने में विश्वास रखती है।

इसके बाद दूसरा कदम मेडिकल कॉलेज कैडर का है। अगर फतेहपुर चुनाव विधान सभा में काम करने वाले व्यक्ति की अगर शिमला या किसी अन्य जगह पोस्टिंग की जाती है तो वह तीन महीने बाद डी.ओ.लगाकर कहीं ओर एडजस्टमेंट ले लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 5 या 6 जगह ही डॉक्टर्ज तैनात किए जाते थे और वे ऐसी जगह होती थी जहां के लोगों ने पुण्य किए होते थे तभी उनके क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टर्ज की सेवाएं उपलब्ध होती होगी। पहले वे ही लोग अपना इलाज आसानी से करवा सकते थे लेकिन इस व्यवस्था को ठीक करना बहुत जरूरी थी। अब जो मेडिकल कॉलेज कैडर और दूसरा कैडर बन रहा है

11.03.2025/1305/RKS/एचके-2

इससे डॉक्टर्ज की उपलब्धता हर जगह होने वाली है। मैं कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में जनता और नेताओं को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी उन्हें है जो एक ही जगह पर 20-25 साल से बैठे हुए हैं और अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी सेवा प्रदेश की जनता को मिल पाए। यह व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य है। वर्ष 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में हुए सर्वे की रिपोर्ट इस वर्ष आई है। हम रीडिंग में पूरे देश में 28 में से 21वें स्थान पर हैं। इसका कारण यह है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ संस्थान खोलना नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए।

आज श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगवाई में यह निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले स्कूलों की कंसोलिडेशन की जाए। जहां कम छात्र हैं वहां छात्रों को उन स्कूलों में ले जाया जाए जहां हम उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। इसके लिए जनता में कोई रोष नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ स्कूल बंद हुए हैं। मैंने वहां की जनता से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि यह कदम सही है क्योंकि जब हम अपने बच्चों का इन स्कूलों में दाखिला ही नहीं करवाते तो इन स्कूलों को खोलने का क्या फायदा है? जिन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे ज्यादातर बिहार या छत्तीसगढ़ से आए मजदूरों के बच्चे हैं और वे भी दो या तीन ही बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज हालत यह है कि जो प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है यानी जो शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहा है वह उस स्कूल में अपने बच्चे को

नहीं पढ़ाता क्योंकि उसे यह पता नहीं होता कि कल को उसे कहां फैंक देना है। जब मुझे यही पता नहीं कि बाकी अध्यापक मेरे बच्चे को किस तरीके से पढाएंगे तो मैं किसी ओर को कैसे कंविंस करूंगा कि आप अपने बच्चे को मेरे पास लाकर पढ़ाओ। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम रेशनलाइजेशन का प्रोसैस चला रहे हैं जो एक मील का पत्थर साबित होगा।जब वर्ष 1991-92 में स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन की नीतियों को लागू किया था तब इसका विरोध हुआ था। जो आज सत्ता में हैं, वे उस समय विपक्ष में थे। वे बैलगाड़ियों में आकर सड़कों पर लेट गए थे। लेकिन जो गाइडलाइंस उन्होंने बनाई थी, आज हर कोई उसे आंख मूंदकर फॉलो कर रहा है। वह भी एक व्यवस्था परिवर्तन था। लोग चीखते-चिल्लाते थे लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसमें अडिग हूं।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

11.03.2025/1310/बी.एस./एच.के./-1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी...

उन्होंने कहा कि मैं इस पर अडिग हूं और जो हमारा हिन्दुस्तान है इसका भविष्य तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम इस नीति को फोलो करेंगे। मैं उसी मूवमैंट को आज देख रहा हूं। जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा आदरणीय मुख्य मंत्री जी का है वह साकार होगा। आज भी लोग प्रोटैस्ट कर रहे हैं। परंतु आज से 2-3 या 4 साल बाद इस दिन को देख करके लोग याद करेंगे कि उस दिन इस व्यक्ति ने अपना निर्णय लिया था और किसी से डरा नहीं उसकी वजह से ही आज हिमाचल आर्थिक बदहाली से निकल कर पावर हाउस स्टेट बन चुका है। आप देखिए दो-तीन साल में आपको इसके परिणाम मिल जाएंगे।

इसके बाद आप देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल अगले दो सालों में बन करके तैयार होंगे। मुख्य मंत्री जी की तरफ से मैं कमिट करता हूं और उसके अन्दर जो शिक्षा है, उसे ग्रहण करने के लिए खुद लोग वहां पर पढ़ने के लिए आएंगे। आप ऐसे ही हंसे थे और ऐसे ही हंसोगे। आप वर्ष 2027 में भी यहीं पर बैठ करके ऐसे ही हंसोगे, आज मैं आपको यह बता देता हूं। आप के पास वे लोग आते हैं जो त्रस्त होते हैं, आपके पास

वह ठेकेदार आते हैं जो अन्य पॉलिसी में आ गए हैं और आपके पास वह कर्मचारी आतें हैं जो 20-25 साल से एक ही स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि यह जनता की आवाज है। परंतु यह जनता की आवाज नहीं है। आज जनता के बीच में जा करके देखिए जनता दुःखी नहीं है।

श्री विनोद कुमार : माननीय सदस्य, जनता के बीच में जा करके देखिए।

श्री भवानी सिंह पठानिया : सर, मैं तो रोज ही जनता के बीच में होता हूं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें 900 नई बसें आ रही हैं। इनमें से 300 इलैक्ट्रिक बसें हैं और बाकी की दूसरी बसें हैं। पहली बार इतिहास में टैंपो ट्रैवलर से ले करके छोटी बसों के 350-400 नये रूट्स आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जिन गांव पर आज तक बस नहीं जाती थी उन रूट्स के अंदर बस पहुंचाने का दायित्व परिवहन मंत्री जी ने लिया है, यह व्यवस्था परिवर्तन है।

11.03.2025/1310/बी.एस./एच.के./-2

परवाणू से ले करके शिमला तक की रोपवे की स्कीम लगभग 9,000 करोड़ रुपये की है और अन्य स्थानों पर भी प्रस्तावित है, ये व्यवस्था परिवर्तन हैं। जहां पर आप ऑल्ट्रनेट ट्रांसपोर्ट स्कीम की बात कर रहे हैं, आप यह नहीं बोल रहे हैं कि सड़क यदि टूट गई है तो वहां पर कोई पुल/फ्लाइओवर बना दो। परंतु अल्ट्रनेट ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत यह सब बनने वाले हैं, यह व्यवस्था परिवर्तन है।

इसके अलावा हमारे एच0पी0एस0ई0बी0एन0एल0 के बिजली बोर्ड के प्रोजैक्ट्स हैं। यदि हम देखें तो यह हमारा आय का साधन होना चाहिए था और एक कमाऊ पूत होना चाहिए था। जिसके जोर पर हम कहते कि साल का 2,000 या 3,000 करोड़ रुपये इससे प्रॉफिट आ रहा है। आज बिजली बोर्ड की हालत यह है कि सरकार 2200 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में उसको देती है और 2200 करोड़ रुपये में यदि 75 लाख रुपये की लागत में एक ट्यूबवेल बनता है तो हम हर एक चुनाव क्षेत्र में 60 ट्यूबवेल लगा सकते थे। इस 2200 करोड़ रुपये में से अगर 30 करोड़ रुपये में एक अस्पताल की बिल्डिंग बनती तो हर चुनाव क्षेत्र में हम एक सिविल अस्पताल खोल सकते थे। हमें सीधा 2200 करोड़ रुपये का

नुकसान हो रहा है और यह नुकसान इसलिए हो रहा है कि हमने इसे जमा होने दिया। ट्राइफरकेशन हुई, उसका क्या मतलब था; क्या उस समय के हिसाब से उसकी जरूरत थी? परंतु आज आप देखिए, आज जो हमारे पास मैन पावर है और जो जनसंख्या है यह टोप पर बैठी हुई है और जहां पर मुझे 5-6 या 7 हजार लोग काम करने के लिए चाहिए वे नहीं मिल रहे हैं। मुझे टी मेट्स और ए0एल0एम0 चाहिए उन्हें मैं वहां पर हायर नहीं कर पा रहा हूं। हम इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वे लोग हल्ला मचाते हैं। जो इस व्यवस्था को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। आज से चार या पांच दिन पहले हमारी फतेहपुर के अन्तर्गत गोलुआं पंचायत है वहां एक लाइन मैन, 31 साल का लड़का खम्भे पर चढ़ा हुआ था उसे करंट लग गया और वह खम्भे के ऊपर ही मर गया। उसके बाद आप देखिए कि वे ही यूनियनें विरोध कर रही हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है। जो युनियनें विरोध कर रही है कि आप कंसोलिडेशन क्यों कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे खम्भों पर लटक कर इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है। मैन पावर की

कमी को हम तब पूरा कर सकते हैं जब टोप को हटाएं और टोप को हटाने के बाद जो बोटम में हमारे पास सात-आठ हजार लोगों को हमें हायर करना है उन्हें अगले दो-तीन साल में हायर करें और जो हमारी इलैक्ट्रिसिटी की व्यवस्था पहले थी उसे उसी तरीके की सर्विस ले करके जाएं। मैं चाहता हूं कि 2200 करोड़ रुपये की सब्सिडी रुके। हम उन्हे 2200 करोड़ रुपये की सब्सिडी देते हैं यह कहां और कैसे यूज हो रहे हैं? मैं कहता हूं कि इन्डस्ट्री तो ठीक है परंतु हमने होटल इन्डस्ट्री को भी एक रुपये की सब्सिडी दी हुई है। हमने ऐसी फालतू की सब्सिडियां उन लोगों को दी हुई हैं जिन्हें शायद सब्सिडी की जरूरत नहीं है। हमारा यह मानना है कि सब्सिडी उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है। जो बी0पी0एल0 परिवार हैं, उन्हें 300 क्यों, उन्हें 500 यूनिट्स तक सब्सिडी दीजिए। परंतु जो साधन संपन्न परिवार हैं उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि पहले फेज के अन्दर सभी माननीय विधायकों ने सब्सिडी छोड़ी और क्लास-I, क्लास-II अधिकारियों ने भी स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ी।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

11.03.2025/1315/डीटी/वाई0के0/1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी...

लेकिन सरकार ने समाज के कमजोर व गरीब तबके की सब्सिडी को हाथ नहीं लगाया। बोलने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्था परिवर्तन में एच.पी.एस.बी.एल. जब दो साल बाद प्रोफिट मेकिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा तब आप बोलेंगे कि हां जो आप उस समय कर रहे थे वो ठीक था लेकिन आज आप इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आपका नाम ही विपक्ष है। इसके अलावा व्यवस्था परिवर्तन के साथ पिछले दो साल में 2600 करोड़ के रेवन्यू की वृद्धि इस सरकार में हमारे मुख्य मंत्री जी के प्रयासों की वजह से हुई है। मिल्क सेस, वैट, माईनिंग लीज, लिक्कर वेंड का ऑक्शन जो पूर्व सरकार ने पांच साल नहीं करवाया, वह वर्तमान सरकार ने करवाया और सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करवाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है।

हमारे विपक्ष के नेता मीडिया के पास जाते हैं और मीडिया इनकी उसी तरह से ख़बर लगाता है जैसा ये चाहते हैं और आज मुझे पता चला कि ये शायद पैसा देकर ख़बर लगवाते हैं क्योंकि ये सोच रहे है कि हम ख़बर कुछ इस तरह से लगाएं कि केंद्र की सहायता प्रदेश सरकार को न मिले। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को पैसा न दे और प्रदेश में वर्तमान सरकार न चले। ...(व्यवधान) मेरा सवाल यह है कि क्या केंद्र यह पैसा अपने घर से लाता है। हमे केंद्र सरकार कहा से पैसा देती है? विपक्ष ऐसी बातें कैसे करता है कि अगर केंद्र सरकार सहायता न करे तो प्रदेश सरकार कॉलेप्स हो जाएगी। केंद्र का पैसा हमारा पैसा है और हमारा पैसा-हमारा पैसा है,केंद्र का पैसा नहीं है। वह पैसा हिमाचल की जनता का पैसा है। वह पैसा हमारा है। वह प्रदेश के गरीब किसान के द्वारा दी गई जी.एस.टी. का पैसा है जो केंद्र के पास पड़ा हुआ है और वही पैसा वह हमें देते हैं। इसपर आप अहसान मत जताओ। आप एक अच्छे विपक्ष का काम नहीं कर रहे। मैं प्रदेश की इस आर्थिक स्थिति का गुनहगार विपक्ष को मानता हूं and I will prove it to you. मैं आपको

साबित करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको बताता हूं रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट जब शुरु हुई थी तो रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट इसलिए मिली थी i.e. in lieu of the revenue जो फॉल करेगा। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ये ग्रांट 11431 करोड़ थी और उस समय आपकी सरकार सत्तासीन थी।

11.03.2025/1315/डीटी/वाई0के0/2

इसके बाद 10249 करोड़ रुपये की ग्रांट आई और उस समय भी आपकी सरकार थी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 9337 करोड़ रुपये की ग्रांट आई, उस समय भी आपकी सरकार थी। आपको पता था कि यह रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट है और 6 साल में ये ग्रांट 3000 करोड में पहुंच जाएगी। मतलब 8000 करोड़ रुपये तक ये ग्रांट कम होगी। आप मुझे ये बताइए कि आपके पांच साल में इस 8000 करोड़ रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट को काम्पन्सेट करने के लिए आपने किया क्या; अगर नहीं क्या तो क्यों नहीं किया? अगर वित्तीय वर्ष 2020-2021 में इस रेवन्यू को ऑफ्सेट करने के प्रयास आपने किए होते तो जो व्यवस्था परिवर्तन आज मुख्य मंत्री महोदय कर रहे हैं वह नहीं करना पड़ता और अगर वही प्रयास आपने अपने समय में किए होते तो आज प्रदेश की ये हालत नहीं होती। हिमाचल प्रदेश के लिए आप 8000 करोड़ रुपये का एक खड्डा क्रिऐट करके गए हो। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना।

Shri Bhawani Singh Pathania : ...(Interruption) Let me speak. ...(Interruption) This is not fair. ...(Interruption) Sir, I am not yeilding. ...(Interruption) 8000 करोड़ है कि नहीं है ...(व्यवधान) 11431 करोड़ का 3200 करोड़ 8000 करोड़ रुपये का डिप है। ...(व्यवधान) मैंने कोई नाम नहीं लिया है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कोई नाम नहीं लिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी लंच के बाद आपको ही बोलने का अवसर मिलेगा। ...(व्यवधान)

Shri Bhawani Singh Pathania : I am not yeilding. ...(व्यवधान) सर, मैं साल में एक बार ही बोलता हूं और आप मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) सर, आप हर रोज बोलते हैं। आप प्रश्न काल के पहले और बीच में बोलते रहते हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कृपया बैठ जाइए और माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी बात रखने दें।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र परिस्थिति बनी है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

11.03.2025/1320/ए.जी.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री.....जारी

वे राजस्व घाटा अनुदान के बारे में बता रहे हैं कि आपकी (श्री जय राम ठाकुर की ओर देखते हुए) सरकार जिम्मेवार है। यदि उस पर कोई क्लैरिफिकेशन देनी है तो अभी हमारी ओर से मेन स्पीकर बोल रहे हैं और उसके बाद आप (उपाध्यक्ष की ओर देखते हुए) इन्हें बोलने का मौका दे दीजिएगा। बेशक लंच को 5-7 मिनट बाद कर दीजिए और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लंच के बाद इनकी स्पीच दोबारा से करवा दीजिएगा। लेकिन ये गलत बात है और आपका ये ट्रेंड बन चुका है कि जब हमारी ओर से कोई बोलता है तो आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे वक्ता के बाद माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी को बोलने की अनुमति दे दी जाए।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने विपक्ष के नेता का दो बार नाम लिया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : इन्होंने नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान) ठीक है। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फाइनैंस बैकग्राऊंड से हैं। मैं समझता था कि फाइनैंस बैकग्राऊंड होने के कारण ये फैक्ट्स पर ठीक प्रकार से बोलेंगे। इनको जानकारी होनी चाहिए थी कि जब कोई वित्तायोग आता है तो वह केवल हिमाचल प्रदेश या देश के किसी एक प्रदेश के लिए नहीं आता है बल्कि वह वित्तायोग तो पूरे देश के लिए आता है। 15वें वित्तायोग की सिफ़ारिशें तो पूरे देश भर के लिए आई थीं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राजस्व घाटा अनुदान को पूरे देश में टेपर डाउन किया जाएगा। उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान हर साल घटता चला गया। इसमें कोई भी नई बात नहीं है।

11.03.2025/1320/ए.जी.-एन.जी./2

अब केवल एक ही बात को लेकर बात है कि जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता हासिल करनी थी तो उस वक्त आप (माननीय मुख्य मंत्री की ओर देखते हुए) भी इस माननीय सदन में थे और आप (माननीय उप-मुख्य मंत्री की ओर देखते हुए) भी इस माननीय सदन में थे। हमारी सरकार के समय में अनेकों बार राजस्व घाटा अनुदान के संदर्भ में चर्चा हुई थी और उस समय हमने कहा था कि यह हमारे लिए चिंता का विषय होगा। वर्तमान सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सत्ता में आने से पहले आपकी पार्टी ने जो गारंटियां दी थीं तो क्या उस समय आपको यह इल्म नहीं हुआ था? क्या आपको उस समय यह सब ध्यान में नहीं आया था? आपने उस समय ऐसी गारंटियां क्यों दी थीं? पिछले कल तेलंगाना के माननीय मुख्य मंत्री, जोकि कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित हैं, ने कहा है कि 'सरकार में आने के बाद मेरी गलतफहमी दूर हो गई है कि जो गारंटियां दी गई हैं वे कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। यदि मुझे पहले पता होता तो शायद यह नहीं होता।' क्या आपको (माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर देखते हुए) यह जानकारी नहीं थी? आप गारंटियों का वायदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 गारंटियां पूरी कर दी गई हैं। क्या आपको हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी? आप (माननीय मुख्य

मंत्री की ओर देखते हुए) भी इसी सदन में मौजूद थे और माननीय उप-मुख्य मंत्री, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे। आप सब को प्रदेश के हालात मालूम थे। लेकिन वर्तमान सरकार के दो साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद हमारा प्रदेश बर्बाद हो चुका है और यह सब हमारी आंखों के सामने हुआ है। इस सबके लिए केवल वर्तमान सरकार दोषी है न कि पिछली सरकार।

Smt PB द्वारा जारी--

11.03.2025/1320/ए.जी.-एन.जी./3

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भवानी सिंह पठानिया जी, आप बोलिए।

श्री भवानी सिंह पठानिया : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि इन्होंने पहले ही बोल दिया नहीं तो मुझे इनका उत्तर देने के लिए बाद में बोलने की अनुमति नहीं मिलनी थी। इन्होंने बोला कि राजस्व घाटा अनुदान ने टेपर करना था, मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि 11400 करोड़ रुपये ने 3000 करोड़ रुपये पर आ जाना था और यह सब आपको भी पता था। इस 8000 करोड़ रुपये के गैप को भरने के लिए जो स्टैप्स वर्ष 2020-21 में लेने चाहिएं थे वे आपकी सरकार ने नहीं लिए। यदि आप पॉजिटिव स्टैप्स लेते तो आज हमारा राजस्व बढ़ता और शायद आज हमारी यह हालत नहीं होती। मैं भी तो यही बोल रहा हूं और Thank you for endorsing me. आपने भी वही बात बोली है जो मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे खड्डे के बारे में बताना चाहता हूं जोकि जी0एस0टी0 से संबंधित है। जी0एस0टी0 कंपनसेशन वर्ष 2022 में पूर्व सरकार के समय में समाप्त होनी थी। वह कंपनसेशन पूर्व सरकार से पहले शुरू हुई होगी और इनकी सरकार में पूरे पांच साल वह कंपनसेशन मिलती रही। जी0एस0टी0 के तहत हर साल 3200 करोड़ रुपये मिलते थे और राजस्व घाटा अनुदान इसके अतिरिक्त था। जी0एस0टी0 कंपनसेशन अब शून्य हो गया है। पूर्व सरकार को मालूम था कि वर्ष 2023 में राजस्व घाटा अनुदान के तहत लगभग 8000 करोड़ रुपये और जी0एस0टी0 कंपनसेशन का लगभग 3200 करोड़ रुपये कम होने वाले हैं। पूर्व सरकार को पता था कि हिमाचल प्रदेश की जनता को वर्ष 2023 से 11120 करोड़ रुपये का घाटा झेलना पड़ेगा। उस समय पूर्व सरकार ने प्रोएक्टिव स्टैप्स

क्यों नहीं लिए? पूर्व सरकार ने स्कूल्ज़ खोलने से पहले क्यों नहीं सोचा की इनका पैसा कहां से आएगा? इन्होंने चुनाव जीतने के लिए ऐसे निर्णय क्यों लिए जिसकी व्यवस्था न की जा सके? उस समय इन्होंने ऐसे drastic steps क्यों नहीं लिए जिससे हिमाचल प्रदेश को नई दिशा मिलती और यहां-यहां से राजस्व एकत्रित किया जाएगा।...(व्यवधान) अभी मैं गारंटियों पर नहीं आया हूं। मैं हर चीज़ पर बात करूंगा।मेरा सवाल यह है कि पूर्व सरकार ने 11200 करोड़ रुपये का प्रावधान क्यों नहीं किया? यदि पूर्व सरकार के पास इतना पैसा था तो ये छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान ही कर देते। आज हमारे पास यह पैसा नहीं है। यदि इनके पास था तो ये छठे वेतन आयोग का एरियर दे सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने वे देनदारियां हमारे ऊपर ट्रांसफर कर दी।

11.03.2025/1325/पी0बी0/ए0जी0/-1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी...

इसके बाद हमारे पर दो और बेड़ियां डाली गई। हमारा ओ0पी0एस0 का चुनावी वादा था। मैं गारंटी की बात कर रहा हूं। हमने हिमाचल की जनता को ओ0पी0एस0 दी। हमारे प्रदेश के उस कर्मठ कर्मचारी को जो प्रदेश को बनाने में जिनका योगदान रहा है। केन्द्र सरकार ने क्या किया कि हमारी उधार लेने की सीमा को 1600 करोड़ रुपये से कम कर दिया। सर इसको भी आप साथ में जोड़िए।...(व्यवधान)। आप अपने लोगों को आर्थिक सुरक्षा दे रहे हो जिन्होंने हिमाचल को बनाया। इसके लिए हम आपको पीनेलाइज़ करेंगे और आपको 1,600 करोड़ रुपये कम देंगे। 11,200 करोड़ रुपये जमा 1600 करोड़ रुपये मोटा-मोटा 14,000 करोड़ के आसपास का हमारा यह खड्डा बन जाता है। इसके बाद एक और है कि सदी की सबसे भयंकर आपदा आई। सदी की इसलिए बोलूंगा कि इससे पहले 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था। आपदा में बहुत सारे लोग मरे और कई लोग शहीद हुए। राज्य ने 4,500 करोड़ रुपये अपनी किटी से रिलीफ फण्डज़ में डाला। केन्द्र की टीम आई और उसने आकर पोस्ट डिजास्टर एसेस्मैंट किया और उसमें बोला कि हां इनका जो नुकसान है यह 10,000 करोड़ रुपये का हुआ है और इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। आज इस बात को एक साल से ज्यादा बीत गया। यह पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला। इसको भी अगर में खड्डे के साथ जोड़ दूं तो हिमाचल प्रदेश के लिए 24,000 रुपये करोड़ का यह खड्डा तैयार हो गया है। पांचवीं चीज़, जब ओ0पी0एस0 लागू हुई तो उसमें जो अंशदान था

और जो राज्य का शेयर था,वह 10,000 करोड़ रुपये का जो यह एन0पी0एस0 का पैसा है यह केन्द्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। ये केन्द्र सरकार से ड्रिवन जो फण्डज़ हैं उनके पास पड़ा है और यह शेयर मार्केट में लगा है। इसे भी अगर मैं जोड़ लूं तो लगभग 35,000 करोड़ रुपये के आसपास हिमाचल प्रदेश की सम्पदा जो हक से हमारी है हमें वह नहीं दी जा रही और फिर यह बोलते हैं कि केन्द्र पैसा न दे तो सरकार नहीं चलेगी। हमारा बजट है बी0बी0एम0 अब जोड़ लीजिए, मैं तो सिर्फ बड़ी-बड़ी राशि बोल रहा हूं। आप या तो इसे मिटिगेट करते या आप कुछ ऐसा करते जिससे मेरा रेवेन्यू बढ़ जाता। मेरा आखिरी प्वाइंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे दो केन्द्र बिन्दु हैं एक राज्य और दूसरा केन्द्र है। हमारे राज्य में 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं। हम उनको रिप्रेज़ेट करते है। हम जनप्रतिनिधि है और जनता की आवाज़ सदन में उठाते हैं। विपक्ष के पास सात एम0पीज़0 है, चार लोक सभा के सदस्य और दो राज्य सभा में चुन कर के आए। एक इन्होंने सिक्का उछाल कर जो चुनवाया... (व्यवधान)

11.03.2025/1325/पी0बी0/ए0जी0/-2

वह टॉस था, पैसा उछाला, पैसा उछला टॉस हुआ और उसमें हैड-टेल में जीत गए।...(व्यवधान)। हमारे कुल सात लोग लोक सभा और राज्य सभा में हैं। आप मुझे बताइए कि जो भी मैंने चार या पांच चीज़ें बोली है इनके ऊपर वे कब ज्ञापन लेकर गए। इनके ऊपर कब उन्होंने लोक सभा के अंदर ऐसे खड़े होकर बात की है कि हिमाचल प्रदेश का हक मर रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता सफर कर रही है क्योंकि केन्द्र ने उनकी तरफ एक सौतेला व्यवहार अपनाया हुआ है। अब मैं अपको बताना चाहता हूं कि कब उन्होंने बोला है। पी0डी0एन0ए0 का 10,000 करोड़ रुपये का जो पैसा है इसके लिए मैं इनसे यह अनुरोध करूंगा कि आप एक बार ज्ञापन बनांए और ज्ञापन बनाकर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को दें, तो सही होगा। आप गृह मंत्री जी को दीजिए तो भी सही है कि हमारे हक की कमाई है और यह हमारा पैसा है। आप इसको क्यों नहीं दे रहे? मैं यह बोल चाहता हूं कि हम जनता के और अपने विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। मेरा दायरा इस सदन तक है मैं यहां पर अपनी आवाज़ उठाता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने चुन के अपने जिले से भेजा है इसकी बात करना क्या उनका दायित्व नहीं है? क्या उसकी बात करना भारतीय जनता पार्टी के एम0पीज़0 का दायित्व नहीं बनता? अगर ये बात नहीं कर रहे तो ये क्यों नहीं कर रहे? सवाल तो यह आता है कि जब पता है कि वह पैसा हमारा है आप

उसकी रिप्रेज़ेंटेशन क्यों नहीं देते? पी0डी0एन0ए0 अलावा दूसरी चीज़ कर्मचारी अंशदान मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 10,000 करोड़ रुपये एच0डी0एफ0सी0, आई0सी0आई0सी0आई0 इत्यादि फण्ड हाउसिज़ के पास पड़ा है। जब पैंशन मैं देने वाला हूं, जब ओलड पैंशन स्कीम मैंने पहले ही अनाउंस कर दी है ये पैसे का वहां रखने का क्या औचित्य है। इस पैसे को आप राज्य को वापिस क्यों नहीं करते? यह वही पैसा है अगर ये राज्य के पास वापिस आ जाए तो जितने भी एरियर हैं हम सारे के सारे वापिस दे सकते हैं। इसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इसके लिए किसी भी एम0पी0 ने आज तक लोक सभा में क्यों नहीं बोला कि यह पैसा हिमाचल की जनता का है, हिमाचल के कर्मचारी का है आप हिमाचलियों को वापिस करो? आप नहीं बोलते है।...(व्यवधान) परंतु individual का पैसा है पैंशन के लिए...(व्यवधान) मैं आपको अपनी फाइनेंस पृष्ठभूमि बता देता हूं एन0पी0एस0 प्रोडक्ट का जब डिज़ाइन हुआ था मैं उसी कंपनी में काम करता था।...(व्यवधान) हमारा पैसा नहीं है, कर्मचारियों ने पैंशन के लिए पैसा दिया था।...(व्यवधान)

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

11.03.2025/1330/A.P./A.S./01

श्री भवानी सिंह पठानिया द्वारा जारी.....

जब पेंशन देने वाला हूं, ओ0पी0एस0 स्कीम मैंने अनाउंस कर दी है, तो इस पैसे का वहां रखने का क्या औचित्य बनता है। इस पैसे को आप स्टेट को वापिस क्यों नहीं करते? ये वही पैसे हैं अगर ये स्टेट के पास वापिस आ जाएं तो जितने भी एरियर्स हैं हम सारे-के-सारे वापिस दे सकते हैं। इसके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते? इसके लिए किसी भी एम0पी0 ने आज तक लोकसभा के अंदर क्यों नहीं बोला की यह पैसा हिमाचल की जनता का है, हिमाचल के कर्मचारियों का पैसा है, आप उन्हें वापिस करो। यह कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं है। सर, मैं आपको फाइनैंस बैकग्राउंड बता देता हूं। एन0पी0एस0 प्रोडक्ट का जब डिज़ाइन हुआ था तब मैं उसी कंपनी में काम करता था।...(व्यवधान)

सर, हमारा पैसा नहीं है, कर्मचारी ने पैसा दिया था पेंशन के लिए। सर, कर्मचारियों ने पैसा तब दिया था जब माननीय श्री अटल बिहारी जी ने उनका पेंशन का हक छीन लिया था, अब हमने उन्हें वह हक वापिस किया है।...(व्यवधान)

सर, मैंने पहले ही कहा था, सच कडवा होता है। जिन कर्मचारियों ने अंशदान दिया है आप उनके हित में आवाज उठाएं और उनका पैसा केन्द्र सरकार से वापिस लेकर आएं। मैं जानता हूं कि आप नहीं ला पाएंगे लेकिन आप आवाज तो उठाइए। हमारे प्रदेश की एक माननीय एम0पी0 जब आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि हमारी फिल्म रलीज हो रही है उसे देख लीजिए।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि वैश्विक राजनीति में एक परिवर्तन आया है। श्री डोनाल्ड ट्रंप यू0एस0ए0 के राष्ट्रपति बन गये हैं। वे हमारे प्रधानमंत्री जी के काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने काफी स्कीमें भी चलाई थीं जैसे अबकी बार ट्रंप सरकार आदि। अब वह अमेरीका के राष्ट्रपति बन चुके है। उन्होंने एक छोटी सी चीज बोली कि मैं रेसिपोक्ल टेक्स लगाउंगा। इसका मतलब यह है कि जो टैरिफ आपने मेरे देश के ऊपर लगाया है, मैं उसी प्रोडक्ट में आपके ऊपर लगा दूंगा। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में ही थे तो उन्होंने वहीं बैठे-बैठे अमेरीकी शराब जिसको केंटनी व्हिस्की कहते हैं, उसकी ड्यूटी 100 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी। अब आगे यह सुनने में आ रहा है कि यही काम सेब पर न हो जाएं। सेब का इनका इतिहास बताता हूं। इनके उतने ही एम0पी0 उस समय

11.03.2025/1330/A.P./A.S./02

भी थे, वर्ष 2023 के बीच में अमेरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन भारत आने वाले थे, लेकिन भारत आने से पहले वॉशिंग्टन एप्पल की ड्यूटी इन्होंने 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी। आप तो सेब वाले हो आपको तो यह मालूम होगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि पहले 4496 मीट्रिक टन सेब इंपोर्ट होता था लेकिन इस कदम के बाद एक साल के अंदर सेब का इंपोर्ट 19 गुणा बढ़कर 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये होगा। जिसका सीधा खामियाज़ा हमारे बागवानों के ऊपर पड़ा है। जिसके लिए आप जिम्मेवार हैं और किसी ने इसके उपर आवाज तक नहीं उठाई। अब अगर ट्रंप जी कहते हैं कि आप ड्यूटी को 30

प्रतिशत कर दो। आप कृप्या एक चीज़ कीजिए की प्रधानमंत्री महोदय जी से बोलिएगा कि लाल बालों वाले राष्ट्रपति जी को अपनी लाल आंख दिखा कर हमारे लाल सेब बचा लीजिएगा, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर हमारे चार जिलों पर एक बहुत बड़ा आघात होने वाला है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी सात एम0पी0 साथ में प्रतिनिधित्व करें कि सेब पर जो ड्यूटी है वह अमेरीका के दवाब में आकर न घटाएं, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही 02:30 बजे अपराह्न तक भोजन के लिए स्थगित की जाती है।

श्री ए0टी0 द्वारा.....जारी

11.03.2025/1430/ए0टी0/एम0डी0/.1

(दोपहर के भोजनोपरांत माननीय सदन की बैठक 02:30 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आगे चर्चा होगी और माननीय श्री सुल्तानपुरी जी इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे।

श्री विनोद सुलतानपुरी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री भवानी सिंह पठानिया जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि इस सदन में एकत्रित सदस्य राज्यपाल महोदय का दिनांक 10 मार्च 2025 को उन्हें संबोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं, का मैं अनुसमर्थन करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी सरकार का जो इन दो वर्षों का कार्यकाल रहा है, वह ड्राइव होता है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके द्वारा जो डायरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले-आउट की है और हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इस रिवाज को आगे कैसे ले जाया जाए, इसीलिए इसका नाम व्यवस्था परिवर्तन रखा गया ।

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी.....

11-3-2025/1435/MD/DC/1

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी...

आज जो हमारी डाइरेक्शन है वो डाइरेक्टिव प्रिंसीपल को लेते हुए हमारे संविधान का रिकार्ड हमें देना है उसके द्वारा जो ले-आउट किया गया है आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 41 से लेकर 47 तक ये सारे हमारे प्रींसिपल्ज हैं जिनके द्वारा हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमें डायरेक्शन्ज दी हैं। और यह सरकार उसी पक्ष में आगे बढ़ रही है। आज हम देखते हैं कि जो पिछली सरकारें थीं उसमें एजुकेशन के नये तरीके नहीं अपनाए जा रहे थे। मैंने देखा है कि पहले जो हमारे सरकारी स्कूल्ज में बच्चे पढ़ते थे वे जीवन में आगे बढ़कर सफल होते थे। मगर समय के साथ हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जंग लगना शुरू हुआ मगर इसको रिकॉग्नाईज करने के लिए हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया। इसमें हमें भी कई बार अनईजी फील हुआ मगर उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया और हम अब हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रोड्यूस करने वाले हैं तथा इस पर काम चालू हुआ। आप देखते होंगे कि आज स्कूल्ज में रेशनेलाइजेशन हो रही है। रेशनेलाइजेशन के साथ ही साथ हमारा जो फॉल्टी सिस्टम है उसको भी ठीक किया जा रहा है। आज उसका यह परिणाम आया है कि हमारा प्रदेश जो पहले 18वें स्थान पर हुआ करता था वह अब अव्वल नम्बर पर आया है। हमें पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। यह हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प का परिणाम है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह निर्णय

11-3-2025/1435/MD/DC/2

भी लिया था कि क्योंकि आगे की पढ़ाई में अंग्रेजी का बहुत महत्व रहता है। वह चाहे मेडिसिनल एजुकेशन है या कोई ओर एजुकेशन है जिसमें हमें इंटरनेशनल लैवल पर जाना है तो हमारे बच्चों में एक जो आत्मविश्वास होना चाहिए उसके लिए अंग्रेजी की पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे सरकारी स्कूल्ज में प्री-प्राइमरी क्लासिज भी शुरू की गई। इसके अतिरिक्त बच्चों की यूनिफॉर्म पर भी काम किया गया। हमारी सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूल के बच्चों को एक जो कॉन्फिडैंस बिल्डिंग दी गई है उसके परिणाम आप देख सकते हैं कि आज स्कूल्ज में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ी है। हमारा हर स्कूल इंग्लिश

मीडियम बन चुका है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने वोकेशनल टीचर्स की नियुक्ति करने का काम शुरू किया है जोकि एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। वोकेशनल टीचर्स के आने से बच्चे की जिस प्रकार रुचि है उसके अनुसार उसको नौकरी भी मिले तो उसे उस प्रकार की वोकेशनल टीचर्स द्वारा दी जाएगी और उन्हे इनकरेज करने के लिए यह बात हमारे जमीनी स्टेप पर पाई गई। साथ ही में आज हमारी जो इंडस्ट्री कि डिपार्टमेंट है उसमें बेस्ट प्रफोरमेंस स्टार्ट-अप हिमाचल प्रदेश को मिला है मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय हमारे इंडस्ट्रीज मनिस्टर साहब को भी और इसमें आपने जो बहुत बडा काम किया है जिसमें इनवाइरमेंट का भी खयाल रखा गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी कि जो सोच है ई-टैक्सीस और सोलर पावर जनरेशन घरों तक पहुंचाई गांव तक पहुंचाई।

श्रीमती के0एस0 जारी -----

11.03.2025/1440/केएस/एचके/1

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी---

रेवन्यू के बारे में बात करते हैं। रेवन्यू में सबसे ज्यादा मुश्किलें रही हैं। दो साल के अंतराल में अगर हाईएस्ट म्यूटेशंस हुई हैं तो पूरे हिमाचल में हुई हैं और क्लीनली हुई है जो कि बहुत बड़ी बात है। आज यह चर्चा भी आई है कि पटवारियों को स्टेट काडर के तहत लिया जाए। यह एफिशिएंसी के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रपोज़ल दी है। कई लोगों को शायद यह ठीक न भी लगे परंतु हिमाचल कैसे आगे बढ़े, इसके ऊपर सरकार का ध्यान है और मैं समझता हूं कि इस तरह की जो कवायद है, सोच है, यह प्रदेश को आगे ले जाती है। आज हमारे रोडज़ में गुणवत्ता आई है, सड़कों में क्वालिटी वर्क देखने को मिल रहा है। हमारे लोक निर्माण मंत्री जी बहुत काबिल हैं, युवा हैं और उन्होंने पर्सनली मॉनिटर करने का जो सिस्टम अपनाया है, मैं इन्हें भी इसके लिए बधाई देता हूं।

टूरिज्म को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की जो सोच है, हम गांव की तरफ जा रहे हैं और होम स्टे को एन्क्रेज किया जा रहा है। हमारा पर्यटक किस तरीके से आराम से गावं तक पहुंच पाए, इसके लिए नये हेलीपैड्ज़ बनाए जा रहे हैं जिन्हें इंटरनेशनल

स्टैंडर्ड का बनाया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। आज आई0पी0एच0 में नये-नये तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले जो कैमिकल्ज़ पानी में डाले जाते थे, उस पानी को पीने से बहुत सी समस्याएं आई हैं। उसके कारण कैंसर होता है। पहले जो गल्तियां हुई हैं, उनको सुधारने का जिम्मा हमारी सरकार ने लिया है जो कि बधाई की बात है। इसी तरह इसमें नई टैक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया और इसके द्वारा लोगों को स्वच्छ पानी मिले, अच्छा पानी मिले, इसके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार नैचुरल डिजास्टर से जूझ रही थी तो हमने हमारे विपक्ष के साथियों से अनुरोध भी किया था कि आप हमारे साथ दिल्ली चलो। आज जो हमारा नैचुरल डिजास्टर का पैसा बकाया बनता था वह भी हमें नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही जो हमें फाइनेंशियल लॉसिज़ हुए हैं और जो हिमाचल का हक है, वह भी हमें नहीं दिया जा रहा है जो कि बहुत दुख की बात है। इसके बावजूद जब डिजास्टर हुआ, जो हमारी लीडरशिप है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो निर्णय

11.03.2025/1440/केएस/एचके/2

लिया कि जब एक गरीब आदमी का पूरा घर तहस-नहस हो जाता है, उसके बाद उसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए, यह हिस्टोरिक है और 7 लाख रुपये हमारी सरकार ने उनके घरों के लिए,उनको रिहैब्लिटेट करने के लिए उपलब्ध करवाए। इस तरह के निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब आप में क्षमता होती है। भले ही हमें फाइनेंशियली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और हमारे जो विपक्ष के साथी हैं ये न तो हमारे साथ दिल्ली जाते हैं और न ही हमारे प्रदेश की बात करते हैं। हमारे माननीय सांसद वहां बोलने से कतराते हैं। ...(व्यवधान) आज हमारे प्रदेश के जो बागवान हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो रहा है। जिस तरीके से इकोनॉमी शैटर होने वाली है, इसके ऊपर हमें इकट्ठा हो कर, मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करता हूं क्योंकि यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है और आने वाले समय में हमारी एप्पल की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संग दिल्ली चले और हिमाचल की बात रखने में हमारी मदद करें।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में हम आए दिन यह सुनते थे कि जो एग्जाम हो रहे हैं, उनका पर्चा लीक हो चुका है। जब इस तरह की बातें हुईं, तो हमारे जो युवा साथी हैं, उनका जीवन बहुत खतरे में पड़ गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.03.2025/1445/av/hk/1

श्री विनोद सुल्तानपुरी----क्रमागत

जब इस तरह की बातें हुईं तो मैं समझता हूं कि उनसे हमारे युवा साथियों का जीवन खतरे में पड़ा। इसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दृढ़ निश्चय किया और ऑफिसर्ज ने इसको प्लग करने व इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए करप्शन को रोकने का काम किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे युवा साथी के जीवन में जो पहले से अंधकार फैलाने वाला एक सिस्टम चला आ रहा था, क्योंकि एक उदाहरण है कि पहले ऐसे एग्ज़ाम होते थे जैसे एक इंटरव्यू के दौरान टॉपर को यह तक मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य मंत्री कौन है। यह ऑन रिकॉर्ड है मगर आज इस प्रकार की बातें बंद हुई हैं।

आज मुख्य मंत्री जी ने अपने काम करने के तरीके में यह पाया है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे प्रिज़र्व कर सकते हैं। हम अपने पानी के स्रोतों के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। हमारे किसान अपनी जैविक खेती को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हिमाचल आज इस प्रकार की सोच लेकर आगे बढ़ रहा है और हिमाचल में सबसे बड़ा व पुण्य का काम मुख्य मंत्री जी द्वारा शुरू की गई 'सुख आश्रय' योजना है। मैं आपको अपनी आंखों देखा परिणाम बता सकता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 56 बच्चे ऐसे हैं जोकि आश्रम में रहते हैं। उनके पास अब हर सीजन में नये कपड़े आते हैं, उनको पॉकेट मनी आती है और वर्तमान सरकार सही में उनके लिए एक परिवार बनकर सामने आई है। आज उनका ही आशीर्वाद और दुआएं सरकार को मिल रही है वरना यहां पर पहले भी कई बार सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की गईं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव तो वर्ष 2027 में ही होंगे। आप सपना लेते रहिए और तब तक इंतजार करते हुए हमारी सरकार की हिमाचल प्रदेश को

आगे ले जाने में मदद कीजिए। प्रदेश की जनता और देवी-देवताओं का आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक साथ मिलकर काम करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

11.03.2025/1445/av/hk/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चुनाव तो 'वन नेशन-वन इलैक्शन' नीति के तहत वर्ष 2027 की जगह वर्ष 2029 में भी हो सकते हैं।

अब इस चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव और जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी ने किया, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार के दो साल के कार्यकाल और विशेष तौर पर जब बजट सत्र शुरू होता है तो पिछले एक साल के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है। मैं इसमें देख रहा था और शायद यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2025/1450/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

श्री जय राम ठाकुर ... जारी

और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को लम्बा कर दिया गया। यदि इस अभिभाषण की तुलना एक साल पहले के अभिभाषण के साथ की जाए तो इसमें भी मोटेतौर पर वही विषय और बिन्दु लिए गए हैं यानी उन्हीं विषयों को पुनः रिपीट किया गया है। लेकिन अभिभाषण में ऐसा प्रतीत हो कि हमने बहुत कुछ किया है इसलिए अभिभाषण को लम्बा कर दिया गया ताकि राज्यपाल महोदय का उसको पढ़ने में ज्यादा समय लगे। इसमें सरकार का प्रयास अवश्य ही सफल हुआ है लेकिन जब इस माननीय सदन में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चल रहा था तो न सत्ता पक्ष के मंत्रियों में और न ही विधायकों में उत्साह था। मैं सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को देख रहा था और अधिकांश माननीय मंत्री व विधायक सुस्ता रहे थे और कुछ तो गहरी नींद में भी थे। अगर उपलब्धियां हो तो उनको लेकर उत्सुकता होती है। पूरे अभिभाषण में सिर्फ दो बार ही मेज थपथपाया गया और इसके अलावा कोई भी मेज थपथपाने की आवाज नहीं आई। इसका अभिप्राय यह है कि बहुत बड़ी निराशा का वातावरण पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों के बीच में भी है। किसी भी सदस्य द्वारा अभिभाषण का समर्थन करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय, एक प्राकृतिक आपदा होती है, उस पर किसी का बस नहीं होता है। वह प्राकृतिक परिस्थितियों के हालात के मुताबिक होती है, वह तबाही करती है और सभी को समझ में आता है कि प्राकृतिक आपदा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जिस तबाही और बर्बादी के दौर से गुजर रहा है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह तो सरकार द्वारा लाई गई आपदा है। सरकार के व्यवस्था परिवर्तन ने दो सालों में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि व्यवस्था पतन का ऐसा नजारा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। हिमाचल प्रदेश छोटा है इसके बावजूद भी ये हालात बन गए कि पूरे देश भर में हिमाचल की चर्चा हो रही है। यदि अच्छे कार्यों के लिए चर्चा हो

11.03.2025/1450/टी0सी0वी0/वाई0के0/2

तो अच्छा लगता है और उससे आन्नद की अनुभूति होती है कि हम भी देवभूमि हिमाचल के रहने वाले हैं। लेकिन चर्चा सरकार के फैसले लेने के तौर-तरीकों को लेकर हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके कारण जग हंसाई हो रही है। मैं इस बात को बार-बार कहता हूं कि जब सरकार फैसले लेने के लिए बैठती है तो सरकार को गहराई से चिंतन व विचार करना चाहिए और उसमें गम्भीरता होनी चाहिए लेकिन अपने साथियों को विश्वास में लिए बिना और बिना सोचे-समझे फैसले लेने की इनकी आदत बन गई है जिसके कारण जग हंसाई होती है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

11-03-2025/1455/ns-yk /1

श्री जय राम ठाकुर----- जारी

आज फैसला लिया जाता है और कल फिर वापिस लिया जाता है। इस कारण से देश में हिमाचल प्रदेश की चर्चा होती है कि वहां क्या हो रहा है, ये फैसले कैसे हो रहे हैं? मुझे लगता है कि यह देश की चर्चा का विषय नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी हाइ कमान भी इस बात को सोचने के लिए विवश हो गई कि ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं जिससे जग हंसाई हो रही है? अभी माननीय भवानी सिंह पठानिया जी जिन्होंने इस प्रस्ताव को मूव किया वे इस बारे में कह रहे थे । वे कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति के जब इस प्रकार के दौर से गुजरने के आसार लग रहे थे तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष का भी सवा दो वर्षों का कार्यकाल हो गया है। सवा दो साल के कार्यकाल का समय थोड़ा नहीं होता है। अगर सत्ता में गारंटी दे करके आए हैं तो उन गारंटी को पूरा करने का जिम्मा विपक्ष का नहीं है बल्कि वर्तमान सरकार का है जिसके बलबूते आपने सत्ता हासिल की है। मैंने पहले ही दिन पहले ही सत्र में कहा था कि इन 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए 10 जन्म लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अब हालात यही हैं। आप कितनी बार झूठ बोलेंगे और कब तक झूठ बोलेंगे तथा कहां-कहां झूठ बोलते रहेंगे?

सत्ता पक्ष कह रहा है कि 6 गारंटियां पूरी कर दीं। यह बड़ी हैरानी की बात है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि अभी तक गारंटी के नाम पर एक भी गारंटी पूरी तरह से पूरी नहीं की है। आखिरकार, आप (सत्ता पक्ष)क्या समझते हैं? शायद आप यह समझते होंगे कि विपक्ष में बैठे लोग, हिमाचल प्रदेश के नागरिक और जो प्रबुद्धजन हैं उनको कोई जानकारी मालूम ही नहीं है। गारंटी पूरी होती तो आवाज जमीन से आती। गारंटियां अगर पूरी होती तो लोगों के बीच से आवाज आती, आपके विधायकों के चेहरों से पता चलता और मुंह से आवाज आती लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। इन गारंटियों के बारे में एक-दो लोग ही बोल रहे हैं और वे भी रस्म अदा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को ले करके बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पैरा संख्या : 3 में कहा है कि 6 गारंटियां पूरी कर दी हैं। आप ओ0पी0एस0 की बात कर रहे हैं। आपने ओ0पी0एस0 की शुरुआत की है और इसका असली रूप या इम्पैक्ट आने वाले समय में जब आएगा तब ही मालूम पड़ेगा। आप गारंटियों को पूरा करने की बात कह रहे हैं जिसमें आपने महिलाओं की गारंटी का भी पूरा जिक्र

11-03-2025/1455/ns-yk /2

किया है। क्या यह सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में गारंटी के हिसाब से उन महिलाओं की संख्या गिनी जाए तो वह 23 लाख बनती है? आपने इस दस्तावेज में 30,000 महिलाओं का जिक्र किया है। मैं बताना चाहूंगा कि यह संख्या 30,000 भी नहीं है जिन महिलाओं को आपने 1500 रुपये देकर गारंटी पूरी करने की बात कही है। आपने एकमात्र किस्त जारी की है। आपने लोकसभा के चुनाव से पहले और दूसरा, जो घोर संकट आपके सामने आया था यानी उपचुनाव के दौर के समय में गारंटी पूरी की थी। क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उसके बाद भी आपने 1500-1500 रुपये महिलाओं के खाते में डाले हैं? अगर डाले हैं तो कितनी महिलाओं के खाते में डाले हैं? अध्यक्ष महोदय, गारंटी का मतलब तो यह है कि हर महीने 1500 रुपये खाते में आएंगे। आपने सिर्फ वोट लेने, कुर्सी बचाने और सत्ता में बने रहने के लिए एक किस्त जारी की और उसके बाद अब किस्त भी बंद पड़ी है।

आपने कहा कि 680 करोड़ रुपये का राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना के लिए बजट प्रावधान किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितना पैसा खर्च करके कितने

बेरोज़गारों को स्वरोज़गार दिया है? आपने उसका आंकड़ा इस दस्तावेज में नहीं बताया है। आप (मुख्य मंत्री की ओर इशारा करते हुए) अब बैठे-बैठे 40,000 आंकड़ा बोल रहे हैं जोकि सत्य नहीं है। यह सरासर झूठ है। इसमें कतई भी हकीकत नहीं है।

आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

11.03.2025/1500/RKS/एजी-1

श्री जय राम ठाकुर... जारी

आपने गाय और भैंस के दूध में वृद्धि करने का जिक्र किया है। क्या गाय और भैंस के दूध में थोड़ी-सी वृद्धि से आपकी गारंटी पूरी हो गई है? आप गोबर को खरीदने की गारंटी से मुकर गए हैं। अब आप गोबर से केंचुआ खाद बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन आपने 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की गारंटी दी थी। यह स्थिति वर्तमान सरकार के कार्यों को हास्यास्पद बना देती है। जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावक हैं वे ओ.पी.एस. का जिक्र कर रहे थे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ओ.पी.एस. वर्ष 2003 में बंद हो गई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार थी? उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और उनका अनुभव हम सभी से ज्यादा था। हालात को देखकर उन्होंने यह तय किया कि आने वाले समय में हमें इस विकल्प को अपनाना पड़ेगा। मैं यह बात रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने एम.ओ.यू. साइन करके एन.पी.एस. लागू की और ओ.पी.एस. को समाप्त किया। अब इसका दोष हमारे ऊपर कैसे डाला जा सकता है? अब यह कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास पड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं क्या वह प्रदेश सरकार का पैसा है? आप उस पैसे को कैसे क्लेम कर सकते हैं? जो पैसा सरकार का नहीं है उसे आप कैसे कह सकते हैं कि यह हमारा पैसा है? वह पैसा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का है जिन्होंने अपने खाते से काटकर PFRDA में जमा किया है। उस पैसे को प्राप्त करने का अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों का है जो

सेवानिवृत्ति के बाद उसे अपने खाते में प्राप्त करेंगे। सच्चाई यह है कि आप उस पैसे को क्लेम नहीं कर सकते। वह पैसा सरकार के खजाने में नहीं आ सकता।

Speaker: Hon'ble Chief Minister wants to intervene.

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य मुझे आपकी बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

Speaker: I am grateful that you have yielded. Hon'ble Chief Minister, please.

11.03.2025/1500/RKS/एजी-2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ओ.पी.एस. लागू की। आप वर्ष 2003 का जिक्र कर रहे हैं लेकिन यह सही नहीं है। हमने अपनी गारंटी में यह कहा था कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं हम उनके लिए ओ.पी.एस. लागू करेंगे। मुझे आपके भाषण से ऐसा लगता है कि अगर आप गलती से कभी सत्ता में आ गए तो आप ओ.पी.एस. को हटा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, तो आप माइक में यह स्पष्ट रूप से कह दें कि हम ओ.पी.एस. को नहीं हटाएंगे। यह फैसला लिया गया था कि सरकारी कर्मचारी एन.पी.एस. में जाएंगे और उस फैसले के अनुसार यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि सरकारी कर्मचारी का ई.पी.एफ. का अंशदान 10 प्रतिशत और सरकार का अंशदान 14 प्रतिशत होगा। यह उस समय का निर्णय था जब किसी ने भी एन.पी.एस. के बारे में कल्पना नहीं की थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी और सरकार के अंशदान पर कानूनी अधिकार है। जो कर्मचारी एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. में आए हैं, उस समय जो हिमाचल प्रदेश सरकार का अंशदान था वह हम ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसे कोई रोक नहीं सकता। यह पैसा सरकारी कोष से गया है। कर्मचारियों के पास ओ.पी.एस. का विकल्प है और हम उस पैसे को प्राप्त करेंगे। जो पैसा मार्केटिंग में लगाया गया है हम उसकी वापसी की बात कर रहे हैं। हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओ.पी.एस. दी है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

11.03.2025/1505/बी.एस./ए.जी./-1

मुख्य मंत्री जारी...

और दूसरी बात इन्होंने कही है कि 'राजीव गांधी स्टार्टअप योजना' इसके तीन पहलू हैं। एक पहलू युवाओं को एक टैक्सी के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, दूसरा पहलू है 'राजीव गांधी खेती स्टार्टअप योजना', उसमें मक्की 30 रुपये किलो और गेहूं 40 रुपये किलो तथा अन्य भी चीजें होंगी। उन्हें हम स्टार्टअप योजना के तहत आने वाले बजट में लाएंगे। हम तीनों पहलुओं पर बात करेंगे। अभी तो दो वर्ष सरकार के हुए हैं। जुम्मा-जुम्मा देखिए आगे होता है क्या? व्यवस्था परिवर्तन के दौर में आप सब को तकलीफ होती है लेकिन आम जनता के लिए कोई तकलीफ नहीं है। यह व्यवस्था परिवर्तन उन तकियां पुस्सी कानूनों को बदलने के लिए है जिनके कारण हम सुधारात्मक कदम उठा करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष : श्री जय राम ठाकुर जी, कृपया अपनी बात रखें।

श्री जय राम ठाकुर : आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यवहारिक पक्ष सोचिए और आप वहां से बाहर आने की कोशिश कीजिए। जो जमीन पर दिख रहा है, उसे देखने की कोशिश कीजिए कि हकीकत क्या है? मुख्य मंत्री जी जिस प्राकृतिक खेती का जिक्र कर रहे हैं, इसे हमारी सरकार ने ही शुरू किया था और मैंने इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया था। आज प्राकृतिक खेती का वह काम अवरुद्ध नहीं परंतु लगभग बंद पड़ा है। यही जमीनी हकीकत है और आप जा करके जमीन पर देखिए। उनका ट्रेनिंग का कंपोंनेट समाप्त है और ट्रेनिंग का शैड्यूल भी समाप्त है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए सारी चीजें होल्ड पर हैं। मुझे मालूम नहीं मुख्य मंत्री जी ऐसी कल्पनाएं क्यों करते हैं? मक्की की बातें आप कर रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के दौर में यह भी कर दिया कि लोगों को सोसाइटीज में मक्की का आटा लेना पड़ेगा और 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेना पड़ेगा, यदि नहीं लेंगे तो बाकी का राशन लोगों को नहीं मिलेगा।

मुख्य मंत्री : ऐसा नहीं है।

11.03.2025/1505/बी.एस./ए.जी./-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह हो रहा है। यही तो हकीकत है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जमीन पर देखिए। अध्यक्ष महोदय, आप तो पिछड़ा क्षेत्र से आते हैं। आप और हम भी मक्की की रोटी खाते हैं। मक्की का आटा अगर पीस करके रखा जाता है तो वह एक महीने के बाद इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता है और वह कड़वा हो जाता है। उस आटे की अगर रोटी बनाने की कोशिश करें तो रोटी नहीं बनाई जा सकती और वह टूट जाती है। जो भी महिलाएं रोटी बनाती हैं उन्हें इस चीज का पता होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ करके जो बातें कह रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश में इस बात को ले करके मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि यहां जिक्र हो रहा था कि सेब की इंपोर्ट ड्यूटी पर गलत फैसला किया गया है, उसे और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आपको हकीकत में जाने की आवश्यकता है। आपकी पार्टी के विदेश मंत्री आदरणीय आन्नद शर्मा जी थे उनके समय की सिलिंग हुई है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा उसे इन्क्रीज नहीं किया जा सकता है और वह आज तक चल रहा है और यथावत् है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि एम0आई0एस0 के तहत जो पैसा दिया। आपको एक साल का लगभग 50 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के किसानों को देने को है। यह उन बागवानों का हाल है। आपके कुछ माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं जो यहां पर बात करने से कतराते हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

11.03.2025/1510/डीटी/ए0एस0/1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

आज की तारीख में अभी तक आप पैसा देने की स्थिति में नहीं आ पा रहे। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय इस तरह से तो अपनी बात रखना मुश्किल है, इससे अच्छा तो यह है कि

हम बाहर ही चले जाते हैं। मैं देख रहा था कि कल माननीय मुख्य मंत्री मीडिया में भी रिएक्शन दे रहे थे और आजकल मीडिया में रिएक्शन देते वक्त मुख्य मंत्री जी बहुत उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात नहीं करती। वह वॉक-आउट करना चाहती है। इन्होंने कहा कि प्लानिंग की बैठक में भी विपक्ष हिस्सा लेने के लिए नहीं आया। हम नहीं आए; नहीं आये तो नहीं आए; ये हमारा फैसला था और ये एक सोचा-समझा फैसला था। ऐसा नहीं था कि उस फैसले को हमने ऐसे ही अचानक में लिया। आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। मैं इस बात को स्प्ष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये हालात हैं कि जो विधायक प्राथमिकताएं पिछले दो सालों से दी गई हैं, उसमें विपक्ष के माननीय विधायकों की एक भी डी.पी.आर. उसमें अभी तक नहीं बन पाई है और मैं भी स्वयं इसमें शामिल हूं। हमने अधिकारियों से कहा कि पहले हमें बताया जाए ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारियों ने कहा कि हम इसे जल्दी कर देंगे।

Speaker: Hon'ble Leader of Oppostion, will you yield please?

Shri Jai Ram Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, I will not yeild. ...(Interruption) अगर इसी तरह का दौर रहा तो मुझे लगता है कि फिर बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तथ्य इन्हीं के पास नहीं है, हमारे पास भी हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही प्वाइंट में बोलना है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विपक्ष जो ये बागवानों की बात कर रहे हैं के संदर्भ में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछली सरकार में किसानों का एम.आई.एस. के तहत 78 करोड़ रुपये बकाया था उसके बाद वर्ष 2023-2024 में प्रदेश में फिर आपदा आई और जो एम.आई.एस. था उसका हमने तकरीबन 153 करोड़ रुपए, जिसमें इनकी सरकार के समय का जो 70 या 78 करोड़ रुपये का एरियर भी था, उसके अतिरिक्त भी हमनें बागवान का अप्रैल तक का पैसा दे दिया है, जो 153 करोड़ रुपये के करीब था।

11.03.2025/1510/डीटी/ए0एस0/2

नेता विपक्ष कह रहे है कि इनको पता ही नहीं धरातल पर क्या हो रहा है? मैं इनको यह कहना चाहता हूं इस बार का जो एम.आई.एस. है, वह नया है और बागवानों का सारा पैसा दिया गया है। दूसरी बात ये विधायक प्राथमिकता के बारे में बोल रहे हैं। मैं विधायक प्राथमिकता से सम्बन्धित बात अभी नहीं कहना चाहता मैं जब रिप्लाई दूंगा उस समय इसकी बात करूंगा। ये तथ्य आप देख लीजिए। इन्होंने जो बात कही है शायद उसमें इस साल का जो बैलेंस है, वह होगा। लेकिन पिछले दो साल में हमारे समय की सरकार में उसका सारा पैसा दे दिया है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जब एक बार भरोसा टूट जाता है- तो वह टूट जाता है। यह टूटा हुआ भरोसा वापिस नहीं आने वाला। आंकड़ों के संबंध में झूठ बोलना, आंकड़ों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना, वर्तमान सरकार की यह आदत बन गई है। जिस दिन हमनें विधायक प्राथमिकता की बैठक में हिस्सा नहीं लिया उस दिन एक अधिकारी ने आपके हाथ में एक कागज पकड़ा दिया और उस कागज को आपने पढ़ कर सुना दिया कि इतना हमनें इस निर्वाचन क्षेत्र में दिया-उतना हमनें उस निर्वाचन क्षेत्र में दिया; यह सारे-का-सारा उस समय का है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान डी.पी.आरज. बन कर तैयार हुई थी और स्वीकृत हो कर आई थी, वहीं पैसा खर्च हुआ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न तो यह था कि विधायक प्राथमिकता की बैठको में हम इसलिए नहीं जा रहें हैं क्योंकि पिछले दो साल से हमारी डी.पी.आरज. ही नहीं बनी। प्रश्न यह था कि डी.पी.आरज. नहीं बनी है। जब नहीं बनी है तो नहीं बनी है। जब हमारे विधायकों ने अधिकारियों से कहा कि हमारी डी.पी.आरज. बनी हैं के नहीं बनी, तो उन्होंने कहा की हम जल्दी बना रहे हैं। लेकिन डी.पी.आरज. किसी की भी नहीं बनी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो मैंने विधायक प्राथमिकताएं दी हैं उनकी डी.पी.आरज. भी नहीं बनी है। हमने इसलिए कहा। क्योंकि कुछ क्षेत्र में ही डी.पी.आरज. बनाने के ओदश दे दिए गए और उनकी डी.पी.आरज. बन कर तैयार हो गई और वे डी.पी.आरज. दिल्ली भी भेज दी गईं और उनकी डी.पी.आरज. को स्वीकृत करने का प्रोसैस भी शुरू हो गया। लेकिन सिर्फ विपक्ष के माननीय विधायकों के क्षेत्रों से संबंधित डी.पी.आरज. को डिले किया गया या

फिर रोका गया। हमारा प्रश्न यही था लेकिन जो आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन भी प्रस्तुत किए और श्री एन0जी0 द्वारा जारी

11.03.2025/1515/ए.एस.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर.....जारी

मैं कहना चाहुंगा कि अधिकारीगण यही काम करने में लगे हैं और आपको गलत सूचनाएं देते हैं। मेरा आपसे कहना है कि इस पर थोड़ा ध्यान रखें और विपक्ष को हलके में मत लीजिए। विपक्ष के पास फैक्ट्स हैं। हमने सारी सूची को वैरिफाई किया है। हमने विधायक दल की बैठक बुलाकर अपने सभी विधायकों को पूछा है कि क्या आपके विधान सभा क्षेत्र में यह पैसा स्वीकृत हुआ है? उन्होंने कहा कि यह पैसा तो तब स्वीकृत हुआ था जब आप (स्वयं के लिए) मुख्य मंत्री थे। इनकी डी0पी0आर0 तो आपके समय में ही स्वीकृत हो चुकी थीं और अब इन पर कार्य चला हुआ है। हमें अच्छा लगता यदि आप यह बोलते कि डी0पी0आर0 बननी चाहिए और हम इन सभी चीजों को एक्सपीडाइट करेंगे। आपको यह भी कहना चाहिए था कि जिस विधान सभा क्षेत्र में नाबार्ड के तहत पैसा देने का स्कोप बचा हुआ है वहां के लिए हम पैसा जारी करने में प्राथमिकता देंगे। आपको अधिकारियों ने जो आंकड़े पकड़ाए हैं वे सत्य पर आधारित नहीं थे। अधिकारियों ने आपको कहा है कि इतना पैसा स्वीकृत हुआ है लेकिन यह नहीं बताया कि इनकी डी0पी0आर0 पूर्व सरकार के समय में स्वीकृत हो चुकी थी।

अध्यक्ष महोदय, आज हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की यह स्थिती बन गई है कि अपनी योजनाओं का कोई नाम ही नहीं है क्योंकि योजनाएं शुरू ही नहीं हो पाई हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि योजनाओं में अपना नाम लिखना छोड़ दीजिए। जब आप योजनाओं के साथ अपने नाम का जिक्र करते हैं तब वह योजना शुरू ही नहीं हो पाती है। वह योजना जमीन पर ठीक प्रकार से चल ही नहीं पाती है और इससे आपका नाम भी खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि अधिकारीगण आपको खुश करने के लिए कहते होंगे कि आपके नाम से योजना बनाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं तो उसमें केन्द्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। इस अभिभाषण के एक पैरा में सरकार ने जरूर कहा है और आपने स्वीकार किया है कि केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना

11.03.2025/1515/ए.एस.-एन.जी./2

हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देना कठिन है। आप तो केन्द्र सरकार की योजनाओं पर अपनी मोहर लगाए जा रहे हैं। आप राष्ट्रीय राजमार्गों का भी श्रेय ले रहे हैं कि यह हमने किया है। आप फोर-लेन का भी श्रेय ले रहे हैं। आप प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का भी श्रेय अपने आप ले रहे हैं। आप प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को मिले लगभग 93000 घरों का भी श्रेय ले रहे हैं। इस सबके बाद भी इस अभिभाषण में एक स्थान पर भी आपकी सरकार ने केन्द्र सरकार का धन्यवाद नहीं किया है। केन्द्र सरकार ने प्रदेश को सी0आर0एफ0 का पैसा दिया है, नाबार्ड का पैसा दिया है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आया है, ए0डी0बी0 प्रोजैक्ट का पैसा आया है और इसके अलावा केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें भी प्रदेश को सैंकड़ों करोड़ रुपये आए हैं। आज केन्द्र सरकार की इन्हीं योजनाओं के माध्यम से वर्तमान सरकार का कार्य चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के बजट के माध्यम से वर्तमान सरकार ने क्या किया है? आज यह प्रश्न उठा है और इस अभिभाषण में आपको इसका जवाब देना चाहिए था। आपने महामहीम राज्यपाल महोदय से 1 घण्टा 30 मिनट से ज्यादा समय लगवाकर जो यह अभिभाषण पढ़वाया है उसमें कहीं पर भी केन्द्र सरकार के धन्यवाद का जिक्र नहीं है। आपने केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का श्रेय अपने ऊपर ले लिया है। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि फैडरल सिस्टम है। लेकिन इसमें यह भी बोलना चाहिए कि केन्द्र सरकार का हमें सतत् सहयोग मिल रहा है और उसके बावजूद हम बेहतर ढ़ंग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कहते तो ज्यादा बेहतर होता।

अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में रेलवे की बात की गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को चिट्ठी लिखी है कि आप स्टेट शेयर जमा कीजिए नहीं तो हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं का काम चलाए रखना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार की योजनाओं में स्टेट शेयर देने की स्थिति में भी नहीं है। मैं तो एक आंकड़े को लेकर हैरान हुआ और मुझे लगा कि...(व्यवधान)

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

11.03.2025/1520/पी0बी0/ए0जी0/-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

...(व्यवधान) अभी तक बिलासपुर ही मांग रहे हैं। आगे तो सर्वे का प्रोसैस है। पहले सर्वे फाइनल होना है उसके बाद वह भी 50-50 शेयर के साथ होगा। ...(व्यवधान) आज अगर हिमाचल में कार्य हो रहे हैं तो वह सैंटर की योजनाओं की वजह से हो रहे हैं। चाहे वह पी0एम0जी0एस0वाई0, मनरेगा का पैसा हो चाहे नाबार्ड, सी0आर0एफ0, वर्ल्ड बैंक, ए0डी0बी0 का पैसा हो या फिर स्किल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को दिया गया पैसा हो। अगर मैं Special Centre Assistance की बात करूं तो पूर्व में रही हमारी सरकार को मात्र 1983 करोड़ रुपये मिले थे जिसमें वर्ष 2021 में 533 करोड़ रुपये मिले। वर्ष 2021-22 में आठ सौ करोड़ रुपये मिले और वर्ष 2022-23 में 650 करोड़ रुपये मिले। यह वह पैसा है जो केन्द्र सरकार 50 साल के लिए लोन पर देती है बिना ब्याज के। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार को वर्ष 2023-24 में 1,515 करोड़ मिला तथा वर्ष 2024-25 में 1347 करोड़ रुपये मिला जिसको जोड़ कर 2,872 करोड़ रुपये बनता है जिसका आपने केन्द्र सरकार को धन्यवाद नहीं किया।

आप हमें सैंट्रल टैक्सिज़ का शेयर समझा रहे हैं और साथ में Revenue Deficit Grant (आर0डी0जी0) की बात की जा रही है। मैं पिछले कल देख रहा था कि तेलंगाना राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि उनकी गलत फहमी दूर हो

गई है, जो गारंटीज़ चुनाव से पहले दी थी वह कैसे पूरी होगी। उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था कि प्रदेश के ऊपर लगभग 350 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण है। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति यह है कि प्रदेश की जितनी आय होती है उससे वह कर्मचारियों की तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। अब जब हकीकत मालूम हुई तो उनकी आंखें खुल गई।कम से कम किसी व्यक्ति ने हिम्मत तो की, हौसला तो किया कि सच्चाई को स्वीकार करें। परंतु यहां सच्चाई सामने है लेकिन उसके बावजूद सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा था कि यह जब आए0डी0जी0 कम हो रही थी तब से शुरू करना चाहिए था। जब से जी0एस0टी0 मुआवज़ा मिलना बंद होना तय हो गया था उस वक्त से शुरू करना चाहिए था। हमने उपलब्ध संसाधनों से प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को चलाया। मुझे इस बात का फक्र है कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में 80 वर्ष के बाद जो पैंशन मिलती थी भाजपा सरकार

11.03.2025/1520/पी0बी0/ए0जी0/-2

ने वह 60 वर्ष की और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को हमने पैंशन दी है। भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना के अंतर्गत 25 हज़ार गरीब लोगों जो इलाज के लिए अपने बिस्तर पर बेबस पड़े हुए हैं लेकिन जिंदा है और अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते उनके खाते में हर महीने तीन हज़ार रुपये डाले हैं। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवार की बेटियों के लिए शगुन योजना चलाई जिसके अंतर्गत लड़की की शादी के दिन 31 हज़ार रुपये उनके खाते में डालने की शुरूआत की थी। हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हज़ारों युवाओं को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए व्यवस्था की थी। वे जो लोन लेते थे उस पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी तथा विध्वा और एकल नारी को 35 प्रतिशत सब्सिडी उस वक्त प्रदान की है। इसके बावजूद भी आपकी सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दीं। आज आप जिन योजनाओं का जिक्र कर रहें हैं कि आपने ये शुरू किया आपने वो शुरू किया मुझे इस बात को लेकर बहुत हैरानी हो रही है। मैंने विधान सभा के धर्मशाला सत्र में कहा था कि सरकार की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक नहीं है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

11.03.2025/1525/A.P./D.C./01

श्री जय राम ठाकुर द्वारा जारी.....

हिमाचल प्रदेश में 80 साल के बाद जो पेंशन मिलती थी वह हमने 60 साल तक पहुंचाईद और 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन दी है। हमने हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना के अंतर्गत लगभग 25,000 गरीब लोग जो इलाज के लिए बेबस अपने बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, हमने उनके खाते में 3000 हज़ार रुपये हर महीने ड़ाले थे। हमने हिमाचल प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवार की बेटियों के लिए शगुन योजना चलाई थी। जिसके अंतर्गत उनकी शादी में 31,000 रुपये दिये जाते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हजारों बच्चों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए व्यवस्था दी और उसपर जो लोन लेते थे, उस पर सब्सिडी मिलती थी, बेटियों के लिए 30 प्रतिशत थी और विधवा व एकल नारी को 35 प्रतिशत देते थे। उसके बावजूद यह सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। आज जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने यह शुरू किया, वह शुरू किया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को लेकर के बहुत हैरानी हो रही है। पिछला विधान सभा का सत्र धर्मशाला में था और उस वक्त मैंने विधान सभा के अंदर कहा था कि सरकार की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है। अब हिमाचल प्रदेश में हालात यह बनते हुए दिख रहे हैं कि मंदिर के चढ़ावे व सोने-चांदी पर नज़र है। हमें उस समय ही मालूम पड़ गया था लेकिन उप-मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। सनातन में आस्था रखने वाले लोग जो हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में चढ़ावा दिया है तो अब कहा जा रहा है कि उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा करवा दिया जाए। इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि हालात किस कद्र हो चुके हैं। ऊपर से इस बात को कहा जा रहा है कि मेरी सरकार ने भी लिया था। मेरी सरकार द्वारा कभी योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा नहीं लिया गया। मैंने पैसा सिर्फ एक चीज़ के लिए बोला और वह मेरी कमिटमेंट थी कि अगर गाय को हम मां कहते हैं तो एक सनातनी होने के नाते, हिन्दु होने के नाते, यह

मेरा धर्म है बनता है कि गाय मां की सेवा कि जाए। इसलिए हमने यह तय किया कि मंदिर ट्रस्टों में जो पैसा है उसमें लिमिट लगाई कि 15 प्रतिशत तक अगर कोई मंदिर ट्रस्ट गौ सदन चला रहा है, उस पर खर्च करने की अनुमति उनको दी। एन0जी0ओ0 अगर कोई

11.03.2025/1525/A.P./D.C./02

चला है और वह चाहते हैं तो 15 प्रतिशत की सहायता की जा सकती है। लेकिन सरकार के खजाने में पैसा जमा करने के लिए हमने कभी नहीं कहा। आपकी सरकार में तो योजनाओं के लिए यह पैसा मांगा गया है। सुखाश्रय योजना एवं सुख शिक्षा योजना सरकारी स्कीमों के लिए पैसा मांगा गया। क्या यह बजटिड स्कीम नहीं हैं? वह आपकी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, आपके दिल के बहुत करीब है, अगर आपके पास उनके लिए बजट नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, इसका मतलब यही होता है। एक तरफ आप सनातन का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ मंदिरों में सनातनियों द्वारा चढ़ावे में दिये गये पैसे कसे आप वापिस ले रहे है। अध्यक्ष महोदय, यह हमने सिर्फ 15 प्रतिशत के लिए कहा था लेकिन हकिकत यह है कि यहां 15 नहीं कहा जा रहा है यहां कहा जा रहा है कि जितना भी पैसा पड़ा है 500 करोड़ के लगभग पैसा मंदिरों के ट्रस्ट में पड़ा है उस पैसे को वापिस लेने के लिए दवाव ड़ाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हनोगी माता मंदिर है मेरे पास उसका फैसला भी है जो वहां पर कमेटी ने फैसला लिया है। 5 लाख रुपये जमा कर दिये कई कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली अभी तक, लेकिन उसके बावजूद 5 लाख रुपये सुख आश्रय योजना के लिए दे दिया गया है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि अगर हमने वह मंदिर ट्रस्ट का पैसा इस्तेमाल किया तो वह हमने गाय की सेवा के लिए किया। जब मैं मुख्य मंत्री बना था तब प्रदेश में 6000 गाय गौ-सदनों में थी और जब मैं मुख्य मंत्री के दायित्व से मुक्त हुआ और नेता प्रतिक्ष के रूप मे आया तो उस वक्त 22,900 गाय हिमाचल प्रदेश के गौ-सदनों में और गौ अभयारण्य में थी। गऊ रक्षा के लिए अगर सबसे बड़ा काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और उसके बाद हमने जो गाय पालन करते हैं, जो 10 से ऊपर गाय रखते हैं उन्हें 500 रुपये प्रति गाय के हिसाब से अनुदान देने का प्रावधान हमारी सरकार द्वारा किया गया था ताकि वह गाय कि सेवा अच्छे से करें। इसके बाद वह अनुदान हमने 700 रुपये प्रति गाय के

हिसाब से किया और इन्होंने कहा कि हम 700 रुपये से इसको बढ़ाकर 1200 रुपये कहा था लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया गया।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

11.03.2025/1530/ए0टी0/एच0कए0/.1

श्री जयराम द्वारा जारी.....

यह ऑन द फ्लोर आपकी कमिटमैंट है अब तो साल बीत गया और दूसरा बजट शुरू हो गया है। लेकिन उसमें आपने अभी तक एक भी पैसा तक नहीं दिया। इसलिए जो गौ माता आपके लिए भी आदरणीय होनी चाहिए और आपकी भी प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया है? आप लोगों ने यह बात बड़ी साफतौर से जाहिर होती है।

अध्यक्ष महोदय, सनातन के बारे में बड़ा स्पष्ट है और इन्होंने कहा है कि मैं हिन्दुवादी पार्टी को हरा कर आया हूं और उसके बाद मंदिर से पैसा मांगा जा रहा है। सनातन का विरोध करना और सनातन के खिलाफ आप गाली देते रहो, सनातन का अपमान करना और उसके बाद इस प्रकार से सनातन का दिया हुआ श्रद्धा का पैसे से आप सरकार की योजनाओं को चलाना चाहते हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में आप यहां पर कह रहे थे कि रेवेन्यू में आपने बड़े अमूलचूल परिवर्तन किया। आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अंधाधुंध पैसा स्टांप ड्यूटी पर बढ़ाया। आपकी मंशा रेवेन्यू जनरेट करने की थी लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में आपके पटवारी, कानूनगो क्यों नराज हैं? आज वे हड़ताल पर हैं उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं । बच्चों ने किसी परीक्षा कॉम्पिटेटिव एक्जाम के लिए उनका सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है और न ही कानूनगो मिल पा रहा है और न ही पटवारी मिल पा रहा है। क्योंकि वहां वे हड़ताल पर चले हुए हैं। आज आखिरकार हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति क्यों आ गई? जो उपलब्धियां आपकी सरकार की हैं जिनका आपको जिक्र करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। अगर सही मायने में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां हैं

तो वह यह है कि जिसका जिक्र आप नहीं कर पाएंगे तो हम ही कर देते हैं। यह लोगों के दिल दिमाग में बैठी उपलब्धियों की बात है कि हिमाचल प्रदेश में आपने दो साल के कार्यकाल में 2000 से ज्यादा खुले हुए संस्थान बंद किये। यह आपकी उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाए तो वह उपलब्धि यह है कि जिस दिन हम सरकार छोड़ कर गए थे और उस समय हिमाचल प्रदेश पर जहां 69000 करोड़ रुपये का ऋण था और उसके बाद आज लगभग 30000 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेकर आपने हिमाचल प्रदेश को एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा ऋण के

11.03.2025/1530/ए0टी0/एच0कए0/2

नीचे आ गए हैं। यह आपकी सरकार की उपलब्धि है। राज्यपाल महोदय जी के आभिभाषण में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए था। अगर नहीं है तो हम कर रहे हैं क्योंकि यह आपकी सरकार की उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश में आपने 5 लाख नौकरियों की गरंटी दी थी। 5 साल में 5 लाख नौकरियां यानि के एक साल में एक लाख नौकरियां, 2 साल में दो लाख नौकरियां, अब तक 2 लाख नौकरियां हो जानी चाहिए थीं। लेकिन आपने एक नोटिफिकेशन निकाली कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त कर दिया गया। आपने डेढ़ लाख नौकरियां समाप्त कर दी, यह भी उपलब्धि आपके खाते में ही जाती है। आपके खाते में यह भी उपलब्धि है कि जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, हैंडीकैप पेंशन मिलती है, 6 महीने से हिमाचल प्रदेश में ओल्ड ऐज़ पेंशन बंद पड़ी है, बुजुर्ग लोग फोन करके हमको बता रहे थे की पेंशन नहीं आई, सुक्खू भाई को बोल देना की पेंशन खाते में नहीं आ रही है। यह उपलब्धि आपके खाते में है जो हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ करके आपके 2 साल के कार्यकाल में जो गरीब लोगों के इलाज के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना शुरू की थी, सहारा योजना शुरू की थी वह सारी योजनाएं बंद कर दी गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल आज न्यूनतम स्थान पर चला गया है और लगभग आयुष्मान भारत की और हिम केयर योजना की लगभग 4.50 करोड़ रुपये की पेमेंट अभी देनी बाकी है हिमाचल प्रदेश के आई0जी0एम0सी0 जैसे संस्थान में जहां पर

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी…….

11-3-2025/1535/MD/HK1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

एक बेटी का पिता कैंसर से पीड़ित था और वह बेटी अपने इलाज के लिए गुहार लगाती रही। डाक्टर ने कहा कि इसे इंजेक्शन लगेगा और यह इन्जेक्शन आपको प्राइवेट खरीदना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। जब तक वह बेटी अपने रिश्तेदारों व सगे-संबंधियों से पैसे का इंतजाम करती तब तक उसके पिता जी इस दुनिया से चले गये। यह IGMC शिमला की बात है। इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का कहां-कहां माफ करेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए भगवान भी माफ नहीं करेगा। यह हिमाचल प्रदेश में वतर्मान सरकार की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में दस हजार से ज्यादा आउटसोर्स में लगे कर्मचारियों को आपने नौकरी से निकाल दिया और जो शेष कर्मी हैं उनको छः-छः महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। आज पैंशन वाले धरना दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम तो कर्मचारी हितैषी हैं और जयराम कर्मचारी विरोधी है। हम इस बात से सहमत है कि आपने आपदा का दो महीने का दौर फेस किया और जो नुकसान हुआ उस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। आपदा से मानव जीवन और संपत्ति की क्षति हुई। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि दो साल तक पूरे विश्व व हिमाचल प्रदेश कोविड का दौर था तो प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी समय पर मिलती थी। अब कर्मचारी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में कब पेंशन आएगी। वे कह रहे हैं कि आप इस बात को सदन में उठाएं। अभी उन्होंने शिमला में जनरल हाउस किया कि आने वाले समय में वे बहुत जल्द आंदोलन पर जाएंगे। यह आपकी उपलब्धियां हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हालात इस प्रकार के बन गए हैं कि यहां के फैसलों की चर्चा पूरे देशभर में होती है। यह चर्चा इसलिए होती है क्योंकि यहां पर समोसे पर FIR होती है। यह भी आपकी उपलब्धि है। जंगली मुर्गा के बारे में चर्चा हुई। आपने जनमंच योजना को बंद कर दिया। आप कहते थे कि जनमंच में रोटी खिलाने का कार्य किया जाता है। यहां तो लोग

आपको मुर्गा खिलाने पर आ गए हैं यह बात अलग है कि आपने मुर्गा नहीं खाया। यह जंगली मुर्गा किसने मारा, किसने बनाया, किसने खाया लेकिन इन लोगों के खिलाफ

11-3-2025/1535/MD/HK-2

कोई कारवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने इस चीज को रिपोर्ट किया, खबर लगाई उन पर FIR दर्ज की गई। आखिरकार यह क्या हो रहा है?

अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपको बोलते हुए 40 मिनट का समय हो गया है, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि आज हिमाचल प्रदेश में हीटर, कुकर का किराया अलग से लिया जा रहा है। बस में अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ मोबाइल पर टिप्पणी सुन रहा हो तो उसकी जांच के आदेश पारित हो जाते हैं। सबसे चिंता का विषय हमारे लिए यह बना हुआ है कि जो मीडीया में रेंगता हुआ हिमाचल के बारे में चल रहा है। पिछले दो महीने के कार्यकाल में दस से ज्यादा नौजवानों की ओवरडोज के कारण हिमाचल प्रदेश में मौत हो गई। आप सारी चीजों को लेकर ठीक हैं और ये खबर लगा रहें हैं कि ये कार्रवाई वह कार्रवाई लेकिन क्या आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि नशे का कारोबार लगातार बढता जा रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के हमने अपने समय में जो कदम उठाए थे उन बातों को जिक्र करने में समय लगेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी आज हिमाचल प्रदेश तबाह होने की कगार पर है। आज अध्यक्ष महोदय देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति बन गई है कि दूर-दराज के इलाके में आज चिट्टा पकडा जा रहा है। जो लोग सरकार का हिस्सा है, जो कर्मचारी है वह चिट्टे को दूर-दराज क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं। आप दो साल से सता में है और आप हमारी सरकार का जिक्र कर रहे हैं। आप कब स्वीकार करेंग कि आप सता में हैं? जब राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है वो आप जबाब दीजिए कि आपके कार्याकाल में ऐसे हालात क्यों बन

गए? जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी सारी सीमांओं का कोई जिक्र नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां 118 के सिलसिले में एक ऑडिया सर्कुलेट हुई है जिसमें नेताओं और अधिकारियों के नाम लिए जा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वह व्यक्ति मुख्य मंत्री का नाम इस प्रकार से ले रहा है जैसे पता नहीं वह कितना बड़ा आदमी है। आप उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर इस तरह की बात आई है तो उन लोगों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए।

श्रीमती के.एस.द्वारा जारी

11.03.2025/1540/केएस/वाईके/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---

अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन यह हकीकत है कि यहां पर कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। उद्योगपति भी यही कहते हैं। इसके अलावा जो नाचन विधान सभा क्षेत्र से ट्रांसफर के सिलसिले में एक चिट्ठी आई है, जिसमें बाकायदा नाम भी लिखकर दिया हुआ है, जिसने शिकायत की है उसने अपना नाम भी दिया है। ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि आप उस पर कार्रवाई करिए। आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी, आप हर बात हंस कर नहीं टाल सकते। आपको गम्भीर होना पड़ेगा। यह चिंता का विषय है कि ट्रांसफर के 40 हजार, 45 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि बिलासपुर में ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टिट्यूट खुला और जब आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उस वक्त उसकी शुरुआत की गई थी। आज भी वे स्वास्थ्य मंत्री हैं और वे जब भी यहां आते हैं, उस संस्थान के लिए लगातार पैसे दे कर जाते हैं लेकिन कांग्रेस के नेता झंडा उठाकर वहां पर नारे लगा रहे हैं कि यहां पर जो ठेके दिए जा रहे हैं वे हमारे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। क्या वे कांग्रेस पार्टी के लिए ठेके देने का काम करेंगे? हर बार पैसा दे कर वे इस ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टिट्यूट जैसे संस्थान को मज़बूत करने के काम में लगे हैं और उसके विरोध में जो ये आरोप लगा रहे हैं, यह बेशर्मी की हद है। ये वहां पर सड़क पर नारे लगाते हैं कि हमारे लोगों को ठेका नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया कन्क्लूड करें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी को गम्भीर होना पड़ेगा। हंसते-हंसते दो साल गुज़र गए। विपक्ष जो भी बात करता है, ये उसको गम्भीरता से नहीं लेते। यह इनकी आदत का हिस्सा बन गया है जो कि प्रदेश को बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि जो चल रहे हैं, वे चल रहे हैं। जो कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। उनको रोकने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा है क्योंकि सब चलता है। मेहरबानी करके इसको बंद करिए। अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जिन बातों का ज़िक्र हुआ है, अगर मैं उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप घंटी दे कर हमें बार-बार रोक रहे हैं। मैं यह भी देख रहा था कि आपने इस अभिभाषण में बस अड्डों का ज़िक्र भी किया है। वरच्छवाड़

11.03.2025/1540/केएस/वाईके/2

(सरकाघाट), पतलीकूहल (कुल्लू), ठियोग (शिमला), जंजैहली (मण्डी) आदि का ज़िक्र किया लेकिन ये हमारी सरकार के समय के हैं। हमने शिलान्यास किया था और इनके लिए बजट का प्रावधान किया था उसके बाद इनका कार्य पूरा हुआ है। आप मेहरबानी करके एक योजना बता दें जो आपने बजट प्रावधान के साथ शुरू की हो, शिलान्यास किया हो और उसके बाद उस योजना पर काम लगा हो और उसको कम्पलीट किया हो? हद तो इस बात की है कि बतौर मुख्य मंत्री जो हमने शिलान्यास किए उनका भी पैसा वापिस ले लिया। यह मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि बतौर मुख्य मंत्री हमने शिलान्यास किया, बजट का प्रावधान किया, टेंडर हुआ उसके बाद भी वह पैसा वापिस हुआ। होर्टिकल्चर थुनाग के लिए 10 करोड़ रुपये हमने दिए थे और मुख्य मंत्री होने के नाते मैंने उसका शिलान्यास भी किया था। आपने उस पैसे को भी वापिस लिया और अभी तक भी वह काम शुरू नहीं हुआ है। टेंडर अवार्ड करने से रोक दिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आप एक उदाहरण बताएं जहां मुख्य मंत्री ने शिलान्यास किया हो और जय राम ठाकुर ने उस शिलान्यास का पैसा रोक दिया हो, काम रोक दिया हो। सभी जगह, जहां-जहां हमारे से पहले मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी ने शिलान्यास किए थे, बजट प्रावधान था या नहीं लेकिन उसके बावजूद हमने उन योजनाओं

को बजट का प्रावधान किया,उनको पूरा किया और प्रदेश को समर्पित किया। यह भाव आपमें भी होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज़रा सोचिए। जमीनी हकीकत इस प्रकार की है। आप बहुत सी बातों का ज़िक्र करते हैं। परिणाम आपने देख लिया। लोकसभा का चुनाव आपके सामने हुआ, हिमाचल प्रदेश में सरकार का नेतृत्व आप कर रहे थे और पार्टी का नेतृत्व भी एक तरह से आप ही कर रहे थे। उसके बाद परिणाम आपके सामने हैं। हम चारों सीटों पर जीतें हैं जो कि कोई छोटा विषय नहीं है। जो हम कह रहे हैं यह जमीनी हकीकत है इसलिए इस बात पर आप सोचें, विचार करें, मेरा इतना ही कहना है।

अध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल जी ने यहां पर अभिभाषण दिया है, मेरा राज्यपाल महोदय के प्रति पूरा सम्मान है लेकिन जो दस्तावेज बनाकर सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया, महामहिम राज्यपाल जी ने एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उसको पढ़ा है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

11.03.2025/1545/av/yk/1

श्री जय राम ठाकुर----क्रमागत

वह बिल्कुल झूठ का पुलिन्दा है। वह तथ्यों पर आधारित नहीं है, उसमें सारी बातें असत्य हैं और वे धरातल से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं हैं। सरकार के पास दो साल के कार्यकाल के नाम पर गिनाने लायक एक भी उपलब्धि नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बीच में यह सोचकर नहीं टोका कि अगर मैं बोलूंगा तो माननीय नेता प्रतिपक्ष भी गुस्से में खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आप बार-बार न उठा कीजिए। हमारे नये विधायक और सभी वरिष्ठ विधायक कहते हैं कि आप बीच में उठते हैं, तो आप बीच में न उठा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, हम हंसते हुए बात सुनें तो भी इनको दुःख होता है। आप हंसते हुए कह रहे हैं तो मैं भी उसको हंसते हुए ही सुन रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम हंसते हुए कही गई बात की गंभीरता को भी समझते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी गंभीरता वाली बात यह है कि जबसे हमारी सरकार आई है और जिसके बारे में यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बड़े जोर-शोर से कहा, पहले मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। हमने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आप भी मुख्य मंत्री थे लेकिन आपने नशे के विरुाद्ध कानून में दो साल तक किसी जज की नियुक्ति नहीं की थी। यह पता तब चला जबसे हमारी सरकार ने नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शुरू की है। हमारी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें एंड-टू-एंड जाकर कार्रवाई की जाए। पी0आई0टी0एन0डी0पी0एस0 के तहत माह फरवरी, 2024 में जब मुझे पता चला कि हम इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट के जस्टिस की एक कमेटी है जोकि इस कानून के तहत कार्रवाई करने की अनुमति देती है। मैंने उस पर साइन किए और मैंने

11.03.2025/1545/av/yk/2

पी0आई0टी0एन0डी0पी0एस0 की एक कमेटी बनाई। उसका फायदा यह हुआ कि आज प्रोपर्टी तोड़ने और गुनाहगारों को अरैस्ट करने की पावर हमारे पास आ गई है। आपके समय में नशाखोर घूमते रहे और आपने अपने समय में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी। अभी नशे में 30 प्रतिशत की कमी आई है और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस प्रदेश को पूर्णतया नशा मुक्त राज्य बनाएगी। दूसरी बात, आप मुझे कहते हैं कि आपके समय के 60 साल के आयु वर्ग के लोगों को पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है। आप भी तथ्यों का ज्ञान रखिए क्योंकि आपके पास भी अधिकारी हैं। आप उनसे भी फोन करके पूछ सकते हैं और इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शिता वाली सरकार है। आप किसी भी अधिकारी से कोई भी

रिपोर्ट ले सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि माह दिसम्बर तक की पेंशन चली गई है और यह पेंशन क्वार्टरली जाती है। इस क्वार्टर की अंतिम किस्त माह मार्च में जाएगी। अगर मैंने झूठ बोला है तो मेरी बात यहां पर रिकॉर्ड में है और आपकी बात भी रिकॉर्ड में है। आप इस बारे में अपने आप कंफर्म कर लीजिए। ...(व्यवधान) नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमने माह दिसम्बर तक पेंशन दे दी है और जनवरी, फरवरी तथा मार्च की अभी दे देंगे। ...(व्यवधान) आप कल अपना रिकॉर्ड ठीक करवा लेना, इसमें आप आरग्यूमैंट क्यों कर रहे हैं? इसके अतिरिक्त इनका एक दर्द होर्टिकल्चर के बारे में है। उसका फाउंडेशन स्टोन आपने रख दिया था, अब हम उसका काम शुरू करवा देंगे। ...(व्यवधान) आप निश्चिंत रहिए, आपके दर्द पर हम मरहम लगा देंगे। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप यहां पर एक बात बार-बार कहते हैं कि मंदिरों के पैसे के बारे में ऐसी नोटिफिकेशन कर दी। किसी भी मंदिर के पैसे के ऊपर एक गाइडलाइन्स जारी की जाती है। आप सड़कों के लिए मंदिर का पैसा देते हैं, विधवा बेटियों की शादी के लिए डी0सी0 मंदिर का पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों का पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप मंदिरों से 20-20 हजार रुपये की राशि देते हैं और हमें कहते हैं

टी सी द्वारा जारी

11.03.2025/1550/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

मुख्य मंत्री ... जारी

...(व्यवधान) मैंने कहा कि अगर कोई अनाथ बच्चा है और कोई उपायुक्त मंदिर से उसको पैसा देना चाहता है तो वह दे सकता है क्योंकि हमारी योजना तो 27 साल की आयु के बाद है। ...(व्यवधान) मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी विधवा की बेटी की एडमिशन डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है तो उसको मंदिर से पैसा दे दिया जाए और सरकार बाद में उस पैसे को वापिस कर देगी। लेकिन किसी भी विधवा की बेटी की पढ़ाई पैसों के वजह से नहीं रुकनी चाहिए। ...(व्यवधान) आप पत्रकार

बन्धुओं से कहना कि यह सरकार का लिखित अभिभाषण होता है जिसको राज्यपाल महोदय पढ़ते हैं। यदि किसी ने राज्यपाल महोदय के नाम से लिख दिया तो उसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि इस अभिभाषण में जो कहा गया है वह उन्हीं के द्वारा कहा लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमारी सरकार का भाषण पढ़ते हैं तो श्री कुलदीप सिंह पठानियां जी द्वारा बोला लिखा जाएगा। ...(व्यवधान) आप बार-बार बोलते हैं कि डेढ़ लाख नौकरियां खत्म कर दी है। आप उन डेढ़ लाख नौकरियों को खत्म करने की नोटिफिकेशन हमें भी बताएं ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुने। आप मंत्री रहे हैं, अनुभवी है आप युवा उम्र में चुनकर आए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जब नौकरियां खत्म करती है तो उससे पहले नोटिफिकेशन करती है। आप भाषण के माध्यम से जो बातें हमें समझाते हैं वह हम समझते हैं लेकिन ऐसे तर्क-वितर्क के साथ आप बात करेंगे कि डेढ़ लाख नौकरियां खत्म कर दी है तो यह अच्छा नहीं लगता। आप सनातन की बात करते है लेकिन हमने कहा कि असली सनातनी तो हम हैं जिन्होंने छद्मवाद को हराकर जन-सेवक पार्टी को लाया है ताकि हम लोग आम लोगों के कार्य को कर सके और कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं चाहे आप लोग साथ दे या न दे, हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य और विधायक वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इन बीते दो वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया है। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी न की

11.03.2025/1550/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

संस्थानों से होगी। हम संस्थान खोलने के लिए नहीं आए हैं, हम गुणात्मक शिक्षा संस्थान बनाने के लिए आए हैं। आप आई0जी0एम0सी0 के इमरजेंसी वार्ड में जाकर मरीजों को पूछना जहां एक बैड पर दो-दो मरीज होते थे। आज वे मरीज हमारी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आपने उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री संजय करोल जी से जरूर मिलना।...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं था लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह आई0जी0एम0सी0, शिमला में गया। उन्होंने पिछले कल मुझसे कहा कि

मैंने इमरजेंसी डिपार्टमैंट में इस तरह की व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी। उस समय मेरे साथ माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी भी थे। लेकिन व्यवस्था में अभी और सुधार करने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। आपने तो हैल्थ सैक्टर को 36वें स्थान पर पहुंचा दिया था लेकिन हम तो उसको ठीक कर रहे हैं ...(व्यवधान).....

एन0एस0 द्वारा ... जारी

11-03-2025/1555/ns- ag/1

मुख्य मंत्री ----- जारी

अध्यक्ष महोदय, ये चीजें वे हैं जो जनता में भ्रम फैलाने के लिए राजनैतिक तौर पर बोली जाती हैं। पूर्व मुख्य मंत्री जी राजनैतिक तौर पर भ्रम फैलाने के लिए इन चीजों को बोलते हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय आशीष बुटेल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, श्री भवानी सिंह पठानिया जी द्वारा लाया गया प्रस्ताव और श्री विनोद सुल्तानपुरी जी द्वारा उस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष : माननीय आशीष जी, एक मिनट, मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि पटवारी, कानूनगो और तहसीलदारों की हड़ताल के कारण कई बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। मैंने इस बारे में सुबह माननीय राजस्व मंत्री जी से भी बात की है और मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे एग्जामिनेशन्ज के फॉर्म भर रहे हैं, वे सैल्फ डिक्लेयरेशन से फॉर्म भर सकते हैं और अगर करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत ज्यादा होगी तो उसके लिए एस0डी0एम0, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बाहर के प्रदेशों के

फॉर्म्ज के लिए एस0डी0एम0, तहसीलदार और नायब-तहसीलदार उनके सर्टिफिकेट बना कर भेज देंगे और मैं इसकी नोटिफिकेशन आज कैबिनेट से करवाने जा रहा हूं। अपने प्रदेश के लिए जो सर्टिफिकेट पटवारी, कानूनगो बनाते हैं तो उसके लिए अभ्यर्थी सैल्फ डिक्लेयरेशन कर सकते हैं। उनका यह सर्टिफिकेट मान्य होगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री आशीष बुटेल जी आप चर्चा में भाग लें।

11-03-2025/1555/ns- ag/2

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले कल राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा और आज सुबह जब अखबारें पढ़ी तो उसमें नेता प्रतिपक्ष का बयान आता है तथा उसमें लिखा गया है कि राज्यपाल महोदय से झूठ बुलवाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि राज्यपाल महोदय जितनी शायद मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनका राजनैतिक जीवन हो गया है। वे बहुत बड़े-बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। वे विधायक, मंत्री और भारत सरकार में Ministry of Finance में Minister of State रहे हैं। उसके बाद बहुत बड़े पद पर हिमाचल प्रदेश में भी आसीन हैं। यह कहना कि उनसे झूठ बुलवाया गया तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का या इस गरिमा का कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार का कोई झूठ बोल पाएगा। झूठ तो तब था जो उस समय हमारे साथ हुआ था। मुझे लगता है कि जब उस तरफ (विपक्ष) चले जाते हैं तो शायद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब हम लोग विधायक थे और विपक्ष में थे तब हिमाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण प्रस्तुत करने इस माननीय सदन में आए थे। उस समय सरकार का नेतृत्व बतौर मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी कर रहे थे। राज्यपाल महोदय, अभिभाषण पढ़ने लगे तो उन्होंने दो-चार पन्ने ही पढ़े और दस्तावेज को

फोल्ड करके अपना अभिभाषण समाप्त कर दिया। माननीय डॉ0 हंस राज जी आपको भी ध्यान होगा क्योंकि उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने हमारे 6 विधायक सस्पैंड किए थे। आप उस समय उपाध्यक्ष थे। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो इस गरिमामयी पद पर बैठता है उसे मालूम होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है? पिछले कल माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है वह शत प्रतिशत सच था। उसका एक-एक शब्द सच था।

अध्यक्ष महोदय,

आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

11.03.2025/1600/RKS/As-1

श्री आशीष बुटेल जारी.....

अखबारों में यह बात सामने आई कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में केवल केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का ही व्याख्यान किया गया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? जो जी.एस.टी. यहां से कटकर जाता है, क्या वह विकासात्मक कार्यों के लिए केंद्र सरकार से वापस नहीं आना चाहिए? अगर हमने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का जिक्र किया है तो क्या ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की ट्रेजरी से हमें उन स्कीमों के लिए अपना शेयर देना पड़ता है? आपने ओ.पी.एस. और छह अन्य गारंटियों की बात की कि हमने इन गारंटियों को पूरा नहीं किया।

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

जब आपकी सरकार थी तो उस समय ओ.पी.एस. की मांग करने वाले कर्मचारी विधान सभा के बाहर खड़े थे लेकिन सरकार के किसी भी व्यक्ति ने उनसे जाकर बात नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय आप विधायक थे और मुझे याद है कि मैं, आप और श्री भवानी सिंह पठानिया जी उन कर्मचारियों के पास गए थे तथा हमने उन्हें यह कहा था कि हम ओ.पी.एस. दिलाने के पक्ष में हैं। आज हमने उनका यह हक उन्हें दे दिया है जिसके लिए मैं

गर्व महसूस करता हूं। आप कहते हैं कि अभी तो यह शुरुआत है और हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या होता है। आप उन्हीं कर्मचारियों के बारे में कह रहे हैं जिन्हें आपकी सरकार ने पुलिस से डंडे मरवाए थे। जो महिलाएं विधान सभा सत्र के समय अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर अपना हक मांगने के लिए यहां आई थीं, आपने उन्हें डंडे मरवाकर यहां से भगा दिया था। आपने उनके खिलाफ केस बनवाए थे। एक टीचर ने जो नारा लगाया था उसके लिए आपने पता नहीं कहां-कहां उसका तबादला करवा दिया था। आप लोगों को याद होगा कि वह नारा बाद में गाना बन गया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जिनके बारे में आज आप यहां चर्चा कर रहे हैं जबकि आपकी सरकार में आप उन बातों का विरोध कर रहे थे। मैं महिलाओं की 1500 रुपये वाली गारंटी को जारी करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस योजना की शुरुआत जिला लाहौल-स्पीति से हुई है। आप कहते हैं कि लाहौल-स्पीति की महिलाओं को केवल एक बार ही किस्त मिली है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि लाहौल-स्पीति की जनता खुश थी

11.03.2025/1600/RKS/As-2

तभी वहां की जनता ने एक महिला सदस्य को चुनकर यहां भेजा है। आप गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इन्होंने गोबर खरीदने का मजाक उड़ाया लेकिन जब प्रदेश सरकार ने यह कह दिया कि हम गोबर खरीद रहे हैं तो आज इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। आप भी अपनी-अपनी गाय और भैंस का गोबर लेकर आइए, हिमाचल प्रदेश सरकार उस गोबर को भी खरीदेगी। आप कह रहे हैं कि विधायक प्राथमिकता के अनुसार हमारी योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो रही हैं। मैं आपसे यह पूछता हूं कि जब विधायक प्राथमिकता की बैठक हो रही थी तब आप कहां थे? आपने उस समय किस बात का विरोध किया था ? ये तो पूरी तरह से आपके अधिकार क्षेत्र की योजनाएं हैं। विधायक प्राथमिकता की योजनाएं आपकी कलम से आनी थीं और जो कुछ भी आप लिखते या कहते उसी आधार पर योजनाएं बननी थीं। लेकिन जब आप विधायक प्राथमिकता की बैठक में ही नहीं आए तो मुझे लगता है कि यह कमजोरी आप में है, सरकार में नहीं है। प्रदेश सरकार को सत्ता में आए हुए दो साल हो गए हैं। हमने हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की है। यह सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल

रही है। जैसे ही हमारी सरकार बनी उसके कुछ समय बाद प्रदेश में एक बड़ी आपदा आई थी। आपदा के लिए केंद्र सरकार से पैसा मांगना तो आपके लिए दूर की बात थी लेकिन मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूं कि जब हमने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए एक रेजोल्यूशन केंद्र सरकार को भेजने की बात की तो उस दिन आप कहां थे? आप यह बात करते हैं कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या किया और क्या नहीं?

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

11.03.2025/1605/बी.एस./डी.सी./-1

श्री आशीष बुटेज जारी...

जब एक छोटा सा प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जाना था तो आप लोग कहां थे? यह हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी आपदा थी। कितने लोग उसमें अपनी जाने गंवा चुके थे? परंतु उसमें आप लोगों ने हस्ताक्षर तक नहीं किए। आपको उस संबंध में प्रदेश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा।

महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बात करना चाहूंगा और एक बहुत पुरानी कहावत है 'Change is the only constant in life', बदलाव जरूरी है और यह भी कहते हैं The only constant for the Opposition is the fear of the change. आप बदलाव से डरते हैं। आप लोग इस लिए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि आज ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है, वह वर्ष 2027 और वर्ष 2032 में फिर से रिपीट न कर जाए। इस बात का आपको डर है और आप डरते हैं। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जी कृपया शांत रहें।

श्री आशीष बुटेल : आप भी यहीं है और हम भी यहीं हैं। हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। महोदय, जब-जब सामने वाले मित्र सरकार में रहे है, जो आज विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन इन्होंने कृषि के लिए पिछले पांच सालों में क्या किया? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर आज कृषक की आर्थिकी नहीं सुधरी है और कृषक अपनी जमीनें छोड़ रहा है तो

उसके लिए आप भी कहीं-न-कहीं गुनहगार हैं। आपके पास पिछले पांच वर्ष थे। आपने ऐसा क्या काम किया, जिससे लोग कृषि की ओर प्रेरित हुए हों? हमारे लोग आज किसानी नहीं कर रहे हैं, पशुपालन करना उन्होंने छोड़ दिया है और बागवानी करना भी छोड़ दी है। मैं फिर से मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्री एवं बागवानी मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये ऐसी स्कीम ले करके आए हैं जिसके अंदर गेहूं और मक्की की खरीद मिनिमम स्पोर्ट प्राइज पर होने लगी है। आपके पशुपालन के अंदर जो हमारे पशुपालक थे जिनको यही नहीं पता था कि 32 रुपये गाय और 47 रुपये में भैंस का दूध बिक जाता था। परंतु आज गाय का दूध 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। यह हमारी सरकार की देन है।

11.03.2025/1605/बी.एस./डी.सी./-2

श्री बिक्रम सिंह : माननीय सदस्य, आपने लोगों को गारंटी कितने रुपये की दी है?

श्री आशीष बुटेल : हम वहां भी पहुंचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसके अलावा मैं अपने गृह जिला कांगड़ा की बात करना चाहता हूं। अगर ढगवार में 250 करोड़ रुपये का मिल्क प्रोसैस वहां पर लग रहा है तो वहां के कृषकों के लिए और आस-पास के पशुपालकों के लिए आपने बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरी बड़ी चीज जो प्रदेश में आर्थिकी के लिए जरूरी है वह पर्यटन है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय और मंत्रीमण्डल के सभी सदस्यों का जितनी भी बार धन्यवाद करूं, कम है।

जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है और आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले जो कहा था कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात कही थी, वह कार्य आज चल रहा है। आज वहां पर उसका प्रोसैस अगली स्टेज तक पहुंच गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय पवन कुमार काजल जी, आप उधर चले गए, आप पहले भी हमारे साथ उधर ही बैठते थे और आज भी उधर ही बैठे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि बजट में मण्डी के एयरपार्ट की बात होती थी। वहां के लिए 1,000 करोड़ रुपया ग्रीन फ्रील्ड के लिए रखा गया। यह भाजपा की ही सरकार थी

जिसे यह नहीं मालूम था कि वहां पर 1,000 करोड़ रुपया दे भी देंगे परंतु जगह नहीं मिल पाएगी। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया गया और आज भी मण्डी एयरपोर्ट के लिए पैसा रखा है। उसके बाद ए0डी0बी0 का आपका प्रोजैक्ट 2400 करोड़ रुपये का है और एक बार फिर से आपका धन्यवाद महोदय, आपके जरिए पालमपुर के सौन्दर्यकरण के लिए बहुत बड़ा पैसा आ रहा है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

11.03.2025/1610/डीटी/डी0सी0/1

श्री आशीष बुटेल जारी...

पालमपुर के सौंदर्यकरण के लिए भी धनराशि आ रही है। उसके लिए भी आपका धन्यवाद। हैलीपोर्ट का निर्माण भी पालमपुर में होने वाला है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। उसके अतिरिक्त चम्बा में भी हैलिपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है, इसके अलावा धर्मशाला के समीप भी एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। वनखंडी में 'जू' का निर्माण किया जा रहा है। पालमपुर में शौरभ वन विहार, जो कि अमर शहीद कैप्टन शौरभ कालिया जी के नाम पर है, वहां 60 लाख रुपये की लागत से एक टॉय-ट्रेन आपके द्वारा शुरु की जा रही है। पौंग डैम में वॉटर स्पोर्टस का काम आप करने जा रहे हैं। कांगड़ा में एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाने वाला है और वहां इंटरनेशनल फाउंटेन भी लगाया जाएगा। इन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद यहीं से करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री महोदय मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आपने बहुत कुछ पालमपुर विधान सभा क्षेत्र को दिया है। मैं मानता हूं कि अगर पालमपुर विधान सभा क्षेत्र को इतना कुछ मिला है तो बाकि क्षेत्रों को कितना मिला होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि अन्य विधायकगणों को मिला होगा।

अगर हम जल शक्ति विभाग की बात करें, माननीय उपमुख्य मंत्री जी यहां पर हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपकी बदौलत पालमपुर ए.एफ.डी.बी. का 135 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट आया है। उसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत वाली एक सिवरेज स्कीम पालमपुर के लिए आपने सैंक्शन। 48 करोड़ रुपये की

एक अन्य स्कीम भी माननीय उपमुख्य मंत्री जी द्वारा पालमपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। नाबार्ड के जरिए जो हमारे किसान है उनके लिए आपने 6 करोड़ रुपये की दो कुल्हें स्वीकृत की जिसमें से एक कुल्ह तो बनकर भी तैयार हो गई। इस तरह की स्कीम्ज वर्तमान सरकार द्वारा सैंक्शन की गई हैं, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सरकार के अंदर बतौर मुख्य संसदीय सचिव मुझे शिक्षा विभाग में भी कार्य करने का मौका मिला। मैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी एक ही स्कूल से पढ़े हैं और ये स्कूल में मेरे सीनियर भी रहे हैं। इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला लेकिन जब हमारी सरकार बनी उसके उपरांत ही माननीय

11.03.2025/1610/डीटी/डी0सी0/2

मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उस बैठक में उपस्थित थे। उस बैठक में जब शिक्षा विभाग की पिछली उपलब्धियों को देखा गया तो ये पाया कि एक समय था जब हिमाचल प्रदेश और केरल के बीच पहले स्थान में रहने के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी वहीं जब एन.ए.एस. (National Achievement Survey) 2021 की रिपोर्ट को देखा गया तो उस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा और जो प्रदेश प्रथम स्थान के लिए लड़ाई लड़ता था उसका स्तर गिर कर अब 21वें स्थान पर पहुंच गया था यानी पहले स्थान से सीधी गिरावट आई और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया। उसी दिन ये डिसाइड हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार जो भी करेगी वह शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए करेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहती। इसी बात पर हमारी सरकार ने बल दिया। उसी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये बात भी बहुत जरूरी है और शायद जो हमारी विपक्ष के मित्र इस सदन में बैठे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं की एन.ए.एस. 2021 में हुआ, यानी भाजपा की सरकार आने के चार वर्ष के बाद। चार वर्ष में इस क्षेत्र में भाजपा की तत्कालीन सरकार ने कुछ-न-कुछ तो कार्य किए होंगे, किसी-न-किसी तरह का तो आपका कार्य रहा होगा, जिसके कारण पहले से हम सीधे 21वें स्थान में

आ गए। उसके बाद वर्ष 2022 में "असर" की रिपोर्ट आई तब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भाजपा सरकार के पांच साल पूरे होने जा रहे थे, उस रिपोर्ट में आया कि आठवीं कक्षा का बच्चा तीसरी कक्षा की किताब भी नहीं पढ़ सकता है। रीडिंग के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग इस बार की रिपोर्ट में सबसे अव्वल है जो उस समय बहुत नीचे थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं।

एक और बात इस सदन में चली रहती थी की ट्रांसफर चली है, ट्रांसफर चली है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने जुलाई के बाद ट्रांसफर्ज में रोक लगाई, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है वह जिस अध्यापक से पढ़ता है उस बच्चे को उस अध्यापक के पढ़ाने का तरीका भी समझ आने लगता है, लेकिन उस अध्यापक की बीच में ही ट्रांसफर हो जाती है तो बच्चों की पढ़ाई उस अध्यापक के ट्रांसफर होने के कारण प्रभावित होती है, लेकिन आज मुख्य मंत्री महोदय ने ट्रांसफर्ज को हैल्ड-अप किया है, उसके लिए भी आपका

11.03.2025/1610/डीटी/डी0सी0/3

मैं धन्यवाद करता हूं। स्कूल्ज में नई नियुक्तियां हुईं और हमारे सभी माननीय विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्र में पड़ता है, आपके क्षेत्रों के स्कूल्ज में शायद अब अध्यापक पहुंचे गए होंगे। मेरे पास भी बतौर मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा विभाग था, मैं इस बात को भी रिकार्ड में लाना चाहूंगा। एक फोन मुझे चम्बा जिले के क्षेत्र से आया और उन्होंने ये कहा कि आजतक उनके क्षेत्र में उन्होंने फ्लां विषय का रेगुलर अध्यापक नहीं देखा था, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

11.03.2025/1615/डी.सी.-एन.जी./1

श्री आशीष बुटेल.....जारी

उसके बाद हमने कोशिश की कि रिसोर्स शेयरिंग की बात करें और जहां पर टीचर्स नहीं होते थे उनके लिए कल्सटर्स बनाए गए हैं तथा एक टीचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पढ़ा सके। उसके बाद हमने Institutions of Excellence की बात की है। 500 GPS, 100 GHS, 200 GSSS or 50 Colleges आज Institutions of Excellence के नाम से चलने वाले हैं और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार हुआ है कि 200 से ज्यादा टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए अपने देश से दूसरे देश में गए हैं।...(घण्टी)... उपाध्यक्ष महोदय, केवल पांच मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में सिंगापुर सरकार के साथ एक एम0ओ0यू0 साइन हुआ है। उस एम0ओ0यू0 के अनुसार सिंगापुर की सरकार हिमाचल प्रदेश के टीचर्स को ट्रेनिंग देगी और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी स्कूल के 50 meritorious students देश से बाहर कम्बोडिया व सिंगापुर गए हैं। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि जिस होटल में माननीय शिक्षा मंत्री जी रुके थे उसी होटल में वे बच्चे भी रुके थे और जो खाना माननीय शिक्षा मंत्री जी ने खाया वही खाना उन बच्चों ने भी खाया है। वहां पर उन बच्चों ने जो सिखा होगा और उनके अंदर जो नयापन आया होगा उससे उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रदेश में पहली बार वर्तमान सरकार ने बच्चों को यूनिफॉर्म के पैसे डी0बी0टी0 के माध्यम से दिए हैं।

11.03.2025/1615/डी.सी.-एन.जी./2

मैं सभी विपक्षी मित्रों को बताना चाहता हूं कि इस बार किसी भी बच्चे की ड्रैस का रंग नहीं उतरा है जिस प्रकार से पूर्व सरकार के समय उतरता था। हमारे विपक्ष के मित्र हर बार रोज़गार के संदर्भ में बात करते रहते हैं कि प्रदेश के युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसा मान लेते हैं कि हमारी सरकार ने जनवरी-2023 में कार्य करना शुरू किया था तो उससे पहले के चार वर्षों में पूर्व सरकार ने कॉलेज कैडर के प्रिंसिपलों की प्रोमोशन नहीं की थी और मैं समझता हूं कि पूर्व सरकार की यह बहुत बड़ी नाकामी थी। ...(घण्टी)... उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में उच्च शिक्षा विभाग में कुल 1504 नियुक्तियां की हैं। हमारी सरकार के अभी केवल दो वर्ष ही हुए हैं और इन दो वर्षों में हमने 1100 से अधिक नई नियुक्तियां करके दिखाई हैं। अगले तीन माह में सरकार के द्वारा लगभग 1500 नियुक्तियां और की जाएंगी जिसका खाका राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को भेज दिया गया है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान सरकार द्वारा 1760 जे0बी0टी0 लगा दिए गए हैं और 1762 जे0बी0टी0 के पद भरने के लिए राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के पास भेज दिए गए हैं। इसके अलावा सी0 एण्ड वी0 के 527 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। इस प्रकार से शिक्षा विभाग में लगभग 6000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।...(घण्टी)...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए।

श्री आशीष बुटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की बात करना चाहता हूं। मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप माननीय मुख्य मंत्री व माननीय शिक्षा मंत्री जी को मिलें ताकि आपके विधान सभा क्षेत्र में भी इस स्कूल का कार्य शुरू हो सके। इसके लिए आपको केवल जमीन व अन्य जरूरतों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करनी होगी। ...(व्यवधान) आपकी सरकार के समय में बच्चे जमीन पर बैठते थे और आज

हमारी सरकार ने 40 हज़ार से अधिक डैस्क देकर बच्चों को सुविधा प्रदान की है।...(घण्टी)...

11.03.2025/1615/डी.सी.-एन.जी./3

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्षी साथियों ने संस्थानों के बंद होने की बात कही है और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक डायलॉग है कि शिक्षण संस्थान नीड बेस्ड होना चाहिए, ग्रीड बेस्ड नहीं होना चाहिए। मैं इनसे एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि नीड बेस्ड भी होना चाहिए और political greed based बिलकुल भी नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का एक कोट कहना चाहता हूं कि ' Success often comes to those who dare to act. It seldom goes to the timid'. So let us dare to act and the success will surely come to us. Hon'ble Deputy Speaker, Sir, thank you very much.

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

11.03.2025/1620/पी0बी0/एच0के0/-1

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज जी भाग लेंगे ।

डॉ0 हंस राज : उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी बाहर चले गए। कोई बात नहीं थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहां माननीय गवर्नर जी से 1 घण्टा और 27 मिनट अभीभाषण दिलवाया गया उसमें आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त टेक्निक लगाई है। वह टेक्निक यह है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था एक मेरा मित्र था वह कहता था कि जब हम लोग आर्ट्स में पढ़ते थे 2001 से पहले की बात है कि आर्टस में पढ़ते

हुए हमारे नम्बर नहीं आते थे, मैं बड़ी अथाह मेहनत करता हूं और कोशिश भी पूरी करता हूं कि सब कुछ बेहतर तरीके से करूं और मुझसे पेपर अटैम्पटेशन भी नहीं होती है। तो हमारे साथ अन्य मित्र था उसने कहा कि आपको फार्मूला नहीं आता, मैं आपको फार्मूला बताता हूं। जो फार्मूला सरकार ने यहां लगाया है ऐसा ही फार्मूला उसने मेरे मित्र को बताया। उसने मेरे मित्र से कहा कि आप जो प्रश्न कर रहे हो मान लो आपसे कहा गया कि हिमाचल कैसा है तो आपको उसमें पूरा हिमाचल का व्याख्यान करना है और उस समय 20 नम्बर का प्रश्न होता था। तो 20 नम्बर का प्रश्न करने के लिए हम आर्ट्स वालों को पांच-पांच पेजिज़ तो भरने ही पड़ते थे तभी 40 पेजिज़ भरे जाते थे। तो फिर हमें उस मित्र ने कहा कि यह फार्मूला मेरे गुरु जी ने बताया है कि तुम यह करो कि पहले इन्ट्रोडक्शन लिखो और उसमें उस प्रश्न का पूरा वृतांत्त दे दो जिससे आपका आधा पेज भर जाएगा। उसके बाद कहो कि main definition of the question, उससे एकाध पेज और निकल जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि main points of the question, ये कर लो इससे भी एक पेज भर जाएगा। उसके बाद elaboration of these all points, मतलब एक्सप्लेशन कर दो। इसके पश्चात् एक-एक प्वाइंट को उठाते जाओ और उसको एक्सप्लेन करते जाओ। उससे आपके 2-3 पेज और भर जाएंगे। अंत में यह लिख दो that I conclude all the points in such a manner. इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी शुरू में ही क्या करवाया है? मैं मेरी सरकार के कार्य करने के तरीक को भी इंगित करना चाहूंगा और शुरू में ही 5-6 प्वाइंट डाल दिए। उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने शुरूआत तो बड़ी अच्छी की है और पण्डित दीन दयाल उपाध्याय साहब की लाइन भी डाल दी। इनको लग रहा होगा कि विपक्ष वाले पण्डित

11.03.2025/1620/पी0बी0/एच0के0/-2

दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत मानते हैं इसलिए वे इस अभिभाषण को सुनेंगे। हम तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुन रहे थे लेकिन इनके अपनी पार्टी के माननीय सदस्य ही नहीं सुन रहे थे। हमें अर्थशास्त्री श्री पठानिया जी जो

अर्थशास्त्र सीखा कर गए वह बड़ा जबरदस्त था। इनका बैंकिंग का जितना भी एक्सपीरियंस है, वह इतना गजब तरीके से पेश किया कि मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया। लेकिन उसके बाद भी इनके मंत्री बनने के चांस नहीं है क्योंकि आज इनसे भी कहा गया कि आप जाओ और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जिसके कारण ये भी खुश और मुख्य मंत्री जी भी खुश है। दूसरा, फार्मूला श्री बुटेल साहब जी को दिया हुआ है। सारा कार्य तो शिक्षा मंत्री जी करते रहे और ये तो बेचारे देखते ही रहते थे। जब ये बोल रहे थे तो इनका मन बड़ा भारी था। शिक्षा मंत्री जी तो बड़े अच्छे आदमी है। इनका तो बड़ा विराट रूप है। इसलिए राज्यपाल महोदय से आपने जो इतनी देर तक पढ़ाया, ये सच में गरिमापूर्ण था।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

11.03.2025/1625/A.P./H.K./01

श्री हंस राज जी द्वारा जारी .....

मैने तो उनको दिया था सुझाव, मैने कहा पढ़ा हुआ समझा जाए। आप दो मिनट में ही चले जाना बाद में फिर हमें इसका व्याख्यान करना पड़ेगा। हमारे पत्रकारों ने भी इस विषय को खींच दिया। यह सारी जो व्यवस्था है मुझे लगता है कि अव्यवस्था के रूप में चली हुई है। स्टेट का तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं लेकिन मै आपको सीधा अपने विधान सभा क्षेत्र चुराह के बारे में अवगत करवाना चाहता हूं। माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं। मैं पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं यह मैं सच्चे दिल की गहराई से कह रहा हूं। जितने डिविजन, सव-डिविजन 246 सड़के तो मैने अपने समय में बनवाई । मैं आपको यह स्पष्ट चीज़े कह रहा हूं माननीय मंत्री जी जब तिसा गये तो हमें व इन्हें बहुत उम्मीद थी कि मेरे डिविजन में हमारी जो बिल्डिग जिसे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 6-7 करोड़ रूपये दिया और भव्य बिल्डिंग बनी है। बस अड्डा, जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन बस अड्डा जो हमने 11 करोड़ रूपये खर्च करके बना दिया था उस समय आचार सहिंता लग गई और बाहर जो टायरिंग तारकोल बिछना था वही रह गया था और वह आज तक नहीं बिछा। इन्होंने न जाने कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन उद्घाटन किया? न पट्टिका लगी वहां न कुछ हुआ और बसें घुस गईं और

वहां पर दुकानें बेच दीं। तो वह तारकोल नहीं बिछी है माननीय डिप्टी सी0एम साहब तारकोल तो बिछवा दो। सारी धूल मिट्टी अंदर जा रही है, मै यह सच्चाई कह रहा हूं और दूसरा एक डबल लेन ब्रिज बनाया है माननीय मंत्री जी वहां से गुजर गये लेकिन पट्टिका नहीं लगाई। मैं चाहता था कि माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी अपनी पट्टिका लगा के जाते तो अच्छा होता और डिविजन की बिल्डिंग भी बन गई है पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं किया? अच्छा तो अब इन से उद्घाटन क्या करवाया गया इ.एन.सी. साहब,एक्सिअन साहब बताएं या कोई और लोग कर्मचारी तो रहते नहीं कवरं साहब ही हैं बेचारे वे कहां जाएं? यह जो उद्घाटन आपसे करवाए गये जिस लडोग रोड को ऊपर बडो तक करवाया गया उसका तो उदघाटन मैं कर चुका था क्योंकि यह सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी थीं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो आप को कोटी-से-चकलू व राजनगर से होते हुए चंबा ले जाया गया क्योंकि बाइंडिंग हो रही है उसकी तो पहले ही करवा चुके थें हम। यह जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ये आपको कसने चाहिए तुम जो

11.03.2025/1625/A.P./H.K./02

है उदघाटन की हुई चीजों का फिर से उदघाटन करवा रहे हो। अब पट्टिका लगती नहीं है जब हम विपक्ष में होते हैं तब यह ख्याल भी नहीं रखते हैं कि हमारी पट्टिका लगेगी। लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि मंत्री जी आए हुए हैं तो पट्टिका लगाए अब वह भी नहीं लगी। अब आप देखो हमार रोना क्या है, आपने स्वास्थ्य भी इसमें गिनवाई, खुशहाल किसान व बागवान भी गिनवाया वो भी माननीय राज्यपाल जी से गिनवाया। चुराह विधान सभा क्षेत्र में हमने जो है पिछली सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 40 बेडिड अस्पताल को 100 बेडिड अस्पताल बनवाया। वह किसलिए बनवाय था हमारी लगभग 45 पंचायतें उसी अस्पताल में फीड होती हैं और यहां पर 300 से 400 की ओ0पी0डी0 हर दिन है उस समय उसका उदघाटन किया, बैड भी लगे एक्सरे, सीटी स्कैन आदि सारी सुविधाएं चलने लगी और उसके साथ-साथ हमें 17 डाक्टर भी मिले और पूरे साढ़े चार साल 17 डाक्टर रहे और अब आप व्यवस्था का आलम तो देखो। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होगे फिर वह नाराज़ होते हैं मेरे से मैं उनसे फिर यह गुजारिश करना चाहता हूं

कि हमारी उन 47 पंचायतों के लोगों ने क्या बिगाड़ा होगा की आज वहां सिर्फ दो ही डॉक्टर हैं और वह भी डेपुटेशन पर कभी कलेल पी0एच0सी0 से कभी बोंदेडी से तो कभी नकरोड़ से कभी जसोरगढ़ से उठाया जाता है यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो गया है। यह तो रैफरल से भी बदतर हो गया है। स्वास्थ्य वहां पर सेनिटेशन के लिए जो हमने आदमी रखे थे आरगेस में भी किल्लत हो गई और अब जो आदमी रखे थे वह भी ड्रॉप करने पडे और अस्पताल बंद। हमारे हालात सच में 10 साल पीछे चले गए हम लोग। मैं यह आप सबसे बताना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। देखिए उस अस्पताल से हमारा पूरा विधान सभा क्षेत्र फीड होता है। अब जो मैडिकल कॉलेज चंबा है उसका आलम भी ऐसा हो गया है वहां से वहां लोग रेफर हो करके सीधे टांडा आ जाते हैं ।

ए0टी0 द्वारा जारी.....

11.03.2025/1630/ए0टी0/वाए0के0/.1
श्री हंस राज द्वारा जारी.....
हमारी व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है इसका जिक्र अगर माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में करवा देते तो अच्छा होता । अब देखिए कल एक खबर छपी थी जो इस मोबाइल पर किसी ने भेजी कि आजकल बच्चों की परीक्षाएं लगी हुई हैं और परिक्षाओं में बिजली बोर्ड का डिवीजन ले रहा है परीक्षाएं मतलब मेरी लगभग 6 पंचायतें ऐसी हैं जहां गांव में लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। जब ट्रांसफार्मर जलता है तो वह दो-दो महीने ठीक नहीं होता । मैंने पीछे प्रश्न भी किया था कि जनाब वह डिवीजन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इसलिए दिया था कि हमारे चंबा में डिवीजन के नाम पर एक तीसा में डिवीजन होना चाहिए क्योंकि वही भरमौर को फीड कर रहा है वही चंबा को फीड कर रहा है वहीं तीसा को करेगा तो यह कैसे होगा । अभी यह जो खबर छपी है यह आत्मा को झुंझलाने वाली खबर है कि हमारी जो गुली-बैरागढ़ पंचायत है यह खबर अमर उजाला ने छापी है। मुझे जो कह रहे थे कि हमारा गलुवा हंडेगल, धंलेजड़ गांव है यह सारे के सारे जितने गांव हैं यहां आज भी तीन-चार-पांच दिनों से लाइट नहीं है। बच्चे क्या पेपर देंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे की गुणात्मक शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।

हमारे हालात सच में बदतर हो गए हैं हमारा बिजली बोर्ड का डिवीजन डी नोटिफाई किया गया। हमने कहा भाई दूसरे हिमाचल की तरह हमें मत ट्रीट करो हम लोग आकांक्षी जिले से हैं और हमारे वहां व्यवस्थाएं नहीं हुई है इसीलिए रोज चिल्ला -चिल्ला के बोल रहे हैं और ऊपर से जो एस्पिरेशनल ब्लॉक सिर्फ तीसा और पांगी रह गया है तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और 2 साल हो गये अब न डिवीजन आया न सब डिवीजन आया और न ही तारे व खंबे लगे। हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम आज से 10 साल पीछे चले गए। बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक पड़ा था जब कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और वर्ष 2012 से पहले तब तो हालात खराब थे कोई गांव कनेक्ट नहीं हुआ था। मुझे 16 ही सड़कें विरासत में मिली थी आज हमारे पास 246 सड़कें हैं, वे हमारी अपनी बनाई हुई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और लगभग सारी सड़कों का उन्नयन हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हो चुका है और लगभग 5000 मकान तो प्रधानमंत्री आवास में आए हुए हैं । अब जल शक्ति विभाग की तरफ आते हैं। जल शक्ति विभाग में मुझे चिंता इस बात की है कि माननीय डिप्टी सीएम साहब यहां पर हैं, आप एक आदेश जारी करो कि लगभग 500 करोड रुपए की सैंक्सनें हमारे वहां थी और काम भी चल पड़ा था, उसमें आप जवाब दें कि वह क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं। गुनघुराट का हमारा

सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लगभग 38 करोड रुपये उस पर खर्च कर रहे थे। उसका इनटेक बन गया, सप्लाई चैन बन गया है और जो डिस्ट्रीब्यूशन टैंक्स हैं वे भी बन गये हैं। लेकिन अब उसकी बहाली नहीं हो सकती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा फिल्टर बेड लगे थे वह नहीं बन पाए। 10-20 लाख का झोल रहा होगा जिससे वह स्कीम रह गई। अब देखो उसका नुकसान क्या हो रहा है ऐसा सभी स्कीमों में हो रहा है हिम गिरी में सनवाल से लेकर के सही कोठी तक थी। हमारा बदोड़ी से मंगली तक एक थी। हमारे यहां खुश नगरी से लेकर के खजुआ तक एक स्कीम थी। हमारा चंजू तक एक स्कीम थी। अब सारी की सारी स्कीम बंद हो गई। माननीय मंत्री जी अब दिक्कत क्या हो गई है कि वह टैंक भी लोगों ने खराब करने शुरू कर दिए। पाइपें चुरानी शुरू कर दी। अब दिक्कत यह हुई कि जब तक उसमें पैसा आएगा तब तक वहां पर न पाइपें होंगी न टैंक बचा होगा। यह डायरेक्शन तो आप दे ही दो। अपने सैक्ट्री को कि कम से कम रख रहा अब तो रखो जब तक वह पूरी नहीं होती 2 साल तो बचाओ जब तक हमारी सरकार नहीं आती । मेरा यह आपसे निवेदन है

कि मैं साफ बोल रहा हूं संजय बस्ती जी मैं सच बता रहा हूं देखो आपने अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो यह फ्लाइट ऐसे उड़ेगी की जिसको जो खाना पीना पहले खा पी लो क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रफ्तार है तो पक्का यह क्रश होगी चीजें है और पक्का बचेंगे वही जो थोड़ा काम करेंगे। तो मेरा यह निवेदन है और मैं हिमाचल की जनता से भी आग्रह कर रहा हूं। देखो पिछली सरकारों ने जो योजना चलाई वह योजना आपने बदल दी जिसका जीता जाता उदाहरण यह है कि उसका नुकसान जनता को होता है अब अटल आदर्श विद्यालय जो है वह हमारी सरकार ने बनाने शुरू किया आपने उसको बना दिया, आप तो गांधी लगते हैं हर स्कीम में क्या स्कीम थी वो राजीव कुछ हां गांधी वीच में ले आते है उसमें आपको अटल पर फोकस करना चाहिए था

श्रीमती एम0डी0द्वारा जारी.....

11.03.2025/1635/एमडी/डीसी/1

डॉ0 हंस राज क्रमागत

आपने ठीक किया। आपने दिलवाया तो दिलवाया, इसमें क्या दिक्कत है? ये प्रत्यक्ष चीजें हैं जैसे चम्बा जिला जो हर बार नितांत आकांक्षी रहा है, उसको फीड करने की बहुत जरूरत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं फिर मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैं वह आज नहीं बोलूंगा, उसको इस टर्म के लास्ट ईयर में बोलूंगा। मेरा निवेदन है कि अभी तो जो स्थिति आएगी वह आएगी ही, ...(व्यवधान) मैं उस बारे में खुलकर नहीं बोल पा रहा हूं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि ...(व्यवधान) मेरे ऊपर बहुत दबाव है। ...(व्यवधान) मेरे ऊपर संजय अवस्थी जी का दबाव रहता है। ...(व्यवधान) ये क्रिकेट मैच में हमारे कप्तान थे न, इसलिए रहता है। हम वह मैच भी हार गए क्योंकि आपने बहुत सारी वाइड बोल फेंकी थीं। मेरा आपसे इसीलिए निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ जरूर इंटरवीन करें कि उस विधान सभा क्षेत्र को स्पेशल विधान सभा क्षेत्र ट्रीट करें और वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, तथा सड़कों के लिहाज से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी जैसे हमने मिनी सचिवालय का पैसा ले लिया था। पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए सच में पैसा दे दिया था। उसके टेंडर बड़ी मुश्किल से करवाए। मेरा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन है कि क्योंकि उसको आपका विभाग ही

एग्जिक्यूट करेगा। शायद किसी का निकला भी है तो आप उसको बोलो कि काम शुरू कर दें। उसने पता नहीं उस काम को क्यों रोका है। मेरा यह निवेदन है कि अभी जैसे बरसात हुई थी तो हमारी चम्बा-तीसा मुख्य सड़क में जो सी0आई0आर0एफ0 का पैसा मिलता है उसके संदर्भ में हम माननीय नीतिन गडकरी जी से भी मिले थे। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा वर्ष 2019-20 यानी हमारे टाइम में भी गया और आपसे भी विशेष आग्रह करना चाह रहा हूं कि कोटी से बड़ोह और बड़ोह से लेकर के कफाड़ी की लगभग 87 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 वहां सब्मिट हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम माह अप्रैल में दे सकते हैं अगर मंत्री जी और सरकार की तरफ से सिफारिश आएगी। आप हमें स्पेशल ट्रीटमैंट दीजिए क्योंकि हमारे हालात सच में बहुत खराब है। आप तो वहां पर जाकर आए हैं। वहां कई फ्रेज़ाईल एरिया ऐसे हैं जहां पर लूज़ स्ट्राटा है और वहां पर सड़क का टिकना बहुत मुश्किल है। इस बार की बारिश ने वहां बहुत डैमेज किया है। हमारी बैरागढ़ की सड़क के दो-तीन डंगे गिर गए हैं और

11.03.2025/1635/एमडी/डीसी/2

उस तरफ मेरा घर भी पड़ता है। वहां आयल की तरफ तो हम दो साल पहले बस भेजते थे। लेकिन अब नकरोड़ से लेकर के वहां पर एक गाड़ी भी नहीं जाती। अभी हम चांजू की तरफ चरड़ा और भूलीण की तरफ जाते थे। लेकिन हमें उस तरफ भी जाने में दिक्कत हो रही है। मेरा यह निवेदन है कि भगवान के लिए कुछ कीजिए। मान लो, अगर बिलासपुर में विकास नहीं होगा तो बिलासपुर तो दिल्ली से भी चल रहा है और यहां से भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री जी खुद हमीरपुर से है तो वह तो वैसे ही चलेगा। शिमला में सरकार बैठती है और इनके आला ऑफिसर्ज यहीं के हैं तो कुछ-न-कुछ एरिया-ईज्म तो चलता ही है। लेकिन हमारी सुध कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय भी भटियात की तरफ जहां-तहां फैल गए। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ...(व्यवधान) महाजन साहब तो आपने ही इधर भेजे हैं। लेकिन वे दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय से झूठ बुलवाया गया, मैं तो चाय पीते-पीते भी उनको बोल रहा था कि आपको सच में यह नहीं पढ़ना चाहिए था। क्योंकि आप लोग तो हर कुछ पढ़वाते हैं और जो है ही नहीं उसको क्यों पढ़ना चाहिए। मैं माननीय आशीष बुटेल जी की

तो मज़बूरी समझ सकता था क्योंकि गोकुल भाई इनके साथ-साथ होते हैं और इनको जोर से चिल्लाना पड़ेगा। उनकी तो मज़बूरी है और मैंने कहा भी है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी का तो अपना फॉर्मूला है। कुछ मामलों में तो हम इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। इन्होंने जिसको ठीक करना था, कर दिया। इन्होंने बड़े-बड़े बंदे ठीक कर दिए और किए भी आपकी ही तरफ के हैं। शायद माननीय मुख्य मंत्री जी सुन रहे होंगे और मैं उनको यह फॉरवर्ड भी कर दूंगा कि हमारा जो तीसा में मुख्य स्वास्थ्य संस्थान था, आपने जो बैरागढ़, कोहाल की खाई या कॉलेज खाया या दूसरे संस्थान खाए तो कोई बात नहीं, हम उनके बिना गुजारा कर लेंगे। मगर हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं। आप बिजली बोर्ड के डिवीजन के लिए एस0ई0 या किसी को बोलो कि ट्रांसफॉर्मर दो। मगर उनका यह कहना है कि

के एस द्वारा जारी

11.03.2025/1640/केएस/एजी/1

श्री हंस राज जारी---

हम तो दोबारा वाइंडिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरह का झूठ न बुलवाएं। ये बहुत रिप्यूटिड व्यक्ति हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिए।

श्री हंस राज : उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त करता हूं लेकिन अभी तो मैं आपकी प्रशंसा करुंगा। आप तो जब इस सीट पर बैठते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं यह हंसते-हंसते इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने अंदर का गुबार नहीं निकाल पा रहा हूं परंतु मैं यह विश्वास रख रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कम से कम उस डिविज़न की बहाली कर देंगे और जो हमारा मसरून का कॉलेज उड़ाया है, वह जरूरी है। जहां जरूरी है, वहां संस्थान खोलने चाहिए। आप चुराह की नदौन से तुलना न करें। भाभी जी (श्रीमती कमलेश ठाकुर) से भी मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे ही प्रार्थना करुंगा कि आप ही मुख्य मंत्री जी को बोलो कि हमारा वह डिविज़न वापिस दे दो और एक कॉलेज दे दो। पी0एच0सी0 तो हम जब माननीय जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री बनेंगे, इनसे ले लेंगे। ...(व्यवधान) कर्नल धनीराम शांडिल जी तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, इनको तो बाबा साहब की उपाधि देनी

पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा हैं क्योंकि ये बाबा साहब की तरह भोले हैं। हमारे मित्रों की ट्रांसफर कर देते हैं और इनको भी पता नहीं लगने देते। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आपने खामखाह का झूठ पढ़वाया है, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

11.03.2025/1640/केएस/एजी/2

उपाध्यक्ष : अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ला, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

हिमाचल प्रदेश की सरकार जब सत्तासीन हुई तो आते ही 75 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का ऋण, 11 हजार करोड़ रुपये से ऊपर की देनदारियां हमें विरासत में मिलीं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने एक साल के अंदर जो यहां प्राकृतिक आपदा आई, अपने साधनों से उसका मुकाबला किया। 12 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार से कोई भरपाई नहीं हुई फिर भी प्रदेश सरकार ने उन लोगों की मदद की जिनके घर उजड़ गए थे। जिनकी मौतें हुई थीं और प्रत्येक घर बनाने के लिए 7-7 लाख रुपये का इंतज़ाम किया। जिनका थोड़ा नुकसान था,उन्हें भी एक-एक लाख रुपये दिए गए। सरकार ने जन-कल्याण की नीतियों को अपनाकर जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे आप सभी के सामने हैं। प्रदेश में जो सबसे बड़ी नशाखोरी थी, बढ़ती हुई चरस, बढ़ते हुए चिट्टे के ऊपर जो नकेल कसी है वह आप सभी के सामने हैं। कई नशा तस्करों को प्रदेश सरकार ने सलाखों के पीछे भेजा है और इस अभियान को आगे भी बढ़ाया जा रहा है जिसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश में नशाखोरों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत्त है। व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में सरकार ने प्रदेश में यहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गांव में जो किसान हैं, उनकी खेती में अनेक परिवर्तन करके प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत राज्य में 3,577 ग्राम पंचायतों में 2 लाख 87 हजार प्रशिक्षित किसानों को कवर किया है। रसायनों और उर्वरकों

के उपयोग के बिना प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई मक्का व गेहूं की जो कीमत है उसे 30 व 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सरकार खरीद रही है, यह योजना भी किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.03.2025/1645/av/एजी/1

श्री किशोरी लाल----क्रमागत

इसके अतिरिक्त हिम कृषि योजना के अंतर्गत 1200 क्लस्टरों की पहचान करके 155 क्लस्टरों में काम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती प्रणाली के तहत केसर व हींग की खेती को बढ़ावा दिया है। साथ ही सरकार ने प्रदेश में बागवानों के लिए एच0पी0-शिवा योजना के अंतर्गत जो क्लस्टर तैयार किए हैं उसके तहत बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में भी कई क्लस्टर लगाए गए हैं। एच0पी0-शिवा योजना के तहत कई किसानों के खेतों में तारबंदी करके फलदार पौधे जैसे अमरूद, लीची, संतरा इत्यादि लगाने हेतु सौ प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहां पर सिंचाई सुविधा भी दी जा रही है। जहां पर कूहलें नहीं हैं वहां पर उठाऊ सिंचाई योजना के माध्यम से उन क्लस्टरों की सिंचाई की जा रही है। सरकार द्वारा हिम गंगा योजना के तहत डगवार में एक बहुत बड़ा मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट लगाया जा रहा है और किसानों के दूध के मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। सरकार द्वारा गाय के दूध में 31.80 रुपये से 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध में 47 रुपये से 55 रुपये रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को लाभ होगा। युवाओं को स्वरोज़गार की तरफ बढ़ावा देने के लिए ट्राउट फार्म बनाने हेतु सहायता प्रदान की जा रही है और इसके लिए युवाओं को 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 6.36 लाख बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार प्रदान किया गया। मनरेगा के तहत मजदूरी को बढ़ाया गया और अब उनको तीन सौ रुपये दिहाड़ी दी जा रही है। गांवों में लोगों को रोज़गार मिले इसलिए

सरकार मनरेगा को कारगर बना रही है। मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 4242 बच्चों को फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत पात्र सभी बच्चों को सरकार द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ाया गया है। आई0टी0 शिक्षकों का मानदेय 1900 रुपये बढ़ाया गया है और अंशकालीन जल वाहक का मानदेय 600 रुपये बढ़ाया गया है। मिड डे कर्मचारियों का मानदेय 4500 रुपये किया गया है। सरकार द्वारा जल रक्षक का मानदेय बढ़ाकर 5300 रुपये किया गया है। पम्प ऑपरेटर और पैरा फीटर का मानदेय भी बढ़ाया गया है। मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों के चुने हुए लोगों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। सरकार द्वारा राजीव

11.03.2025/1645/av/एजी/2

गांधी स्टार्ट-अप योजना से ई-टैक्सी खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त ऑटो की खरीद पर भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा कौशल विकास योजना को लागू करके प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश के युवा रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी है अनमोल व मेरी लाडली कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं और इससे लिंग अनुपात में भी कमी आई है। सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 30929 पात्र महिलाओं को 1500 रुपये देने शुरू किए हैं जिस पर सरकार द्वारा 21.93 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। महिला श्रमिकों के कल्याण हेतु मुख्य मंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना, 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में पंजीकृत महिला श्रमिक जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, को आवास निर्माण हेतु 3 लाख रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2025/1650/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री किशोरी लाल ... जारी

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सिलाई अध्यापकों के मानदेय को 8500 से बढ़ाकर 9000 रुपये किया गया है। अशंकालिक पंचायत चौकीदार के मासिक पारिश्रमिक को 6700 रुपये से बढ़ाकर 7700 रुपये किया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2024 में बरसात में आई आपदा के पुनर्वास हेतु पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए सात लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये दिए गए हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति व ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन किया है। 23 जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा 152 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है जिसमें सौर ऊर्जा परियोजना पेखूबेला (32 मेगावाट) और भनजल सौर ऊर्जा (5 मेगावाट) शामिल है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए सरकार ने ग्रामों में होम स्टे के लिए नई नीति बनाई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन मजबूत होगा और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी होगी। हिमाचल प्रदेश से जी0एस0टी0 की कलैक्शन तो होती है लेकिन प्रदेश को जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में कोई पैसा नहीं मिलता है जोकि प्रदेश सरकार व जनता से अन्याय है। केन्द्र की सरकार द्वारा लगातार कटौतियां करके प्रदेश के आर्थिक राजस्व के घाटे को और बढ़ाया जा रहा है। इसलिए प्रदेश का आर्थिक घाटा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की कई स्कीमें बिना बजट के अभी भी रुकी हुई हैं। अगर केन्द्र सरकार प्रदेश को बजट मुहैया करती है तो उससे उन स्कीमों को सुचारू ढंग से चलाने में मदद मिलेगी। विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत बैजनाथ विधान सभा के बीड़ बिलिंग में इस बार पैराग्लाडिंग का आयोजन हुआ जोकि पिछले पांच सालों से नहीं हुआ था। इससे भी पर्यटन को फायदा हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों को हवाई परिवहन सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के साथ-साथ छह हेलीपोर्ट- रक्कड़, पालमपुर,

सुल्तानपुर, आलू ग्राउंड मनाली, जसकोट और शारबो (किन्नौर) तथा दूसरे चरण में 4 हेलीपोर्ट भी बनाए जाएंगे। यह हर्ष का विषय है कि राज्य में औद्योगिक

11.03.2025/1650/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत Best Performer in the State Startup Ranking 2023, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एस्पिरेर स्टेट इन 2024 और PMFME Scheme में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। यह सभी भली-भांति जानते हैं कि बिना केन्द्रीय सहायता से प्रदेश का विकास संभव नहीं है। यदि हमारे विपक्ष के साथी केन्द्र सरकार से प्रदेश को विशेष सहायता दिलाते हैं तो प्रदेश इससे प्रदेश तरक्की की ओर बढ़ेगा। मेरी पूर्व मुख्य मंत्री जी से भी गुजारिश है कि इस बारे में केन्द्र सरकार से पैरवी करें और प्रदेश सरकार को धनराशि दिलाएं ताकि प्रदेश तरक्की की ओर बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ ।

उपाध्यक्ष : धन्यवाद जी। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2025 को दिए गए अभिभाषण पर

एन0एस0 द्वारा .... जारी

11-03-2025/1655/ns-as /1

श्री जीत राम कटवाल----- जारी

मुझे आपने बोलने के लिए आमंत्रित किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहली बात इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में पहले ही कहना चाहता हूं कि मैं इसको स्पोर्ट नहीं करता क्योंकि यह अभिभाषण उपलब्धियों के बारे में कुछ नहीं कहता है। बाद में अगर इसके बारे में जो भी प्वाइंट या टिप्पणी होगी तो उसको भी स्पष्ट करेंगे।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

बजट की एक प्रक्रिया होती है और बजट सत्र के शुरुआत में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछले वर्ष का जो बजट होता है उसके साथ उपलब्धियां, माइलस्टोन्ज, सरकार के बड़े-बड़े प्रोग्राम्स और हमने जो आर्थिक व सामाजिक तौर पर हासिल किया हो, उसका विवरण होता है। बजट में आने वाले वर्ष के लिए कार्यों, प्रोग्राम्स और बजट की दिशा व दशा को इंगित करते हुए हम आम जनमानस की भावनाएं कह लें या अपने घोषणा पत्र के अनुसार, अपनी-अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के अनुसार प्रोग्राम लिखते हैं और उसके ऊपर कार्य करने का आश्वासन या प्रक्रिया के ऊपर चर्चा होती है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो यह अभिभाषण है तो इसमें एक भी पैरा में कोई उपलब्धि या टारगेट की अचीवमैंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है जोकि अपने आपमें इस अभिभाषण के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाता है। पिछले साल का जो बजट था और उसके बारे में सरकार के जो बड़े-बड़े दावे थे, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स थे तो पिछले वित्तीय वर्ष में उसके बारे में क्या हासिल किया और अगर कहीं कमी रह गई तो उसको सुधारने के लिए यहां पर चर्चा हो, पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्यगण इसमें सुधार व सुझाव और रचनात्मक टिप्पणियां करके उसको आगे बढ़ाने में मदद करें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक लगभग जो दफ्तर की प्रक्रिया ही है। जैसा दफ्तर में कहते हैं कि हमने यह किया है, यह दिया है और इससे इतने आदमियों को लाभ होगा और इतने आदमियों को बांट दिया तो यह मात्र उसका विवरण है। यह दस्तावेज एक छोटे-से निबंध के रूप में लिखी हुई इबारत है।

11-03-2025/1655/ns-as /2

यहां पर प्रोग्रैस कृषि की बात हो रही थी। मैं इस दस्तावेज को बड़े ध्यान से देख रहा था कि "प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना" के तहत 2 लाख 8 हजार क्रियाशील किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। उनको कुछ वित्तीय लाभ भी दिए गए होंगे, कोई प्रोत्साहन भी दिया होगा तो इसमें उसकी प्रोग्रैस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सरकार खुद अपने बजट और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखती है कि 57 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और फार्म सैक्टर पर आधारित काम करती है तथा उनका निर्वहन चाहे वे इंप्लॉयमैंट के तौर पर लें, चाहे अंडर इंप्लॉयमैंट के तौर पर लें या चाहे हम लोगों को एक व्यस्तता का जरिया रखें। सबसे बड़ा योगदान एग्रीकल्चर का इसलिए भी कहा जाता है कि कृषि या फार्म सैक्टर समाज को बांध कर रखता है। अगर एक व्यक्ति को खाली छोड़ दिया जाए तो कानून व्यवस्था की समस्या या किसी और अपराध की समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि बेकार आदमी कुछ-न-कुछ गलत व ठीक करेगा और उससे भी आदमी को दूर रखने का काम कृषि करती है। अगर 57 प्रतिशत जनसंख्या उस पर आधारित है तो उनकी कोई प्रोग्रैस भी हमें एक्सपैक्ट करनी चाहिए।

आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

11.03.2025/1700/RKS/डीसी-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

मान्यवर, अगर हम अपनी आबादी को लगभग 74 लाख मानते हैं तो उसमें लगभग 40 लाख लोग कृषि क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। कृषि क्षेत्र ने इन 40 लाख लोगों को बांध कर रखा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मुझे सदन की व्यवस्था देनी है, कृपया आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं। इस सदन का समय आज सायं 05:00 बजे तक निर्धारित किया गया था लेकिन

श्री जीत राम कटवाल जी के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तीन-तीन माननीय सदस्य अभी और बोलने वाले हैं। यदि ये सभी सदस्य 10-10 मिनट तक भी बोलते हैं तो मिनिमम एक घंटे का समय लग जाएगा। जैसा कि इस विषय पर पहले चर्चा हुई थी कि यदि शनिवार को सदन का अवकाश घोषित किया जाता है तो शनिवार को निर्धारित कार्य सूची पहले ही डिस्कस हो जाएगी और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर परसों चर्चा समाप्त हो जाएगी। इस परिस्थिति में हमारे पास प्रतिदिन 3 घंटे का समय है यानी हमें चर्चा करने के लिए 10-11 घंटे चाहिए। यदि हम अगले दो दिन सदन का समय दो-दो घंटे बढ़ाते हैं तो यह चर्चा संभव हो पाएगी। इसलिए मैं सदन की राय जानना चाहता हूं कि हम सदन का समय कितनी देर तक बढ़ाएं? आज की चर्चा तो एक घंटे में समाप्त हो जाएगी लेकिन अगर शनिवार वर्किंग डे नहीं होता तो हमें सदन का समय बढ़ाने के बारे में निर्णय लेना होगा। Now, I am extending the Hon'ble House for one hour and I request all the Hon'ble Members to be very brief. श्री जय राम ठाकुर जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में पहले भी बातचीत हुई थी लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने शासकीय कार्यवाही का उल्लेख किया तो उसमें शनिवार को वर्किंग डे दर्शाया गया है। मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्टता हो कि शनिवार वर्किंग डे है या नहीं। अगर शनिवार वर्किंग डे है तो चार दिन में तो सारी चर्चा हो जाएगी लेकिन यदि शनिवार वर्किंग डे नहीं है तो हमें सदन के समय को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इस विषय पर सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। हमने जो पहले चर्चा की थी उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं आया है जिससे यह भ्रम उत्पन्न हो गया है।

11.03.2025/1700/RKS/डीसी-2

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक प्रस्ताव भी आया है कि जो बजट सोमवार को 02:00 बजे प्रस्तुत किया जाना है उसे 11:00 बजे प्रस्तुत किया जाए। If Saturday is

not a working day then the House will reassemble on Monday at 11:00am. कृपया इस बारे में भी निर्णय लें।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा और हमारी सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी के नेता ने प्रस्ताव रखा था कि शुक्रवार को होली के कारण शनिवार को सदन में उपस्थित होना संभव नहीं होगा। It has been agreed. इस संबंध में मैंने आपसे आग्रह किया था कि कार्य सलाहकार समिति में इस पर निर्णय लिया जाए कि 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे then I will move a Resolution कि शनिवार सदन का अवकाश होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो बजट प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया है उसके बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चर्चा कर लूंगा लेकिन बहुत सारे विधायकों ने यह आग्रह किया है कि वे सोमवार को अपने गंतव्य स्थान से सुबह चलकर यहां 11.00, 12.00 या 02.00 बजे तक पहुंच जाते हैं। अगर यह संभव होगा तो हम देख लेंगे अन्यथा बजट प्रस्तुत करने का समय अपराह्न 02.00 बजे ही रहेगा।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक 1 घंटे 10 मिनट (06.10 बजे) तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी।

बी.एस.द्वारा... जारी

11.03.2025/1705/बी.एस./डी.सी./-1

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक फिलहाल 06.10 बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा आगे बढ़ाएंगे।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में यह पता लगाना जरूरी था कि इतनी इनपुट्स का हवाला सरकार दे रही है, क्या कोई प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है? और क्या आम जनमानस में भी इसका कोई फर्क पड़ा है? जो लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, उन लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर गारंटियों की बात हुई। दूध के मूल्य के बारे में बात हुई कि हमने भैंस का दूध 45

रुपये से बढ़ा कर 55 रुपये और गाय का दूध 31.80 पैसे से बढ़ा कर 45 रुपये कर दिया है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपनी गारंटी में तो कुछ और ही कहा था उसमें तो दूध का मूल्य 80-100 रुपये बताया गया है तथा दो रुपये गोबर की खरीद के लिए कहा गया है, यह भ्रमित करने वाला अभिभाषण है। इससे तो यही लगता है कि आप अपनी-अपनी जस्टिफिकेशन के लिहाज से इसे जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। मैं इसे सरकार के लिए उचित नहीं मानता हूं। इस बारे में सरकार वास्तव में कोई काम करती है या बताती है तो अच्छा होता।

बजट के बाद यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम की बात करें तो आपके पिछले वर्ष के अभिभाषण में 7,83,719 पेंशनें दी जा ही हैं और उसमें लिखा है कि 41,799 पेंशनें और जमा हो गई हैं। यह कुल मिलाकर 8,24, 619 पेंशनें बन जाती हैं। ये तो सारी जनरल पेंशनें हैं और आप उसे जो आपनी गारंटी मानते हैं उसके बारे में अपना रिकार्ड ठीक कीजिए। जनता के सामने तथा माननीय सदन के सामने ठीक तरीके से अपने तथ्य प्रस्तुत कीजिए। मैं यहां पर आपके पिछली साल के आंकड़े बोल रहा हूं। पिछली साल के अभिभाषण और बजट के अनुसार टोटल 8,24,929 पेंशनें लोगों को दी जा रही हैं। यह जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनें हैं उसके बारे में चिंतन कंसर्न था। माननीय विपक्ष के नेता ने आपको बताया कि काफी देर से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है और उस पेंशन के बारे में स्वतः ही लोग विधायकों को पूछते हैं। सरकार को इस संबंध में अपना रुख स्पष्ट और कार्रवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

सबसे बड़ी बात है कि पेंशन के लिए जो 15,00 रुपये के लिए फार्म भरे गए थे वे जून माह में भरे गए थे। जब आपके उपचुनाव और लोक सभा के चुनाव थे। वे पेंशन के

पेपर पंचायतों को दे दिए गए, यह घोषणा सरकार की थी और कांग्रेस पार्टी की थी और आपको उसके ऊपर बहुमत मिला था। पंचायतों में उसके ले जाने का क्या मतलब है? सूचना हेतु आपको भी मालूम है कि आपकी तरफ से यह डिले टैक्टिक्स रहा होगा। पंचायतों ने जनरल हाउस में फार्मों को वैसे-के-वैसे ही भेज दिया कि सभी लोग पेंशन के

लिए पात्र हैं। आपकी सरकार को अढ़ाई साल होने जा रहे हैं परंतु टोस करने या टरकाने के अलावा आपने उस घोषणा पर कोई काम नहीं किया है। इसका संदेश महिलाओं, समाज तथा जनता के बीच में ठीक नहीं जा रहा है। इसमें भी सरकार द्वारा कुछ काम नहीं किया गया।

विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का पैसा है, हमने नवम्बर माह से आथराइजेशन जारी की हुई है। आज दिन तक वे बिल पास नहीं हुए हैं। आज आम आदमी की भाषा में तो ट्रेजरी में ताला लगा हुआ है परंतु सुनते हैं कि वहां पर 10 हजार या छोटे बिल ही पास हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों की बात आती है कि उनका भुगतान नहीं हो रहा है। लोग हमें आ करके बोल रहे है। कांग्रेस की सरकार है तो आपके ठेकेदार ही ज्यादा सक्रिय होंगे वे भी कहते हैं कि पेमेंट नहीं हो रही है। मैं कहता हूं कि यह तो सरकार का काम है। वे बोलते है कि इस मुद्दे को विधान सभा में उठाइए। विधान सभा में उठाने की बात यह है कि सरकार को तो पहले ही पता होता है कि सरकार क्या कर रही है परंतु हम भी आपको बता रहे हैं कि आप इस पर भी अपना रुख स्पष्ट कीजिए। यह सदन है और इसमें आरपार की बात की बजाए आप अगर अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखेंगे तो हमें भी समझ आएगा और जनमानस को भी समझ आएगा।

इसके साथ ही प्रधान मंत्री आवास योजना में 92,364 घर मिले। पिछले सत्र का आपका जवाब मेरे पास है, 81,928 घर आए हैं और 10, हजार के करीब पिछली साल के होंगे। उन घरों की 1230 करोड़ रुपये की ग्रांट कह लो या केन्द्र सरकार से पैसा आया है उसका भी विविरण आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। जो केन्द्र सरकार से पैसा मिलता है, उसकी भी बात होनी चाहिए। अभी

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

11.03.2025/1710/डीटी/एच0के0/1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

मेरे सत्ता पक्ष के मित्रों ने कहा कि हमारा हिस्सा नहीं मिलता, मैं वह भी बताउंगा कि आपका हिस्सा केवल आपको मिलता ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और

उसकी जानकारी फैक्ट्स एंड फिगर्ज के साथ मैं देने वाला हूं। संस्थान बंद हुए, हमने ऐजिटेट किया, लेकिन आपने नहीं खोले, चलो ये सरकार के स्तर की बात है। परंतु एक बात याद रखिए कि लोगों को जो व्यवस्था या सुविधा एक बार मिल जाती है उसको बंद करना न ही तर्क संगत है और न ही न्याय संगत है। आप गुणात्मक शिक्षा की बात कर रहें हैं। अच्छी बात है, वह रिजल्ट से भी पता लगता है और पब्लिक सैक्टर में या प्राइवेट सैक्टर में सर्विसिज में कंट्रीब्यूशन से भी पता लग जाता है कि हिमाचल प्रदेश का शिक्षा का स्तर क्या है। अगर आप कह रहे हैं तो साल-छः महीने में पता भी चल जाएगा की शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है। आपने स्पोर्टस पर्सन के बारे में कहा कि हमने बाई-एयर उनको अलाउ कर दिया; रेलवे में ए.सी. टायर में अलाउ कर दिया; उनकी डाइट मनी बढ़ा दी; but what about the sport infrasturcutre? आप उन चीजों के बारे में बताइए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका रिकार्डिड समय 11 मिनट और 42 सैकंड हो चुका है।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझ छः मीनट और दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि स्पोर्टस पर्सन को इस प्रकार की सुविधा देने से स्पोर्टस मेन की स्किल अच्छी नहीं हो जाएगी। इसलिए स्पोर्टज इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्टस के बारे में हमारी कोई नीति होनी चाहिए। उनको अपग्रेड करने के कदम उठाने चाहिए, वह जरूरी हैं।

उसके बाद आपने 15वें वित्त आयोग की बात कही। मैं आपको कहता हूं कि प्रदेश सरकार को जो ग्रांट आई है वह वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 6778 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 9167 करोड़ रुपये आई और वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 10681 करोड़ रुपये की ग्रांट आई है और इस साल ये ग्रांट 11806 करोड़ रुपये आई और ये फार्मूला है .83

परसेंट का और अगर जी0एस0टी0 कलैक्शन भारत सरकार में बढ़ेगी तो आपको उसका .83 परसेंट मिलेगा और पिछले पांच सालों में लगभग 5222 करोड़ रुपये अभी तक बढ़ी है, तो आपका ये भी कहना तर्क संगत नहीं है कि भारत सरकार से आपका शेयर आपको नहीं मिल रहा है और प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है। आप गलत बात मत कहिए। सरकार के पास रिकार्ड होता है और सरकार को रिकार्ड देखकर ही बात कहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको यह भी बता दूं कि इन्फ्लेशन यू.पी.ए. की सरकार के दौरान 11.99 प्रतिशत थी और एक बार यह इन्फ्लेशन 10.02 प्रतिशत की भी थी। आज 4.5 प्रतिशत की इन्फ्लेशन है। यह इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी का इंडिकेटर है कि भारत वर्ष की इकोनॉमी किस ट्रेक में चल रही है, ये आप भी देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता। पी0डी0एन0ए0 का धर्मशाला में डिवेट हुआ था और वह क्लोज हो गया था। आपको सी.आर. एफ. में 293 करोड़ रुपये मिले; पी.एम.जी. एस वाई.. में 2643 करोड़ रुपये मिले, नेशनल हाइवे फोरलेनिंग के काम भारत सरकार डायरैक्ट करवाती है। 'हर घर में नल से जल योजना' का लाभ प्रदेश को मिला। गरीबों को घर और पांच किलों फ्री राशन केंद्र सरकार की ओर से दिया गया। उज्ज्वला गैस कनैक्शन दिए गए। लोगों के घर तक केंद्र सरकार का डायरैक्ट इंटरवेंशन है, उसको भी आप याद रखिए। केंद्र सरकार के ऐसे कार्यो से गरीब लोग केवल लाभान्वित ही नहीं बल्कि उनको गरीबी के स्तर से ऊपर आने में भी सहायता मिली है। भारतवर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। हिमाचल में भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसकी भी आपको तारीफ करनी चाहिए और इन चीजों का भी वर्णन आपको करना चाहिए। वाटर कनेक्शन के बारे में मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इसके बारे में जरूर सोचें। इस क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है, बरसातों में पानी नहीं आता, आजकल भी पानी नही आ रहा। जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिशाषी अभियन्ता हैं उनके पास कई जगह के चार्जिज हैं। उनसे बात करो तो कभी वह कहते हैं कि मैं घुमारवी में हूं और कभी कहीं और। आम जनमानस को पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए पानी की व्यवस्था को ठीक करवाइये। मुख्य मंत्री जी आप इस मामले में इंटरवीन कीजिए। मुझे

अधीक्षण अभियन्ता को, अधिशाषी अभियन्ता को दिन में तीन बार फोन करना पड़ता है। ये छोटी-छोटी बातें हैं।

श्री एन.जी. द्वारा जारी...

11.03.2025/1715/एच.के.-एन.जी./1

श्री जीत राम कटवाल.....जारी

ये छोटी-छोटी बाते हैं। जैसे पुलों की बात है।

Speaker : Conclude please.

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कईं पुलों को बने हुए ढ़ाई साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। दसलेड़ा-खमेड़ा में पुल बने हुए ढ़ाई साल हो गए हैं। बाड़ा-बेलवी में भी पुल बने हुए तीन साल हो गए हैं।

Speaker : Conclude please.

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, चोपाला-चंगर में पुल बने हुए ढ़ाई साल से अधिक हो गए हैं। उसमें तो अभी तक अप्रोच रोड भी नहीं बनाई गई है। इनके संदर्भ में मैंने विधान सभा प्रश्न भी लगाए हुए हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी, अब वाइंडअप कीजिए।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि मेरे प्रश्न पर भी गौर कीजिए। इस प्रकार की जो डेफिशिएंसिस हैं, उन्हें देखें बजाए इसके कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप अकेले सोचते रहिए परंतु आम जन मानस में इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। जनता बहुत डेफिशिएंसिस के साथ जी रही है। लोगों का आम

जनजीवन बिलकुल ठीक नहीं है। उन्हें पानी नहीं मिलता तथा बिजली के 20-20 कट लगते हैं, इन चीजों को देखिए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ट्रेजरी बहुत छोटी बात है।

Speaker : Shri Jeet Ram Katwalji conclude please.

11.03.2025/1715/एच.के.-एन.जी./2

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी तो एक शो-रूम है, काऊंटर है, आप आर्थिक स्थिति में देखें तो पिछले दो सालों में बिजली के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? प्रदेश में कोई प्रोजैक्ट नहीं लगा है। आपने इस अभिभाषण में 40 मेगावाट का विवरण दिया है। आपने पिछले बजट भाषण में लिखा था कि 500 मेगावाट सोलर पावर पैदा करेंगे परंतु केवल 67 मेगावाट सोलर पावर पैदा हुई है। इस प्रकार से आप वर्ष-2027 में कैसे आत्मनिर्भर हो जाएंगे? आपका कोई रूख नहीं लगता कि आप वर्ष-2027 में आत्मनिर्भर होंगे और वर्ष-2032 में सबसे समृद्ध प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार के कोई लक्षण नहीं है और न ही कोई रास्ता है। आपकी सरकार का इस ओर कोई कारगर कदम भी नहीं है। मैं ज्यादा न कहता हुआ सरकार को यही परामर्श दूंगा कि आप इसे गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का तथा सरकार के दस्तावेज़ का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2025/1715/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री नीरज नैय्यर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री भवानी सिंह पठानिया द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका

अनुसमर्थन माननीय सदस्य, श्री विनोद सुल्तानपुरी द्वारा किया गया है, मैं इसके पक्ष में अपने आप को शामिल करता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बैठ कर पक्ष व विपक्ष के सदस्यों की बातें काफी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं ज्यादा फिगर्स में नहीं जाना चाहूंगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक वैलफेयर स्टेट है। मैंने पाया है कि शुरू से ही हिमाचल प्रदेश के अपने आय के ज्यादा साधन नहीं रहे हैं। हमारे प्रदेश की संपदा 'वन' है। जिसे हम Himachal Pradesh Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1982 के तहत यूटिलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। वर्तमान सरकार से पूर्व की सरकारें, चाहे वे भाजपा की रही हों या कांग्रेस की सरकारें रही हों, उस दौरान हाइड्रो पावर में बहुत निवेश हुआ था। NHPC, SJVNL etc. corporations ने हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजैक्ट्स लगाए हैं। मैं एक बैठक में गया था तो मुझे पता चला कि एन0एच0पी0सी0 के हिमाचल वाले प्रोजैक्ट्स का टर्नओवर लगभग 60 हज़ार करोड़ रुपये है। मुझे लगता है कि SJVNL का तो इससे भी कहीं ज्यादा टर्नओवर होगा। मुख्य मंत्री जी जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। व्यवस्था परिवर्तन दो सालों में भी नहीं होता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की एक शुरूआत की है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को बने हुए दो साल का समय हो चुका है और दो वर्षों में लगभग 7-8 माह तो चुनावों में ही चले गए हैं। जिसमें लोक सभा का चुनाव भी शामिल है और प्रदेश में विधायकों की उठा-पटक के कारण भी हमारी सरकार का कुछ समय निकल गया।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

11.03.2025/1720/पीबी/वाईके-1

श्री नीरज नैय्यर...जारी

लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखें तो हमारी सरकार को कार्य करने का समय तकरीबन एक वर्ष 6 महीने का ही मिला है। जब हमारी सरकार बनी तो हमें 75 हजार

करोड़ रुपये का ऋण विरासत में मिला। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह ऋण आपकी सरकार द्वारा ही छोड़ा गया था लेकिन इस बीच पिछली कई सरकारों ने प्रदेश में कार्य किया। वास्तविक स्थिति यह है कि हमें यह ऋण विरासत में मिला है। जब आपकी सरकार के अंतिम 6 महीनों का कार्यकाल शेष था तो आपने न जाने कितने हजारों-करोड़ रुपये की घोषणाएं की थीं। आप उस समय रुलिंग में थे और आपको भलि-भांति पता था कि हमारी RDG निम्न स्तर पर आने वाली है और जी.एस.टी. की ग्रांट भी समाप्त होने वाली है। मुझे यह आभास होता है कि आपको शायद पहले ही पता था कि हमारी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं की गईं और इनका बोझ अगली सरकार पर पड़ गया। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपकी सरकार द्वारा की गई कुछ घोषणाओं को निरस्त किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी सारी घोषणाएं निरस्त कर दी गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी साहो का सब-डिवीजन बंद कर दिया गया। एक आई.पी.एच. का सब-डिवीजन भी बंद कर दिया गया था। जब सरकार ने पाया कि कुछ चीजों की जरूरत है तो सरकार ने मेरी एक सब-तहसील को दोबारा से खोल दिया। हमारे छोटे भाई डॉ0 हंस राज जी ने कहा कि मिनि सचिवालय का पैसा दे दिया गया है लेकिन मुझे यह बात क्लीयर नहीं है कि वह मिनि सचिवालय उनके विधान सभा क्षेत्र में स्थापित होना था या मेरे विधान सभा में। हमारा जिला एक एस्प्रेशनल जिला है और यहां कई वर्षों से एक मिनि सचिवालय खोलने की मांग थी जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 करोड़ रुपये की आंशिक राशि जारी की है और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए टैंडर अवार्ड हो गया है। इसका कार्य नाहन की किसी कंपनी को सौंपा गया है। मेरा मानना है कि खराब वित्तीय हालत में भी प्रदेश में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। यह बात अलग है कि हमारा मत अलग-अलग है। आपको लग रहा है कि काम नहीं हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि अच्छे काम हो रहे हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष का यह काम चलता रहता है। जब मैंने पहली बार अपना भाषण विधान सभा भवन, तपोवन में दिया तो उस समय श्री चन्द्र कुमार जी प्रोटम

11.03.2025/1720/पीबी/वाईके-2

स्पीकर थे। मैंने सोचा कि मैं पहली बार अच्छा भाषण देकर अपने लोगों को इम्प्रेस करूंगा। मैंने कहा कि चम्बा को अगर एस्प्रेशनल जिला की श्रेणी से बाहर निकालना है तो हमें चम्बा से चुवाड़ी तक एक टनल की जरूरत है। मैंने ऐसे ही वह बात रख दी थी लेकिन बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को गंभीरता से लिया और जब मुख्य मंत्री जी का चम्बा का दौरा था तो उस समय 4 करोड़ रुपये की राशि चम्बा-चुवाड़ी टनल निर्माण की डी.पी.आर. बनाने हेतु स्वीकृत करवाई। यह टनल बनेगी या नहीं यह अलग बात है लेकिन इस दिशा में हमारी सरकार ने एक कदम उठाया है। मेरा मानना है कि जब कोशिश सच्चाई और ईमानदारी से होती है तो वहां खुदा भी झुकता है।

श्री ए.पी.द्वारा... जारी

11.03/1725/A.P./Y.K./01

श्री नीरज नैय्यर द्वारा जारी.....

और इसी तर्ज पर मैं अपने भाजपा के साथियों को बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी आप 7 सदस्द जो 4 राज्य सभा व 3 राज्य सभा के जो एम0पी0 हैं, छोटे भाई हंस राज जी भी जो अभी उपस्थित नहीं हैं। हो सकता है कि जब इसकी डि0पी0आर तैयार हो जाएं to my knowledge अगर single tube tunnel बननी है तो exact amount तो हमें डि0पी0आर0 बनने के बाद पता लगेगा और अगर twin tube tunnel बनानी है तो लगभग 3600 करोड़ और अगर single tube tunnel बनानी है तो 1800 करोड़ that is an approximation that will go up and down मैं चाहूंगा की आप लोग हमारी सहायता करें और मैं आपको इस मंच से बोलता हूं कि अगर आप यह काम करवाएगे तो मैं आपका धन्यवाद दूगां। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी 6 हैलिपोर्टस में एक हैलिपोर्ट चंबा सुल्तानपुर में है और उसका पैसा सैक्शन हो गया है और टैण्डर जो है वह तीन-चार दिनों में फलोट होने वाला है। मैं मुख्यमंत्री जी का इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करना चाहूगां कि हमारे चंबा शहर की एक बड़ी विकट समस्या कई वर्षों से चली आ रही है कि चंबा शहर के अंदर कोई पार्किग नहीं है। कई विधायक आए और कई गए लेकिन पार्किंग की समस्या का कोई हल नहीं निकला और इस बार मुझे खुशी है कि ओर मैं मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री जी का

धन्यवाद करना चाहूगां कि जिनके प्रयासों की बदोलत इस बहुमंजिल पार्किग के लिए तकरिबन 5 करोड़ तक का प्रावधान कर दिया गया है और करीब 13 करोड़ की लागत से इस पार्किग का निर्माण होगा। इसका टैण्डर बस अड्डा मेनेजमेंट बोर्ड द्वारा लगाया जाएंगा। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करूगा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है इसलिए अतिशीघ्र इसका टैडर लगाया जाएं ताकि चंबा को इस पार्किंग की समस्या से छुटकार मिले साथ ही में आपको बोलना

11.03/1725/A.P./Y.K./02

चाहूंगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएं गये हैं। मैं अगर चंबा जिले की बात करू, माननीय शिक्षा मंत्री जी चंबा दौरे में आए। मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं वह खुद हैरान थें जब उन्होंने चंबा पी0जी0 कालेज में विद्यार्थियों की संख्या देखी लगभग 4000 बच्चे पी0जी0 कालेज में पढ़ते हैं और जब वह चंबा आए तो बच्चों ने यह प्रस्ताव रखा की एम0सी0ए0, एम0बी0ए0 की क्लास भी होनी चाहिए। मैं झुठ नहीं बोलूगां अध्यापक भी कम है लेकिन बुरा हाल नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी का एक ओर चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहूगां कि चंबा मैंडिकल कालेज की construction के लिए 185 करोड़ रूपय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिये और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि यह एक होस्पिटल है मैडिकल कालेज है यह एक पौधे की तरह है जिसे पनपने में समय तो लगेगा। लेकिन मैं इतनी चीज आपको गारेंटी के साथ बोल सकता हूं जो आपके समय में हाल चंबा मैडिकल कालेज थें उससे आज हालात बहुत बेहतर हैं। आपके समय के अंदर एक गायकनोजिस्ट चंबा मैडिकल कालेज के अंदर थीं, आज 6 हैं। रेडियोलोजिस्ट की आज हमें जरूरत है वह बात मैने ऐसे रख दी और खुशी इस बात की है माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस बात को सिरियसली लिया और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का चंबा दौरा था

ए0टी0 द्वारा जारी.....

11.03.2025/1730/ए0टी0/ए0जी0-1

श्री नीरज नैय्यर जारी….

तो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट एक है और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया है कि जो अभी रेडियोलॉजिस्ट ट्रेनिंग पर गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर कम से कम दो जो ट्रेनिंग पर गए हैं वह चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर आएं ताकि वहां जो लाइन लगती है क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट प्राइवेट लोगों को नहीं मिल रहे हैं और एम0आर0आई0 और सीटी स्कैन के लिए उसके अंदर कुछ फर्क पड़ सके। साथ ही में मैं मुख्य मंत्री जी का एक और चीज के लिए खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के तौर पर डवलप कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कांगड़ा तो है ही इसके अलावा चंबा टनल का हमने ख्वाब लिया है अगर यह टनल हम बना लेते हैं तो चंबा से जो धर्मशाला का फासला है वह मेरे आकलन से तकरीबन 2.30 घंटे रह जाएगा और यह एक मील का पत्थर पूरे जिला के लिए सावित होगा। अगर ये चीज होती है तो, एक बार फिर से आज यह प्रस्ताव अभिभाषण का यहां रखा है मैं अपने आप को इसके अंदर सम्मिलित करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री दीप राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री दीप राज : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय जव सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने अच्छे शासन और अच्छे प्रशासन की बात की थी और व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना दिखाया था। मैं आपको असलियत बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर तो आप बना रहे हैं लेकिन आप निर्भर किस तरह से बना रहे हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की वृद्धों की जब उनको पेंशन ही नहीं मिलेगी और बुढ़ापे में आज उनको जब घर-घर जाकर काम करना पड़ रहा है तो हिमाचल आत्मनिर्भर कैसे होगा? उसके बाद में बात करूं हमारे सड़कों की जब हमारी सड़कें ही ठीक नहीं हो रही है पिछले दो साल से तो लोगों को अपने पैसे लगाकर जब सड़के ठीक करनी पड़ रही है तब आत्मनिर्भर हिमाचल कैसे बन रहा है? मैं बात करूं शिक्षा की तो स्कूलों में टीचर ही नहीं हैं जब स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाना पड़ेगा तो फिर कैसे बनेगा आत्मनिर्भर हिमाचल? अगर हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो अधिकतर अस्पतालों में मेरे वहां तो डॉक्टर है ही नहीं है और अधिकतर टेस्ट अस्पतालों में होते ही नहीं है और लोगों को शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। जब उनको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहे हैं तो वह आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं? आपने पिछले बजट में कहा था कि 2032 तक हिमाचल आत्मनिर्भर बन जाएगा लेकिन थोड़ी देर पहले मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह प्रणाली अब 2027 तक पूरी हो जाएगी जो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे पता नहीं लगता कि उन्होंने कैसे ये कह दिया आपको मैं बताऊं कि पी0 एल0 एफ0 सी0 के अनुसार 2025 में जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अपॉइंटमेंट दर 10.4 प्रतिशत है जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जिसमें से की 24% महिलाओं का है जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है अब जब प्रदेश में रोजगार ही नहीं होगा और प्रदेश का युवा जब अपना काम खुद करेगा तो हिमाचल आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? उसके अलावा मैंने एक बात देखी जो स्टार्ट अप योजना है और इंसेंटिव पर बड़ी बात कही जाती है पहले तो

उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि जो आप यह ई-टैक्सी के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए जो पैसा देते हैं इसे स्टार्टअप नहीं कहा जाता है इसे

11.03.2025/1730/ए0टी0/ए0जी0-3

कहते हैं इंसेंटिव और जैसे ही सरकार बनी वैसे ही सुख Sukh Twingling Lab में एक नया स्टार्टअप incubate हुआ उसे स्टार्टअप का सपना था उसे स्टार्टअप में पहले सिर्फ और सिर्फ मित्र थे उसे स्टार्टअप का एक सपना था कि आगे चलकर हिमाचल प्रदेश को स्विट्जरलैंड की तर्क पर टूरिज्म में विख्यात किया जाएगा। क्योंकि हमारी और उनकी जो जनसंख्या है वह लगभग बराबर है लेकिन धीरे-धीरे इस स्टार्टअप के चलते हिमाचल प्रदेश पर कर्जा जो है एक लाख करोड़ से ऊपर हो गया है और धीरे-धीरे जब यह इनक्यूबेटर होगा। वर्ष 2027 की तरफ तो हिमाचल प्रदेश पर कर्ज 140000 करोड़ के लगभग हो जाएगा और पहले तो स्टार्ट टर्म में सिर्फ मित्र ही मित्र थे अब इस स्टार्टअप में फैमिली भी आ गई है तो स्टार्टअप को जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा।अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निजी तौर , व्यक्तिगत तौर पर मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले इनको इंटरव्यू में सुना एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से

श्रीमती एम0डी0द्वारा जारी.....

11-3-2025/1735/MD/HK-1

श्री दीप राज क्रमागत

आपने बात कही कि वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था। यहां सभी के हाथ में फोन है और इसको यदि आप अभी भी चैक करेंगे तो वर्ष 2022 में हम तीसरे स्थान पर थे। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2024 की एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार ही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में भारी मार्जनल डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर मैं 15 से 16 वर्ष के बच्चों की बात करूं तो तीन प्रतिशत डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर स्कूल ही नहीं होंगे या स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो

जिनके लिए आपने लोन की योजना बताई जैसे इस अभिभाषण में आपने कहा है कि बच्चों को 20 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। वे बच्चे ऋण लेकर क्या करेंगे जब आपके संस्थानों में अध्यापक ही नहीं होंगे? अगर आप सच में एजुकेशन के मसीहा है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि दो साल पहले की प्लानिंग की पहली मीटिंग में मैंने आपसे कहा था कि मेरी केंद्रीय विद्यालय की फाइल को आप दिल्ली भेज दें। आपने यह जवाब (हाथ में कॉपी दिखाते हुए कहा।) देकर आश्वस्त किया था कि डी0सी0 साहब के पास मेरी फाइल है उसको जल्दी से भेज दिया जाएगा। आज दो वर्ष हो गए हैं मगर आपने मेरी वह फाइल दिल्ली नहीं भेजी। इससे यह प्रतीत होता है कि आप केवल झूठ बोलकर सत्ता में रहना चाहते हैं। इससे आपकी नीयत और नियति में फर्क पता चलता है। आपकी नियति केवल झूठ बोलकर सत्ता में बने रहने की है और नियति यही बोल रही है कि भविष्य में आप देखने को भी नहीं मिलेंगे। अगर मैं फिज़िकल हैल्थ इंडैक्स-2025 की बात करूं तो नीति आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश हैल्थ में टॉप 10 में भी नहीं आ रहा। नैचुरल स्टेट ऑफ एडल्ट-हिमाचल जिसका सर्वे एच0 पी0 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने किया है, उसके मुताबिक हमारे 48 प्रतिशत बच्चे अंडर वेट पाए जा रहे हैं। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं कि उनको 1500-1500 रुपये दे रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रेग्नैंट विमन में 39 प्रतिशत इम्यून सिस्टम कमजोर होने के चांसिज आ गए हैं। हम बी0पी0, शुगर, पत्थरी जैसी बीमारियों तक का उपचार नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर अपने करसोग विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल अल्ट्रासाउंड की मशीन है मगर वहां पिछले दो वर्षों से डॉक्टर नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड का 1500

11-3-2025/1735/MD/HK-2

रुपये से लेकर 2000 रुपये चार्ज किया जाता है। एक गरीब आदमी के लिए 1500 रुपये या 2000 रुपये का मतलब चार दिन की दिहाड़ी होता है। अगर हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो लोगों का उपचार कैसे हो पाएगा। एमरजैंसी में एक्स-रे की मशीन नहीं है। अगर किसी की टांग टूट जाए तो उसको बाहर से एक्स-रे करवाने को कहा जाता

है। परंतु जितने में वह बाहर पहुंचेगा उतने में तो दूसरा फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए मैं इस संदर्भ में सरकार के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा :-

आपने जिनको ढोना है, आप ढोएंगे जरूर,
आप अपनी रूह की पहचान खोएंगे जरूर।
आपको है नींद न आने की बीमारी,
आपको अगर चौकीदारी पर बिठाएं तो आप सोएंग जरूर॥

मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की सड़कों की बात करूं तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है। आपने कहा कि आपने 4 हजार सड़कों के गड्ढे भरने का काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की भंतलपुरनी सड़क, लथैरी-भडारनू, चुराग से नागलाकोट, चुराग से ठांगर, कुफरीधार से सैंधल, कामाक्षा से चेहरा, चौरीधार से कटौल, नसवार से भानगाडीमन, कंडा से प्रांगण, बेलाधार से शालाना, बिंदला से तलेहन, सराहन से पलोह, तेबन से जेई और गवालपुर से स्कैलड सड़क बरसात के बाद अभी भी ठीक नहीं हो पाई हैं। यहां पर बस सुविधा नहीं है। पहली से पांचवी कक्षा के बच्चों को 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पहली बार करसोग के लिए सी.आर.एफ. के तहत पैसे स्वीकृत हुए हैं। आपने सब जगह के टेंडर लगाए लेकिन करसोग का टेंडर आपने नहीं लगाया है। उसमें आपने यह आपत्ति लगाई है कि पखरोह से लेकर सनारली जो करसोग की मेन सड़क है और इस सड़क का निर्माण वर्ष 1955 में हुआ है। आपने कहा कि इस सड़क का जिक्र लट्ठे में नहीं है। मैं इसका ऐविडेंस लेकर आया हूं। जब सड़कें ही नहीं होगी तो हमारा पर्यटन कैसे बढ़ेगा। सड़कें आधुनिक विकास को दिखाती है। जब यहां पर्यटक नहीं पहुंचेगे तो हमारी आय के साधन कैसे बढ़ेंगे? आप दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। माननीय मंत्री जी तातापानी आते रहते हैं। वहां घाट का कार्य बंद कर दिया गया है।

11-3-2025/1735/MD/HK-3

बरसात के कारण हमारी सभी पेयजल और सिंचाई योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पिछले दो वर्षों से वे कोई भी योजना ठीक नहीं हो पाई है। तेवण, महोग, कुठेड़, टेलरधार, सूरता

इत्यादि पंचायतों में आज भी महिलाओं को दो-तीन घंटे पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़ता है। यह सरकार की वर्तमान स्थिति है। ...(व्यवधान)

श्रीमती के.एस.द्वारा जारी

11.03.2025/1740/केएस/एएस/1

श्री दीप राज जारी---

मेरे घर में भी पानी नहीं आ रहा है लेकिन सर, बात मेरी नहीं है। जनता सरकार को चुनती है और सरकार का दायित्व होता है कि वह जनता की भावनाओं को देखकर उनका कल्याण करे। मैं करसोग विधान सभा क्षेत्र से आया हूं तो मैं केवल अपनी बात नहीं रख रहा हूं, मैं करसोग विधान सभा क्षेत्र के सभी लोगों की बात रख रहा हूं। हमारे करसोग में इकलौता आई0टी0आई0 का संस्थान है। उप- मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि उसके लिए थोड़े से पैसे दे दो। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग में दो साल से एक ईंट तक नहीं लग पाई है। और तो और हमारे बस स्टैंड में शौचालय ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वहां हमारी माताओं तथा बहनों को कितनी दुविधा का सामना करना पड़ता होगा। हॉस्पिटल में भी शौचालय नहीं है। यह है पिछले एक वर्ष का आपका व्यवस्था परिवर्तन। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में दो लाइनें बोलकर अपना भाषण समाप्त करुंगा किः

सुक्खू जी सत्ता में आए, मगर नीयत रही ढीली,
सुक्खू जी सत्ता में आए, मगर नीयत रही ढीली,
वादे थे ऊंचे और हकीकत हो रही ढीली।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण का कतई समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2025/1740/केएस/एएस/2

उपाध्यक्ष : इन्द्र सिंह गांधी जी, कृपया अगर आप फोन करना चाहते हैं तो हाउस से बाहर जा कर करिए। आपके फोन की आवाज यहां पर बार-बार आ रही है जिससे डिस्टरबेंस हो रही है।अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल महामहिम जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा और यहां पर सरकार की उपलब्धियां रखीं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने हुए 2 वर्ष 3 महीने का समय हुआ है और इस कार्यकाल में हमारी सरकार की उपलब्धियां बेहतरीन रही हैं। सबसे पहले जब सरकार बनी तो हमें प्रदेश के अंदर तीन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती प्राकृतिक थी। जब इस प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई और प्रदेश की जनता लाचार हुई, सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ उन हालातों को सम्भाला और प्राकृतिक आपदा से निपटने में हम कामयाब हुए। दूसरी आपदा आर्थिक संकट की आई और प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में जितनी चर्चा आज हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि जब हालात इतने खराब थे उस वक्त कुछ नहीं सोचा गया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक किया जाए? आज जो धन्यवाद प्रस्ताव भवानी सिंह पठानिया जी ने रखा, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कहीं और प्रदेश की सारी वित्तीय स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने लाया।

उपाध्यक्ष महोदय, आर0डी0जी0 की बात करें, वर्ष 2020-21 में सबको पता था कि 15वें वित्तायोग की जो सिफारिशें हैं, उसमें इसमें निरंतर गिरावट आनी है लेकिन उस वक्त कौन से उपाय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए, जरा सदन में बताया जाए? आज हमारी जो आर0डी0जी0 है, वह 3240 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है और यह स्थिति उस वक्त भी थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से जा रही थी। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जाते-जाते इन्होंने 900 ऐसे संस्थान खोल दिए जिनका बोझ हमारी सरकार के ऊपर पड़ा। जब पता था कि हमारी वित्तीय स्थिति कितनी खराब है तो फिर क्यों इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए और प्रदेश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

जब हमारे पास वर्ष 2020-21 में आर0डी0जी0 का बजट साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये था, अगर इतने अच्छे वित्तीय संसाधन हमारे पास थे तो

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.03.2025/1745/av/एएस/1

श्री सुरेश कुमार----क्रमागत

उनसे इन्होंने कर्मचारियों और पेंशन्र्ज के भुगतान क्यों नहीं किए, उस वक्त तो वित्तीय स्थिति ठीक थी। इनको उस वक्त सारे भुगतान करने चाहिए थे। ऐसा न करके पिछली सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन्र्ज के साथ धोखा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में सरकार को गिराने का कार्य किया गया और ख़रीद-फरोख्त से सरकार बनाने का प्रयास हुआ। लेकिन प्रदेश की जनता ने हमारा साथ दिया और हमारी संख्या दोबारा से 40 हुई जोकि इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश की जनता का भरोसा हमारे ऊपर है। प्रदेश की जनता इस सरकार को चाहती है। हमारी सरकार ने जैसे ही शपथ ली माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी अपने कार्यालय न जाकर उन अनाथ बच्चों के पास गए जिनके माता-पिता नहीं थे। सबसे पहले उनके पास जाने का उद्देश्य केवल प्रदेश में यह संदेश देने का था कि हमारी सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयास करेगी। यह सरकार गरीब, बेसहारा, कर्मचारियों और आम जनता की सरकार है, इसके पीछे माननीय मुख्य मंत्री जी की केवल यही मन्शा थी। आज जिन बातों के ऊपर चर्चा की जा रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन कार्य किए हैं। पिछले कल राज्यपाल महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसमें कोई भी असत्य बात नहीं कही गई। उनका पूरा-का-पूरा अभिभाषण सत्य पर आधारित था।

हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था कैसे सुधरे इसके लिए गरीबों, किसानों और आम आदमी की जेब में पैसा जाए, यह हमारी सरकार की सोच है। हमारी सरकार ने गांवों में अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए दूध के ऊपर सब्सिडी दी। आज नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि यह केवल यहीं तक सीमित है और गांवों में कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में उन लोगों की

तरफ जाइए जिनका गुजारा पशुओं के माध्यम से चलता है। गांवों के लोग आपको सच्चाई बताएंगे। हमारी सरकार ने प्राकृतिक खेती हेतु सब्सिडी देकर उससे होने वाली उपज के माध्यम से आम लोगों की जेबों में पैसा डालने का काम किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन केवल कुछ दिनों या रातों की बात नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए पहल करके उस संदर्भ में निरंतर

11.03.2025/1745/av/एएस/2

कार्य करने की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन को निरंतर आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय में आपको व्यवस्था परिवर्तन के नतीजे देखने को मिलेंगे। हमारी गारंटीज के ऊपर बहुत सारी चर्चा की जा रही है। हमारी सरकार ने 1500 रुपये की गारंटी दी और भारतीय जनता पार्टी ने तो दिल्ली में 2500 रुपये की गारंटी दे दी। आप लोग हमारी 1500 रुपये की बात पूछ रहे हैं लेकिन वहां दिल्ली में आप कुछ नहीं दे रहे। आप ज़रा अपने बारे में भी स्पष्ट कीजिए। आप वहां पर 2500 रुपये देने के लिए मुकर रहे हैं जबकि यहां तो 1500 रुपये की राशि दी जा रही है। ...(व्यवधान) लाहौल स्पिति में महिलाओं के खाते में 18000 रुपये एक मुश्त राशि डाली गई है और उसका नतीजा यह है कि माननीय सदस्या कुमारी अनुराधा राणा वहां से जीतकर आई है। हमने डोडरा-क्वार में पैसा दिया है और हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2025/1750/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
श्री सुरेश कुमार ... जारी

हमारी सरकार ने सबसे बड़ी गारंटी ओ0पी0एस0 के रूप में प्रदेश के कर्मचारियों को दी थी और हमारी सरकार ने इस गारंटी को पूरा करते हुए मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में 1.36

लाख कर्मचारियों को ओल्ड पैंशन से सम्मानित किया। लेकिन आपकी सरकार राजस्थान में बनी, वहां पर आपने ओ0पी0एस0 बंद कर दी। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी आपने वहां भी ओ0पी0एस0 बंद कर दी। आपकी मंशा ऐसी है कि यदि भविष्य में गलती से भी आपकी सरकार बन गई तो आप हिमाचल प्रदेश में भी ओ0पी0एस0 को बंद करने का इरादा रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कर्मचारियों का जो पैसा केन्द्र के पास है वह कर्मचारियों का है। लेकिन उस पैसे को देने के लिए वहां पर कर्मचारी नहीं गए थे। कर्मचारियों का वह पैसा सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास पड़ा हुआ है और उसमें भी 15 प्रतिशत शेयर हिमाचल प्रदेश सरकार का है तथा 10 प्रतिशत शेयर कर्मचारियों का है। वह भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है। वह कर्मचारियों का पैसा है और वह उनको मिलना चाहिए। आप गलत बयानबाजी और गलत आंकड़े पेश करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथी यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि प्रदेश को केन्द्र से ये-ये धनराशि मिली लेकिन केन्द्र से हमें कोई खैरात नहीं मिली है। केन्द्र ने प्रदेश को जो पैसा दिया है वह हमारा हिस्सा बनता है। केन्द्र सरकार पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाती है। केन्द्र सरकार के पास जो पैसा आता है वह जनता की जेब से जाता है। वह देश के सभी राज्यों से इकट्ठा होकर आता है और बाद में उसको शेयर के हिसाब से राज्यों में बांट दिया जाता है। यह संघीय ढांचे का नियम है और आप प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज केन्द्र सरकार से जो पैसा मिल रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि केन्द्र से प्रदेश को बहुत-सारा पैसा मिल रहा है। अगर केन्द्र सरकार की मंशा सही हो तो जो पी0डी0एन0ए0 का पैसा है उसे हिमाचल प्रदेश को दें। कर्मचारियों का जो 9200 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार के पास है उसको कर्मचारियों को दें। केन्द्र सरकार प्रदेश में आई

11.03.2025/1750/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

आपदा के लिए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज दें तो उसको कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार ने हमारे प्रदेश की मदद की है। जो पैसा हमें मिल रहा है, वह केन्द्र सरकार कोई खैरात

नहीं दे रही है। वह हमारा हिस्सा है क्योंकि हम संघीय ढांचे में रहते हैं। लोकतंत्र में इस संघीय ढांचे में सबका हिस्सा होता है और वह सबको मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य किया है और हिमाचल प्रदेश देश भर में पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाला पहला राज्य बना है। हमारी सरकार ने डे-बोर्डिंग स्कूल शुरू किए और क्लस्टर प्रणाली को अपनाया। पिछले कल राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि जो ए0एस0ई0आर0-2024 (Annual Status of Education Report) की रिपोर्ट आई है उसमें हिमाचल प्रदेश पहले दर्ज़े पर आया है। इसका सर्वे केन्द्र सरकार ने करवाया है और हिमाचल प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर आया है। कोविड महामारी के समय शिक्षा के क्षेत्र में जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई के लिए जो कार्य सभी राज्यों ने किए उसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर आया है। यह हमारी सरकार की वचनबद्धता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, इतना कहना चाहता हूं कि विपक्ष की जो चिंता है, वह इस बात के लिए नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो लोग यहां से छोड़कर गए थे, वे वहां जाकर ड्राइवर की कुर्सी पर बैठे हैं। यहां सदन में हमारे बहुत-सारे साथी बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि वे असली भाजपा में जाएं या भाजपा में रहे क्योंकि अब असली भाजपा भी बन गई है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

11-03-2025/1755/ns- dc/1

श्री सुरेश कुमार ---- जारी

इनकी चिंता यह है और ये इस चिंता से ग्रसित हैं तथा इस चिंता से ग्रसित हो करके इनको प्रदेश का विकास नहीं दिख रहा है, इनको प्रदेश की जनता नहीं दिख रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने भार से नीचे दब रही है। मुझे यही कहना था।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार जी भाग लेंगे

11-03-2025/1755/ns- dc/2

श्री लोकेन्दर कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पिछले कल माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा और उस पर माननीय भवानी सिंह पठानिया जी ने धन्यवाद प्रस्ताव लाया है तथा मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की। आज सभी लोगों ने इस चर्चा में तर्क के साथ बातें रखी हैं और बड़ी चिंता भी जाहिर की है। मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार जो कार्य कर रही है, अगर अच्छा किया है तो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने किया है और जो गलत हुआ है वह पिछली सारी सरकारों ने किया है। यहां पर राज्यपाल महोदय से झूठ बुलवाया गया। आज जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो वे तर्क के साथ बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास विषय का छात्र रहा हूं और मुझे इतिहास की जानकारी है। माननीय भवानी सिंह पठानिया ने जो यहां पर कहा है तो इन्होंने अच्छे आंकड़ों के साथ लाया है। परन्तु वे जिस तरीके के आंकड़े यहां पर दे रहे थे, मैं उस पर चिंता जाहिर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ओ0पी0एस0 क्यों छोड़ी थी और उस समय प्रदेश में किसकी सरकार थी? जब ये सारी बातें यहां पर हुईं तो फिर उन्हें मालूम पड़ा कि इतिहास में क्या हुआ था? यहां पर कहा जा रहा था कि मनरेगा की दिहाड़ी में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक वृद्धि की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने क्षेत्र के ब्लॉक में गया तो पता चला कि सरकार के पास 64 रुपये देने को नहीं हैं और सत्ता पक्ष के विधायक यहां पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। पिछले चार महीनों से दिहाड़ीदारों को 64 रुपये नहीं मिल रहे हैं। यहां पर सपने दिखाए जा रहे हैं, मीडिया को दिखा-दिखा कर बताया जा रहा है कि हमने व्यवस्था परिवर्तन कर लिया है। युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और यहां पर प्रोजैक्ट लगेंगे। इस तरीके से लोगों का

बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि इस सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय बिल्कुल साधारण परिवार से यहां पर पहुंचे हैं। जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास पूंजी है, वे लोग प्रदेश से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और वे दिल्ली व चंडीगढ़ में सैटल हो गए हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से शिक्षा के स्तर को लेकर के बात कही गई है तो उसके हमने आंकड़े लाए हैं। हमने आंकड़ों में बता दिया है कि हम किस में पहले नम्बर व किस में दूसरे नम्बर पर हैं? मुझे नित्थर से एक चिट्ठी आई है। यहां से श्री ईश्वर दास जी कांग्रेस पार्टी के सात बार विधायक चुने गए हैं और श्री किशोरी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के दो बार विधायक चुने गए। वहां पर साइंस विषय का कोई भी अध्यापक नहीं है। वहां पर 6-7 पंचायतें साथ लगती हैं और उन सारी पंचायतों के बच्चों को मजबूर होकर रामपुर पढ़ने जाना पड़ रहा है। हो सकता है कि कइयों के बागीचे हों, हो

11-03-2025/1755/ns- dc/3

सकता है कि कइयों के पास अच्छी पूंजी हो और वे शिमला में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मिडल क्लास लोग हैं वे कहां पर पढ़ने जाएंगे? मैं इस बात की चिंता जाहिर कर रहा हूं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में सिविल अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाया गया है। मैं आपको वहां के हालात बताता हूं। वहां पर पिछले एक वर्ष से एक्स-रे की मशीन खराब पड़ी हुई है। वहां पर प्राइवेट क्लीनिक को टेंडर दिया गया है और वहां एक्स-रे हो रहे हैं। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी अस्पताल और प्राइवेट क्लीनिक की है।

Rks द्वारा... जारी

11.03.2025/1800/RKS/एचके-1

श्री लोकेन्दर कुमार.... जारी

अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस स्थिति में लोगों को बहुत असुविधा होती है। पीछे करसोग से जो बस आ रही थी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को X-ray करवाने के लिए रामपुर लाना पड़ा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निरमंड

अस्पताल मात्र दो डॉक्टर्स के सहारे चल रहा है। अगर इसमें बी.एम.ओ. को जोड़ दिया जाए तो डॉक्टर्स की संख्या तीन हो जाती है। सरकार बार-बार यह अधिसूचना निकाल रही है कि अब रात को भी पोस्ट-मार्टम किए जाने हैं। स्टाफ के अभाव में अब इमरजेंसी केसों को देखा जाए या पोस्ट-मार्टम का कार्य किया जाए, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी यहां बैठे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र पास लगते क्षेत्र हैं। नगर पंचायत निरमंड को छोड़कर, मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने दूध के विषय में बात की। मैं इस पर भी कुछ कहना चाहूंगा। आपने कहा कि हम ने 45 रुपये की वृद्धि की है। आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 वैटरिनरी अस्पतालों को बंद करने का काम किया है। आज यह हालात है कि जब गाय नये दूध के लिए गर्म होती है तो वहां इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि जब गाय को समय पर इंजेक्शन नहीं मिलता तो वह गाय खराब हो जाती है और फिर लोग उन गायों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। अभी आउटर सराज से मिल्कफैड के चेयरमैन बनाए गए हैं।

हमारी सरकार और आपकी सरकार ने दूध के रेट बढ़ाए हैं। आप यह भी चिंता कीजिए की जो हमारी महिला किसान हैं वे सुबह 04.00 बजे उठकर गौशाला से काम की शुरुआत करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं और फिर शाम को गौशाला का काम करती है। लेकिन जब मैं वैटरिनरी होस्पिटल की बात कर रहा हूं तो आपने वहां पर कोई भर्तियां नहीं कि और उल्टा उन अस्पतालों को बंद करने का कार्य किया है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम किसी से सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है और मैं हर दिन इस चीज़ से गुजर रहा हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र को पीछे छोड़ा जा रहा है। इस दस्तावेज में समेज व बागीपुल की बात हुई। समेज में आपदा के कारण 36 लोगों की मृत्यु हुई। डी.सी. व एस.पी., शिमला को रेस्क्यू ऑप्रेशन के तहत वहां

11.03.2025/1800/RKS/एचके-2

तैनात किया गया। वहां ग्रीनगो कंपनी का प्रोजैक्ट स्थापित है। मेरा विधान सभा क्षेत्र का इलाका भी इसी में आता है। ग्रीन गो कंपनी द्वारा जो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे

उनको 2-2 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रतस्त घरों के लिए 1-1 लाख रुपये मुआवज़ा राशि दी। लेकिन इसमें भी क्षेत्रवाद किया गया। इसमें आनी क्षेत्र के लोगों को छोड़ा गया और शिमला के लोगों को पैसा बांटा गया। लेकिन मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हम समान रूप से सभी क्षेत्रों को देखते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो लोग आपदा में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके परिवार पहले ही काफी चिंतित हैं इसलिए जो उन्हें पूंजी मिल रही है उसे आप ईमानदारी से दें। इस दस्तावेज में 7-7 लाख रुपये देने का जिक्र किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि आपदा प्रभावित लोगों को 3 से 4 महीने का किराया भी अभी तक नहीं मिला है। जो पैसा मिलना था उसके नाम पर सिर्फ 65-65 हजार रुपये मिले हैं। आज 6-7 महीने गुजर गए हैं अभी तक वह पैसा नहीं मिल रहा है। लोग एस.डी.एम. व तहसील कार्यलय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। जब श्रीखंड के क्षेत्र में बादल फटा था तो उसका नुकसान बागीपुल में भी हुआ। वहां पर भी लोगों की मृत्यु हुई। वहां पर भी इसकी राहत में 8-10 परिवारों को केवल 65 हजार रुपये ही मिले हैं। मैंने सुबह उनसे पैसों की डिटेल मांगी थी। जिन लोगों के वाहन और दुकानें बह गई थी उन लोगों को अभी तक पूछा ही नहीं है। इसमें भी भेदभाव हुआ है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

11.03.2025/1805/बी.एस./एच.के./-1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी...

उसमें भी भेदभाव हुआ है और पिन प्वाइंट करके राहत दी गई है। मेरे पास लोगों के नाम हैं और मैं यहां पर नाम भी बता सकता हूं कि किस तरीके से पार्टीबाजी के नाम पर लोगों को कहा गया कि किसकी दुकान है, उसे ही पैसा मिलेगा और कौन बीजेपी का है उसे इतना पैसा मिलेगा। परंतु वहां भी लोगों ने पैसा नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव न करें। इस त्रासदी से सब लोगों को दिक्कत

हुई है और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। मुझे अपने क्षेत्र की पीड़ा है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सब लोगों को समान रूप से देखा जाए।

यहां पर खनन नीति की बात हुई कि खनन नीति लाई गई। जब धर्मशाला में सत्र था उस वक्त भी मैंने कहा था। खनन नीति में कहा गया कि अवैध खनन को रोका जा रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लुहरी, गोंथना और मोइन स्थान हैं जहां पर हमारा खनन का काम होता है। वहां पर जिन किसानों के खेतों में यह खनन का काम होता है और रेत को निकाला जा रहा है उन किसानों को उसका फायदा नहीं हो रहा है। जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं वे लोग क्या कर रहे हैं कि तीन महीनें की परमिशन के नाम पर पिछले दो-दो सालों से अवैध खनन का काम कर रहे हैं और अवैध खनन करके रेत को बेच रहे हैं। जिसका घाटा सरकार को भी हो रहा है क्योंकि जो राजस्व इकट्ठा होना था वह सरकार को नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यहां पर माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। मैंने दो-तीन बार अधिकारियों से भी बात की कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपये में जमीन को लीज पर ले करके रखा है उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से जमीन को लीज पर लिया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। खनन वाले लोग सरकार के करीबी होने के नाते इन पर कोई भी कार्रवाई नही हो रही है। लोग वहां पर कार्रवाई करने के लिए आते हैं दो-तीन दिन वहां पर अच्छे होटलों में रहते हैं और उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कृपया उन पर जोर से शिकंजा कसिए। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से अवैध खनन चल रहा है, कृपया उसके

ऊपर लगाम लगाई जाए। जिस तरीके से वे गुंडागर्दी करते हैं, उससे भविष्य में कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। समय रहते उसे रोक दिया जाए ताकि भविष्य में वहां पर काई ऐसी घटना या दुर्घटना न हो, यही मैं कहना चाहता हूं।

साथ-ही-साथ मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जो हमारा परिवहन विभाग है, मैंने दो-तीन बार उप-मुख्य मंत्री जी से बात करने की कोशिश की, शायद ये बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। एक बार तो वहां पर चलती बस के टायर ही खुल गए, एक बार लुहरी, जाजर होते हुए दलाश को सड़क जाती है, वहां पर बस का पट्टा टूट गया और बस गिरने से बच गई। हमारे पास कुल 30 बसें हैं और 101 रुट्स हैं। जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि 10 बसें और चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बसों की कंडीशन सही नहीं है तो कृपया उन्हें न चलांए। मुझे अपनी जनता की चिंता है ऐसी घटनाएं एक बार नहीं तीन-चार बार हो चुकी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बसों की कंडीशन खराब है तो उन्हें रोक दिया जाए, ताकि लोग सुरक्षित रहें। साथ-ही-साथ महोदय, मैं कॉलेज की बात करना चाहूंगा।

Speaker : Shri Lokenderji don't pay attention to them (Members of Ruling Party) pay attention to me. Please conclude your point.

श्री लोकेन्दर कुमार : हमारा कॉलेज आनी में है, कॉलेज में साइंस का विषय बंद होने की कगार पर है, क्यों? जैसे ही सरकार आई सरकार के आने के तुरंत बाद वहां से प्रोफैसर्ज को बदल दिया गया। सरकार आने से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 60 विद्यार्थी वहां पर साइंस के विषय में एनरोल थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि दूरदराज के क्षेत्र में कॉलेज खुला है और आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री राज वीरभद्र सिंह जी ने हमें वह कॉलेज दिया था इस कॉलेज को सही ढंग से चलाया जाए। वहां पर साइंस विषय के प्रोफैसर जल्दी भेजे जाएं। ताकि कॉलेज बेहतर तरीके से चल सके। वहां पर लाइब्रेरी के अंदर कोई भी स्टाफ नहीं है। ...(घंटी)... मैं साथ ही निर्मड कॉलेज की बात करना चाहता हूं। उस कॉलेज में 190 बच्चे हैं।

11.03.2025/1805/बी.एस./एच.के./-3

Speaker : Conclude please.

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे और समय दे दीजिए। वह कॉलेज प्राइमरी स्कूल में चल रहा है। वहां पर 34 बीघा जमीन कॉलेज के नाम पर हो गई है और उसका एफ0आर0ए0 भी हो गया है, अभी तक पांच करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया है परंतु जो एस.ई0 रामपुर बैठता है, उन्होंने अभी तक कोई टैंडर नहीं लगाया है और न ही कोई काम उस पर हुआ है। यदि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती है तो इस कॉलेज की बिल्डिंग का कार्य जल्दी शुरू करें।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

11.03.2025/1810/DT/YK-1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी.....

हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है उसे जल्दी बनाया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी आपने बजट के ऊपर भी तो बोलना है। Conclude please.

श्री लोकेन्दर कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यहां नशे के ऊपर बात कर रहे थे। राज्यपाल अभिभाषण के अन्दर कहा गया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी एक महीने पहले मुख्य मंत्री सिक्योरटी में वह मैडम है उनके बच्चे की चिट्टे की ओवरडोज से मौत हो गई और उससे पहले भी लगभग 3-4 बच्चे उस क्षेत्र में ओवरडोज के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। यह सब कुछ मालूम है कि कौन लोग वहां पर चिट्टा बेच रहा है। मैं इस माननीय सदन में खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि जब मेरी बात वहां के एस0पी0 या डी0एस0पी0 से होती है तो उन लोगों ने चिट्टे बेचने वाले लोगों को अरेस्ट किया और उन लोगों को दो दिनों के बाद छोड़ दिया गया। यह कैसा कानून है, हम इस विधान सभा सदन के अन्दर बैठ रहे हैं और हम लोगों ने ही कानून बनाना है। परंतु अगर हम यह नोक-झोंक करते रहेंगे कि आपकी सरकार में ज्यादा चिट्टा बिका तो हम सही मायने में जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम सही मायने में चिट्टे को नहीं रोकना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर में रहता हूं उस जगह पर आए दिन ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप समय को बढ़ा दें। ...(व्यवधान)

Speaker : Please conclude now. माननीय सदस्य समय ऐसे नहीं बढ़ जाता है। माननीय सदस्य आप 15 मिनट बोल बैठे हैं। ...(Interruption) Hon'ble Member Shri Lokender Kumarji, please take your seat. ऐसा है कि चिट्टे के ऊपर माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के अलावा सबसे पहले चिट्टे के ऊपर जिक्र किया कि 'मैं प्रसन्न हूं कि मेरे द्वारा चलाया हुआ अभियान जिसमें आप सब लोग, सरकार और प्रतिपक्ष भी शामिल हुआ और यह अभियान आज हिमाचल प्रदेश में जनता की आवाज बना है'। मैं प्रसन्न हूं कि चिट्टे के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। This is the comment for Hon'ble Governor. माननीय

11.03.2025/1810/DT/YK-2

सदस्य आपने 15 मिनट बोल दिया है और अभी कैबिनेट की मीटिंग है जो मुझे रिकवेस्ट आई है। माननीय सदस्य आप दो मिनट में अपनी बात रखिए।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता यह है कि जिस तरीके से नशा वहां पर फैल रहा है और साथ-ही-साथ इस अभिभाषण में लिखा गया है कि ईको-टूरिज्म के अंदर हम नीति ला रहे हैं। ईको-टूरिज्म की नीति ऐसे ला रहे हैं कि मेरे चुनाव क्षेत्र के जलोड़ी पास में तीन जगहों को लीज पर देने के लिए सरकार मुहिम चला रही है। जबकि जलोड़ी पास और रघुपुर गढ़ में लगभग 200-250 बच्चे अपना प्राईवेट रूप से काम कर रहे हैं और वह वन विभाग को भी उसकी फीस देते हैं। जब बड़े लोग यहां पर आ जाएंगे तो उन लोगों का जो काम चल रहा है वह ठप हो जाएगा और वह लोग नेचुरली चिट्टे और भांग की और चले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण सरकार के द्वारा माननीय राज्यपाल से बुलाया गया मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं और मैं इस के समर्थन में नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक पांच मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

उप-मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हमें बताया गया था कि हम इस सदन में आएंगे तो कानून बनाऐंगे। चिट्टे के परिपेक्ष्य में सदस्य ने बात की और मेरे माननीय विपक्ष के सदस्य भी जानते होंगे कि पांच ग्राम तक के चिट्टे में जमानत का प्रावधान है। इस सदन में बहुत बार इसका प्रस्ताव पास किया है लेकिन इसकी अप्रूवल केन्द्र सरकार से नहीं आ रही है। इसलिए जो पांच ग्राम से नीचे चिट्टे का व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसकी जमानत हो जाती है तो इस सदन का उससे कोई सरोकार नहीं है।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 11 मार्च, 2025 **सचिव।**